हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 1997

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय-सूची

मंगलवार 18 मार्च, 1997

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 1
नियम 45 के अधिन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(10) 18
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(10) 24
नियम 104 का निलम्बन तथा श्री भजनलाल एम० एल०ए० का सदन की सेवा से निलम्बन	(10) 30
वाक आउट	(10) 31
वर्ष 1996-97 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान	
(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभावित व्यय के अनुमानों पर चर्चा	(10) 32
(ii) अनूपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(10) 32
नियम 104 का निलम्बन तथा सर्वश्री धीरपाल सिंह, और रमेश कुमार एम०एल०ए० का सदन की सेवा से निलम्बन	(10) 35
वर्ष 1996-97 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(10) 37
वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(10) 39
बैठक का समय बढ़ाना	(10) 67
वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(10) 67
बैठक का समय बढ़ाना	(10) 77
वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(10) 77

मूल्य :

101 66

अध्यक्ष के हटाने के लिए संकल्प /1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा स्थगित करने के लिए प्रस्ताव (10) 85

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (10) 88

बैठक का समय बढाना (10) 89

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (10) 89

वाक आउट (10) 90

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (10) 90

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 18 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे ।

Shifting of Water Disposal System of Bahadurgarh City

***250. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for public Health l pleased to state whether there is any scheme under consideration of tl Government to shift the present water disposal system of Bahadurgarh city another place; if so, the time by which the scheme, as referred to above, likely to be implemented ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : जी हां। कार्य प्रगति पर है और स्थाई डिस्पोजल वर्क्स लिए भूमि अभिग्रहण का कार्य हाथ में लिया गया है। इस कार्य की मार्च 1998 तक पूर्ण होने संभावना है।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने बताया कि कार्य प्रगति पर है मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितना कार्य प्रगति पर है इस पर कितना पैसा खर्च होगा, कब कार्य शुरू हु और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, ऐसा है कि जो नये वाटर डिसपोजल वर्क्स हैं और जो पुराने वा डिसपोजल वर्क्स हैं उनकी दूरी दो किलोमीटर की है इस कार्य को पूरा करने के लिए 53,58,000 रुपया खर्च होगा और यह कार्य मार्च 1998 तक पूरा हो जायेगा ।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो दो किलोमीटर की द इन्होंने बताई है क्या उस जमीन को एक्वायर करने का काम शुरू हो गया है अगर शुरू हो गया है यह काम कब तक शुरू हो जायेगा । इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ रेल के पार का जो क्षेत्र है क्या उस क्षेत्र में भी सीवरेज लाईन डालने का कार्य करेंगे क्योंकि वहां की आबा भी लगभग 15 हजार के करीब है ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, जितने भी विकास के नये क्षेत्र हैं जैसे महावीर नगर, लालच कालोनी, छीकारा कालोनी, आनन्द नगर, शंकर नगर और रेलवे लाइन पार जो बस्ती है उसमें सीवरे डालने का कार्य शुरू करवायेंगें जिस पर 53,50,000/- रुपये का एस्टिमेट 1984 में बनाया गया और उस कार्य को मार्च 1998 तक पूरा कर दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, श्री भायना ने सांपला बारे एक प्रश्न पूछा था उनके क्षेत्र को भी बहादुरगढ के साथ ही सीवेरेज सिस्टम में शामिल किया जायेग

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने श्री नफेसिंह राठी जी के लिखित प्रश्न के उत्तर में बहादुरगढ़ के बारे में जवाब दिया है मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि बहादुरगढ़ के अलावा हरियाणा के जिन गांवों की जनसंख्या दस हजार से अधिक है क्या उनमें भी सीवरेज सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । ये एक योग्य मंत्री हैं और बहुत सीनीयर मंत्री है ।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, सीवरेज के साथ-साथ पानी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर सीवरेज लाईन है वहां पर प्रति व्यक्ति 100 से 110 लीटर पानी होना जरूरी है। इसलिए जहां पानी की कमी होगी पहले वहां पानी की पूर्ति की जायेगी। उसके बाद जिन गांवों की दस हजार कीआबादी है उन गावों को सीवरेज सिस्टम में लाने के बारे सोचा जा सकता है।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के राई के अन्दर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है जिसके कारण राई क्षेत्र में जितने ट्यूबवैल लगे हुये हैं वे ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं ।लोगों को पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। ट्यूबवैल वगैरह सब लगे हुए हैं लेकिन लोगों को समय पर पानी की सप्लाई नहीं मिलती है जिसके कारण लोगों को बहुत दुःख होता है ।

श्री जगन्नाथ : अगर पानी की सप्लाई में कोई गड़बड है, तो उसको ठीक करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि जहां पर आबादी 20 हजार है और ऐसी कंस्टीच्यूएंसी भी हैं जिनके अन्दर कोई शहर नहीं है। क्या आप ऐसे गांव जिनकी आबादी 20 हजार है, उनके लिए कोई सीवरेज का प्रबंध करने का विचार रखते हैं ?

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बहुत से गांव हो सकते हैं। आपका बौंद कलां भी हो सकता है, मोखरा हो सकता है । लेकिन इतना पैसा नहीं है कि हम सारे बड़े-बड़े गांवों और सारे शहरों में यह प्रबंध कर सकें। जितने 44 कस्बों और शहरों में सीवरेज का काम चल रहा है, उनके अन्दर भी यह काम पूरा नहीं हुआ है। किसी में 85 प्रतिशत, किसी में 75 प्रतिशत तथा किसी में 70 प्रतिशत कार्य ही हो पाया है। हां, आने वाले समय में बड़े-बड़े गांवों जिनकी आबादी 20 हजार की है, उनके लिए भी हम विचार कर लेगें लेकिन पहले तो 100 या 110 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन देने का विचार है।

Opening of Polytechnic Institute in Julana Constituency

***238. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister forTechnical Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to open a polytechnic Institute in Julana Constituency ?

आवास मंत्री (श्री नारायण सिंह) : नहीं श्रीमान जी ।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, जुलाना में बहुतकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने की बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जुलाना के अन्दर एक भिहाली होती थी और उस ने दूसरी कास्ट में शादी कर ली थी। वह बाहर से आई हुई थी। यहां पर श्री घासी राम जी एम०एल०ए० होते थे।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, जुलाना में इन चीजों की कमी है। पिछली सरकार ने तो वहां के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं अपनी सरकार से चाहता हूं कि इस बारे में कोई अच्छा जवाब दें ताकि मुझे भी संतुष्टि मिल सके और कोई उम्मीद भी हो सके।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जिससे ज्यादा कार्य हो सकें। इनके यहां तीन कालेज सरकारी हैं और 5 गैर-सरकारी कालेज हैं। इन कालेजों को सरकार ने पूरी सुविधाएं दी हुई हैं। इसके ज्यादा अगर ये कुछ और पूछना चाहते हैं तो अलग से नोटिस दे दें।

Upgradation of Govt. Middle School, Dadlana.

***232. Shri Krishan Lal** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Middle School, Dadlana, District Karnal; and

(b) if so, the time by which the said School is likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री, (श्री राम बिलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लगातार 5 साल से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ददलाना (करनाल) के स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में सदन में सवाल लग रहे हैं। वहां पर बिल्डिंग भी कंपलीट है और उसके 8-10 कि०मी० के एरिया में कोई हाई स्कूल भी नहीं है। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि क्या इस स्कूल को अपग्रेड करने पर विचार करेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल साथी श्री कृष्ण लाल जी ने जो सवाल पूछा है यह पहले भी इस सदन में आया है। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ददलाना के विद्यालय में 8 कमरे हैं और 3 एकड़ जमीन उनके पास है। वहां पर छात्रों की संख्या 647 है। ददलाना गांव की आबादी 7000 है। वह स्कूल अपग्रेडशन के वांछित मार्मज पूरे नहीं करता है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट इनके पास आई है कि यह विद्यालय अपग्रेडशन के लिए मार्मज पूरे नहीं करता है, वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 17 कमरे हैं। इसलिए इस विद्यालय का दुबारा सर्वे कराकर इसको अपग्रेड करवाने की कृपा करें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने माननीय सदस्य को उस राजकीय विद्यालय की सूचना दे दी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषणों में और सवालों के जवाबों में खुद माना है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर शिक्षा का एक नया ट्रैन्ड उभर कर सामने आया है। स्पीकर साहब, देहातों में पब्लिक स्कूलों के पैट्रन पर काफी संख्या में स्कूल खोले हुए हैं क्या मंत्री की नालेज में यह बात है कि वे प्राइवेट पब्लिक स्कूल किन हालात में हैं, किस वातावरण में हैं, उनकी बिल्डिंग कैसी

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

है, और वे फीस कितनी लेते हैं ? मैं कहता हूं कि वे बड़े अच्छे-अच्छे पब्लिक स्कूलों के बराबर फीस लेते हैं उनके पास साधन है नहीं। आज देहातों में भी लोग अपने अपने बच्चों को उन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में पढाने के बहुत इच्छुक हैं जिसके कारण गवर्नमैंट स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बहुत तेजी के साथ घटती जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी कोई कारपोरेशन का गठन कर सकती है जो उन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों को वांछित वातावरण के लिए जोकि अच्छे पब्लिक स्कूलों के लिए होना चाहिए उसमें वह सब साधन जुटा सके। और उन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के अध्यापक उस कारपोरेशन से लोन बगैरह ले करके अपने प्राइवेट स्कूलों को सही ढंग से चला सकें। वे अपने पब्लिक स्कूलों में अच्छे अध्यापक रख सकें और गांव के बच्चे भी एक अच्छे वातावरण में पढ़ सकें और उन पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे मैट्रोपोलिटीन सीटीज के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसी कारपोरेशन स्थापित करने का कोई विचार है।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि हमारे प्रदेश के गांवों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। प्रदेश के गांवों में लोगों ने अपनी सोसाईटीज बना करके कुछ संस्थाएं रजिस्टर करवा रखी हैं और उन्होंने उन शिक्षा संस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से चलाने का प्रयास किया है। यह बात भी ठीक है कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर लोग एक छोटी सी बिल्डिंग बना करके उसमें प्राइवेट पब्लिक स्कूल चला रहे हैं और वे मनमानी फीस भी लेते हैं उनके पास ट्रेन्ड टीचर भी नहीं होते हैं। हमें इस तरह की शिकायतें काफी मात्रा में मिली हैं। हम उनका सर्वेक्षण करवा रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक कारपोरेशन स्थापित करने के बारे में कहा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस समय सरकार का ऐसी कारपोरेशन स्थापित करने का कोई विचार नहीं है परन्तु एक बात पर हम बहुत गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में हर सब डिविजन लैवल पर उन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के मुकाबले में एक आदर्श विद्यालय राजकीय स्तर पर विकसित करें। पिछले दिनों इस बारे में कुरुक्षेत्र के अन्दर दिल्ली के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों ने अपनी तीन मीटिंग्ज भी की हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, या तो मैं इनको अपना सवाल समझा नहीं सका या ये समझ नहीं पाए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कारपोरेशन स्थापित करने का मतलब यह है कि जैसे इन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों को जिन जिन संसाधनों की जरूरत है वह सभी संसाधन वे बच्चों को मुहैया नहीं कर सकते इसलिए यदि ऐसी कोई कारपोरेशन स्थापित कर दी जाती है तो वे उससे लोन बगैरह ले सकेंगे और उनकी मदद हो जाएगी। जो आप सब डिविजन लैवल पर इस तरह के विद्यालय कायम करेंगे उससे तो आपके खजाने पर भार पड़ेगा।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग अपने आप में एक सक्षम विभाग है और हर टेलेंट का अध्यापक हमारे विभाग में है इसलिए हर सब डिविजन पर हम एक आदर्श विद्यालय कायम करना चाहते हैं।

Opening of Government Collage At Sampla

***263. Shri Balwant Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Government Collage at Sampla, and

(b) if so, the time by which the said Collage is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) इस समय कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने गवर्नर एड्रैस पर और बजट पर बोलते हुए भी कहा था कि सांपला में एक कालेज बनाया जाये। स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि रोहतक जिले के अन्दर सांपला कस्बे से चौधरी छोटू राम का गांव भी कोई एक किलोमीटर के फासले पर है। वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोहतक आना पड़ता है जिस के कारण बच्चों को काफी परेशानी होती है। हम सभी सर छोटू राम के नाम पर वोट मांगते हैं। वहां पर उनके उस कस्बे में चौधरी छोटू राम के नाम पर कोई शिक्षा संस्था न बनाई जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी सदन में इसी समय वहां पर इनके नाम पर महाविद्यालय बनाये जाने का एलान करें और इसे बनाये जाने का आश्वासन दें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले में इस समय 19 महाविद्यालय हैं ये हैं— Govt. College for Women, Rohtak, Govt.College, Bahadurgarh, Govt. College, Dubaldhan, Govt.College,Dujana, Govt. College, Jhajjar, Govt. College, Meham, All India Jat Heros Memorial College, Rohtak, G.B. Degree Colege, Rohtak, Sh. L.N.Hindu College, Rohtak, Vaish College, Rohtak, G.B. College of Education, Rohtak, Vaish College of Education, Rohtak, C.R. College of Education, Rohtak, S.J.K. College, Kalanaur, Vaish Arya KMV Bahadurgarh. M.A.College for Girls,Jhajjar, M.K.Jat College, Rohtak, D.A.V. Girls College, Kosli. फिर भी स्पीकर साहब, मायना साहब ने जो बात की है उस पर हर प्रकार से हमने बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया है और उस पर विचार किया है। इस बारे मैं बताना चाहता हूं कि राव बसीं सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय साथी इस सदन के रहे हैं, उनके प्रयत्नों से अटेली में हमने महा-विद्यालय बनाये जाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था, वह बना भी, क्योंकि लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे। लोगों ने खुले दिल से पैसे दिए थे। जब तक बच्चों की भी संख्यां पूरी न हो तो महाविद्यालय खोलने का फायदा नहीं। इसलिए मैं अपने माननीय साथी मायना साहब से निवेदन करता हूं कि वे इस महाविद्यालय के लिए भवन का निर्माण और ग्राउंड का निर्माण कर दें, हम महाविद्यालय वहां पर खोल देंगे।

श्री बलवंत सिंह : वह तो हम करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप करें।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : आप बिल्डिंग पूरी बनवा कर दे दें।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग तो इस काम के लिए पैसा इकट्ठा कर ही रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि वहां पर पीछे बाढ़ आने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वे तो अपनी तरफ से अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करेंगे ही लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने स्तर पर इसे बनवा दे बाकी की मदद वहां के इलाके की जनता करेगी।

श्री बंसी लाल : अब हम बाढ़ नहीं आने देंगे। एक साल में आप हमें बिल्डिंग तैयार करके दे दो।

श्री बलवंत सिंह : मुख्य मंत्री जी आप वहां पर महा-विद्यालय खोले जाने का आश्वासन तो दे दें ?

श्री राम बिलास शर्मा : जिस दिन आप भवन बनवा कर दे देंगे उसी दिन हम वहां पर महा-विालय खोल देंगे।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि शहरों से 30 किलोमीटर के फासले पर जिन कस्बों में महाविद्यालय नहीं हैं था उच्च शिक्षा संस्थाएं नहीं है वहां पर महाविद्यालय खोले जाने का क्या कराईटेरिया है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लाठर साहब ने जुलाना में महाविधालय खोले जाने के बारे में मुझे कई बार कहा है। इनको भी कहना चाहता हूं कि ये भी बलवंत सिंह मायना की तरह वहां पर बिल्डिंग बनवा कर तैयार करवा दें, हम वहां पर भी महाविधालय खोल देंगे। ये सारी शर्तों को जिस दिन पूरा कर देंगे उसी दिन से वहां पर महाविद्यालय चालू कर देंगे।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हाऊस में घुमा फिरा कर आश्वाशन देने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं बादली गए थे उस समय लोगों की भावनाओं को देखते हुए इन्होंने लोगों की इस बात को स्वीकार किया था कि सरकार बनने के बाद उसे बनाएंगे। (विघ्न)अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उनके उस भाषण का टेप है। बिल्डिंग के बारे में भी इनसे बात हुई थी। अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास 10 जमा 2 से ज्यादा बिल्डिंग है तकरीबन 30-35 बहुत बड़े कमरे बने हुए हैं जो कि 40X30 के हैं। 3-4 खेलने के मैदान भी वहां पर हैं चारदीवारी भी वहां पर बनी हुई है और हाल भी बना हुआ है, क्या सरकार उस कालेज को चालू करने बारे विचार करेगी ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने कही थी मैं उससे इन्कार नहीं करता और मैं उस पर अभी भी कायम हूं। हमारे शिक्षा मंत्री जी मौके पर जा कर देख लेंगे अगर सफिशियैंट बिल्डिंग वहां पर होगी तो उसे चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी, मेरे अपने पैतृक गांव में उस समय के मुख्य मंत्री जी वहां पर गये थे और हमारे लोगों को विश्वास दिलाया था कि वहां पर कालेज खोलेगें। 25 कमरे वहां पर बने हुए हैं बाकी का भवन भी पूरी तरह से तैयार है। हम पिछले दो साल से इस बात की बाट जोह रहे हैं कि कब वहां पर कालेज खुलेगा क्या वहां पर कालेज जल्दी ही खुलवाने बारे विचार करेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी इच्छा को हमारे लिए आदेश है। बीन्द में हम कालेज बनाने बारे जरूर विचार करेंगे।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की तरफ दिलाना चाहूंगा। वहां पर एक भी गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है। कैथल में एक जाट कॉलेज है। पिछली सरकार के राज में वहां पर एक डिग्री कॉलेज बनाने का आश्वासन दिया था। पूरी बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है, पूरा प्ले ग्राउंड भी है क्या सरकार वहां पर डिग्री कॉलेज बनवाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राम पाल माजरा जी ने जो सवाल किया है उस के बारे में मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हम जांच करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमैंट कॉलेज ही होने से शिक्षा का प्रचार या प्रसार होता है। स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के बारे में मांग हर चुनाव क्षेत्र से आ रही है और सवालों में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कम है। हमने इन बातों पर विचार किया और लगातार शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं रामपाल माजरा जी को बताना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालय हर जगह हो यह जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी शिक्षा संस्थाएं भी हैं जो शिक्षा के प्रचार और प्रसार में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हमने अभी एक इन्स्टीच्यूट में नई एम०ए० की कक्षाएं शुरू की हैं। इसके साथ जे०बी०टी० और ओ०टी० में 2 हजार छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सीटें थी इन की संख्या भी अब साढ़े तीन हज़ार तक बढ़ा दी है। अध्यक्ष महोदय, कैथल के साथ कोई भी ज्यादती की बात नहीं है। सरकार इस बात से पूरी तरह जागरूक है कि हरियाणा का कोई भी हिस्सा शिक्षा में पिछड़ा न रहे। इसके लिए चाहे कोई भी हल्का हो शिक्षा संस्थान या उच्च शिक्षा संस्थान से वंचित नहीं रहेगा। जहां कहीं कोई कमी है वहां पर शिक्षा संस्थान बनाने बारे जरूरत विचार करेंगे।

श्री बीजेन्द्र सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री तथा डिप्टी प्राईम मिनिस्टर हमारे हल्के इसराना में गए थे। वहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई में से कुछ राशि कालेज बनवाने के लिए एकत्रित की थी। उस राशि में से कुछ राशि तो नेता लोग ले गए लेकिन बाकी की राशि एक-दो आदमियों के नाम पर जमा है। वह पैसा अभी तक यूं ही पड़ा हुआ है। उस हल्के के लोग आज भी उन नेताओं को याद करते हैं। शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उस पैसे को उन लोगों से वापिस लिया जाए और साथ वहां पर कालेज खोलने के बारे में भी विचार करें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसराना की जो शिकायत आई है कि कुछ लोग धन इकट्ठा करते हैं और जिस काम के लिए वह धन इकट्ठा किया जाता है उस पर खर्च नहीं किया जाता है। इस को देख लेंगे आज शिक्षा की तरफ जो लोगों की रुचि बढ़ी है वह हरियाणा में शराब बंदी के कारण ही बढ़ी है क्योंकि अब वे उससे फ्री होकर इस तरफ आ गए हैं।

Laying of Foundation stone of Electricity Stations

***273. Shri Anil Vij** :Will the Chief Minister be pleased to state ----

(a) the total number of foundation stones laid during the last five years for the construction of electricity stations/sub-stations in the State;

(b) the number of electricity stations/sub-stations out of those as referred to in part (a) above that have been constructed/are still under construction; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 66KV Sub-station near Industrial Area, Ambala Cantt.; if so, the time by which it is likely to be set up ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The details of foundation stones laid in the last five years have to be collected from field offices located all over the State. Getting details for last 5 years is a voluminous exercise and the work involved may not be commensurate with the results sought to be achieved.

(b) Details of new power sub-stations commissioned during last 5 years (April,1991 to March,1996) is as follows:—

220KV	4
132KV	13
66KV	10
33KV	35

Work on following sub-stations is presently in progress:—

220KV	7
132KV	12
66KV	9
33KV	23

(c) Yes, Sir. The sub-station is likely to be completed by the year 1998-99.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सवाल के पार्ट "सी" के उत्तर में कहा है कि अम्बाला कैंट का सब-स्टेशन 1998-99 में पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी तरह से चुस्त दुरूस्त बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए ये क्या करेंगे ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रैंथन करने के लिए हमें पांच सौ करोड़ रुपये की अगले पांच सालों में जरूरत है। इसके साथ ही मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में पत्थर इतने रखे गये जिनका हिसाब रखना या लगाया जाना बहुत मुश्किल है। यह जो अम्बाला सब स्टेशन है इस बारे में हमने 1998-99 में बनाने की बात की है। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि इसको हम करंट ईयर में ही चालू कर देंगे।

श्री सूरज मल: अध्यक्ष महोदय, मुरथल गांव के नाम से सब डिविजन सोनीपत में खुला हुआ है। यह आफिस पहले मूरथल में होता था और इसका स्टाफ वहीं पर बैठता था लेकिन अब वह स्टाफ सोनीपत में बैठता है। लोगों को कोई प्रोब्लम हो तो उनको सोनीपत जाना पड़ता है जिससे वहां के लोगों को बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वह स्टाफ गांवों में भी नहीं आता है। क्या मुख्यमंत्री जी उस स्टाफ को मूरथल में बिठाने का कोई प्रबन्ध करेंगे ताकि लोगों को परेशानी से मुक्ति मिले ?

श्री बंसी लाल : आपकी बात जायज है और हम उस स्टाफ को वहीं पर बिठाएंगे।

Number of Persons Getting Old Age Pension

***323 Shri Dhir Pal Singh** : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the number of male and female persons getting Old Age Pension as on Ist January 1990, 1996 and 1997 ?

स्थानीय शासन मंत्री (डा० कमला वर्मा) : सूचना अनुलग्नक 'क' पर रखी है।

अनुलग्नक - 'क'

वृद्धावस्था पैंशन स्कीम में 1 जनवरी 1990,1996 तथा 1997 में लाभपात्रों की संख्या की सूचि :-

वृद्धावस्था पैंशन योजना के अन्तर्गत नीचे दर्शायी सूचि में लाभपात्रों की संख्या	पुरूष	महिलाएं	कुल
1-1-1990	3,80,161	3,57,105	7,57,266
1-1-1996	3,89,938	3,57,460	7,46,398
1-1-1997	3,69,060	3,34,289	7,03,349

10-00 बजे **श्री धीरपाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में दर्शाया है कि 1-1-90 तक 7,37,266 वृद्धों को पेंशन दी गयी और 6 साल बाद यानी 1996 तक 7,46,398 लोगों को पेंशन दी गयी यानी अंतर 9132 का है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि जैसा 1991 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया था कि 65 साल तक जो वृद्धावस्था पेन्शन की सीमा है उसको घटाकर साठ साल कर दिया जाएगा तो पांच साल की आयु घटने के बाद और 6 साल निकलने के बाद भी जो इतनी कम संख्या बढ़ी है इसका क्या कारण है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब वृद्धावस्था पेन्शन की उम्र साठ साल हो गयी,उसके बाद एक सर्वेक्षण करवाया गया। उसमें यह पाया गया कि बहुत से लोगों ने गलत पेंशन लिखवा ली थी। सर्वे के दौरान डाक्टर भी साथ गया था। उनके राशन कार्ड भी देखे गए थे। उसके बाद कुछ लोगों के नाम कट गए और कुछ की मृत्यु भी हो ही जाती है क्योंकि वे वृद्ध तो होते ही हैं। यह संख्या इसलिए ही घटी है। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं की गयी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जब यह पेंशन बनाई जाती है तो इसके लिए एक बोर्ड बैठता है जिसमें डाक्टर,अधिकारी एंव चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। पूरी तरह से तय करने के बाद ही पेंशन बनाई जाती है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या किसी की बनी हुई पेंशन को सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट का एक क्लर्क यह कहकर पेंशन काट सकता है कि अभी तेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं या अभी तेरे दांत नहीं टूटे हैं ? अम्बाला छावनी में इस प्रकार का एक इंस्टान्स हुआ है। पिछले दिनों नगरपालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट का एक क्लर्क

[श्री अनिल विज]

जब अम्बाला छावनी में पेंशन बांटने के लिए गया तो उसने कई लोगों की पेंशन उपर्युक्त कहीं हुई बातों को कहकर काट दी । क्या एक क्लर्क बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी पेंशन को काट सकता है।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह ऐसा नहीं कर सकता और उसको इस तरह से पेंशन काटने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन के बारे में जितने भी विवादास्पद केसिज होते हैं उनके लिए एक समिति बनायी गयी है जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी,मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डी०सी० होते हैं। जिन जिन लोगों की पेंशन काटी गयी है, उनकी आप ऐलीकेशंज लेकर हमें दे दें, हम दोबारा से इसका निरीक्षण करवा लेंगे।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्री साहिबा बहुत ही सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, उनके पास नीचे से जानकारी आयी होगी उसी के आधार पर इन्होंने बताया है कि 1-1-96 के बाद 1-1-97 तक 7,03,349 लोगों को पेंशन दी गयी। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि एक साल के बाद यह संख्या कम होकर 33937 क्यों हो गयी। यह संख्या वर्तमान सरकार के आने के बाद ही कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है और संख्या बार बार डाउन क्यों जा रही है ? बहन जी ने यह पहले कहा था कि हमारे समय में इस बारे में अनियमितताएं हुई थी और पिछली सरकार के समय में भी अनियमितताएं हो गयी थी। लेकिन फिर भी यह संख्या क्यों कम हो गयी है और इसके क्या कारण रहे हैं ? क्या बुजुर्गों की संख्या कम हो गयी या फिर अन्य कोई कारण है ? इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन दस महीनों के दौरान इस बारे में कोई नया सर्वे क्यों नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है ? यह संख्या घट रही है फिर ये दोबारा सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं, इस बारे में बता दें।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 1-1-97 की बात कर रहे हैं तब हमारी सरकार नहीं थी। मार्च-अप्रैल का बैकलॉग जो है वह भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमने पिछली सरकार की बची हुई पेंशन वितरित की है। हर दो साल के बाद सर्वेक्षण होता है वह दो साल का समय अब आ गया है और अब नये सिरे से सर्वेक्षण करवा रहे है जो भी लाभ पात्र होगा उसको पेंशन मिलेगी।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने कहा है कि 1-1-97 को हमारी सरकार नहीं थी जबकि इनकी सरकार ही थी ये इसमें सुधार कर लें।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1-1-97 को हमारी सरकार थी लेकिन सर्वे करने का जो नियम है वह दो साल के बाद होता है वह अब होना है और उसे हम करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जहां तक विधवा पेंशन की बात है पिछले 5 वर्षों में भी हमने इस बात को काफी उठाया है कि कोई भी भारतीय नारी कभी यह झूठ नहीं कह सकती कि वह विधवा है इसलिए उसको पेंशन दी जाए। जो भी विधवा दुर्भाग्य से हो जाए तो उसको पेंशन शीघ्रातिशीघ्र मिले। ऐसा कोई प्रावधान आप करें।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सारे माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि जब से हमारी सरकार आई है विधवा की पेंशन हर महीने जिस वक्त वह प्रार्थना पत्र देती है हम उसी महीने से लागू कर देते हैं हम कोई इंतजार नहीं करते।

श्री रामफल कुण्डु : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कह दिया कि जब भी फार्म भरे, पेंशन बना दी जाती

है। मैं कहना चाहूंगा कि फार्म तो भर लिए जाते हैं लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद भी पेंशन नहीं बनाई जाती है इसका क्या कारण है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वे इस बारे में ऐसा कोई इंसटांस मेरे नोटिस में लाएं उस अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा जिसने ऐसा किया है। और उसकी पेंशन लगा दी जाएगी।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हर महीने की 7 तारीख से पहले पेंशन घर में दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

डा० कमला वर्मा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि जब से हमारी सरकार आई है तब से हर महीने की 7 तारीख को घर में पेंशन दी जाती है।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों बुढ़ापा पेंशन के फार्म दे दिए गए लेकिन पेंशन नहीं बनाई गई इसका क्या कारण है ?

डा० कमला वर्मा : ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा कोई केस मेरे नोटिस में नहीं आया। हम सर्वे करवा रहे हैं और अपैल तक हमारा सर्वे पूरा हो जाएगा ?

Laying of Sewerage System at Radour

***292 Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay the sewerage system in Radour City ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : जी, हां।

श्री बन्ता राम बालमिकि : अध्यक्ष महोदय, किन शब्दों में मैं मंत्री जी की तारीफ करूं कि इन्होंने "नो" को "यस" में बदल दिया है। मैं आपके माध्यम से अपने बड़े भाई मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह आप कब चालू कर रहे हैं और कब तक पूरा करेंगे।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने रादौर कस्बे का प्रश्न पूछा है। वहां यमुना ऐक्शन प्लान के अंदर यह काम होगा। मई जून तक जमीन अधिग्रहण हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। अगले डेढ़ साल में इसका काम पूरा हो जाएगा। मैं हाउस की नालेज के लिए बता दूं कि यमुना ऐक्शन प्लान का काम जगाधरी,करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद इन छह बड़े शहरों में सितंबर में शुरू हुआ था और मई के लास्ट तक इनमें काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सैटेलाइट टाउन छछरौली, रादौर,इन्द्री,घरौंडा, गोहाना और पलवल में काम शुरू हो जाएगा और एक-डेढ़ साल में काम खत्म हो जाएगा।

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन-जिन कस्बों में पानी की व्यवस्था की गई है उन कस्बों में जो मेन लाईन है उस लाईन से घरों की लाईन जोड़ने की कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है क्योंकि मेरे क्षेत्र में गांव के प्रति हाऊस के हिसाब से 300-300 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करा लिये गये हैं लेकिन अधिकारी उस मेन लाईन से घरों में पानी के कनैक्शन की लाईन जोड़ने में असमर्थ हैं।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, जिन गांवों में प्रति व्यक्ति 70 लीटर के हिसाब से पानी है वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि घरों में भी पानी के कनैक्शन दिये जाये लेकिन जहां पानी कम है वहां पर घरों में पानी के कनैक्शन देने में यह सरकार असमर्थ है।

श्री रामजीलाल : स्पीकर साहब, जहां पर लाईन बिछा दी गई हैं और 300 रुपये सिक्योरिटी के जमा करा लिये गये हैं उनके बारे में अधिकारी कहते कि हमारे पास सामान नहीं है वहां पर क्या घरों में पानी के कनैक्शन दिये जायेंगे।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नारनौल जोकि एक जिला हैडक्वाटर है क्या वहां पर सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था यह सरकार कर रही है ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, इसके बारे में अगर अलग से प्रश्न दे दें तो अच्छा होगा क्योंकि उसमें डिटेल में जवाब दे दिया जायेगा।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आश्वाशन दिया था कि गोहाना में सीवरेज लाईन बिछाई जायेगी इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस सीवरेज लाईन को बिछाने में कितना समय लगेगा और कितना पैसा खर्च होगा ? क्या वह सीवरेज लाईन गोहाना के मेन बाजार के अन्दर बिछाई जायेगी या जो बाहर का एरिया है उसको ही इस स्कीम के अन्तर्गत लिया जायेगा।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, इसमें 3 करोड़ 48 लाख रुपया खर्च होगा। सीवरेज लाईन बिछाने का काम गोहाना शहर के बीच के एरिया से शुरू करके आगे तक ले जायेंगे। जो छोटे-छोटे नाले या नालियां है उनको बाद में इस मेन लाईन में जोड़ दिया जायेगा।

श्री जयसिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यमुना एक्शन प्लान के तहत कौन-कौन से शहर शामिल किये गये है और उसका क्या क्राईटेरिया है ? जो बाकी के शहर रह गये हैं क्या उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, 6 बड़े शहरों को इसमें शामिल किया गया है, यमुना-जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इन शहरों का गन्दा पानी यमुना नहर मे पड़ता था इसलिए उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोट ने यह हिदायत दी कि इस पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायें। इन छः बड़े शहरों के साथ छः छोटे शहरों-छछरौली, रादौर, इन्द्री, घरौंडा, गोहाना और पलवल को शामिल किया गया है। इन छः बड़े शहरों पर तो 21 करोड़ रुपया खर्च होगा और जो बाकी के छः छोटे शहर हैं उन पर 211 करोड़ रुपया खर्च होगा। कुल मिलाकर 232 करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय,मेरे हल्के का होडल एक सुन्दर शहर है।पिछली सरकार के काफी मंत्री वहां पर गये, उन्होंने आश्वासन दिया था कि होडल के खारे पानी को मीठे पानी में बदलेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय मेरे हल्के के शहर होडल के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, होडल शहर में मीठा पानी जरूर देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चरखी दादरी में दो कालोनियां हैं। वहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं है। वहां पर गंदा पानी पीने के पानी में मिक्स अप हो

जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समस्या का हल जल्दी करने की कोशिश करें क्योंकि वहां पर बीमारी वगैरह फैलने का अंदेशा है।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहब, अगर कोई ऐसी बात है तो हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन ये माननीय साथी सारा दिन हमारे साथ रहते हैं, इन्होंने अगर पहले हमें यह बात बताई होती तो हम इसका समाधान पहले ही कर देते।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो कैनाल बेस्ड वाटर वर्कर्स स्कीम हैं, जैसे जे०एल०एन० नहर का पानी शहरों में जाता है तो वहां पर उस पानी में सीवरेज का पानी मिल जाता है। ऐसा रिवाड़ी में भी हो रहा है। क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री जगननाथ : स्पीकर साहब, इस सवाल के लिए ये अलग से नोटिस दे दें। मैं इसका जवाब दे दूंगा।

Digging of Drain from Bohar to Baliyana

***336 Shri Sri Krishan Hooda** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to dig out a drain from Bohar to Baliyana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal) :

(a) Yes, Sir.

(b) The work is likely to be completed before on-set of next rainy season.

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर हां में दिया। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कलोई, मंडाल में हजारों एकड़ जमीन में खुदाई नहीं हुई है। क्या वहां पर भी कोई ड्रेन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बंसी लाल : इसके लिए ये अलग से नोटिस दे दें। जो इन्होंने पूछा था उसकी मैंने पहले ही हां कर दी है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि खडारा लिंक ड्रेन पर पिछले दस साल से काम हो रहा है। उसकी केवल 15-20 किलों की खुदाई बाकी रह गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो थोड़ा सा कार्य रह गया है, इसको कब तक करवा दिया जाएगा ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे पास इस बारे में डिटेल नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आने वाली बरसात से पहले ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। (शोर)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया और बलबंत सिंह मैना जी को हमने बताया कि रोहतक जिले में चाहे वह बाढ़ का पानी हो या किसी * * * का हो, पानी नहीं खड़ा होने देंगे। किसी तरह से भी बाढ़ से नुक्सान नहीं होने देंगे। (शोर)

श्री बंसी लाल : इन्होंने तो बाढ़ के पानी की बात कही है। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह बात कही है कि रोहतक जिले में किसी भी तरह से बाढ़ के पानी से नुक्सान नहीं होने देंगे। (शोर)

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, बेरी हल्के में गोछी और शेरिया की जमीन में आज भी बाढ़ का पानी खड़ा है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रोहतक जिले में बाढ़ पर नियंत्रण हेतु चालू साल में इतना पैसा खर्च करेंगे कि इतना पैसा पहले किसी भी सरकार ने खर्च नहीं किया होगा। (थम्पिंग)

(इस समय विपक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े हो गये।)

Mr. Speaker : Now, the question comes to an end (Interruptions). This is also a very serious matter that you are not obeying the orders of the Chair. I request you to take your seat. Now, next question.

Phirani of Diwana Village

***371 Dr. Virender Pal Ahlawat** : Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a metalled 'Phirani' (Ring Road) of village Diwana (District Rohtak) ?

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : नहीं, श्रीमान्, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, चुलाना से बहराना और बहराना से दिवाना गांवों में पूरी सड़कें बनी हुई है लेकिन दिवाना गांव की एक किलोमीटर फिरनी कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उस गांव के लोगों का बड़ा बुरा हाल रहता है। उस एक किलोमीटर फिरनी के कच्चा होने के कारण न कोई हरियाणा रोडवेज की बस गांव के अन्दर जाती है और न कोई प्राइवेट बस गांव के अन्दर जाती है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर उस गांव की फिरनी को मैटल्ड बना दिया जाए तो उससे उस गांव के लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। क्या मंत्री जी मेरी प्रार्थना पर विचार करेंगे।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, उस फिरनी के बारे में डी०सी० साहब की रिपोर्ट यह आई है। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, शिक्षा मंत्री जी ने रोहतक जिले के बारे में मरोड़ निकालने की बात कही है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि उस शब्द को एक्सपंज किया जाए यदि इस बात पर

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

आप मुझे नेम करना चाहते हैं तो बेशक नेम कर दें। मैं नेम होने से नहीं डरता। मुझे अपने रोहतक जिले के लिए नेम होने में गर्व होगा।

Mr. Speaker : Dhirpal Ji, please take your seat.

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इनकी तरफ से मेरे जिले की मरोड़ निकाली जाए और मैं बैठा बैठा इनकी बात को सुनता रहूं। (शोर) मुझे चेयर की तरफ से डराया जा रहा है, स्पीकर साहब, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Dhirpal Ji please take your seat otherwise I will name you. I would not allow you to speak like this.

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि रोहतक जिले में बाढ़ के पानी के कारण नुक्सान नहीं होने दिया जाएगा। चाहे बाढ़ का पानी हो और चाहे जोहड़ का पानी हो वहां पर नुक्सान नहीं होने देंगे मैंने यह कहा है। मैं इस बात पर अब भी कायम हूं। (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यों ने मरोड़ शब्द सुना हो तो मैं इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर मंत्री जी ने मरोड़ शब्द कहा है तो वह एक्सपंज कर दिया जाए।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। (शोर)

Mr. Speaker : No point of order. Now, the matter comes to an end. डा० वीरेन्द्र पाल जी आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं आपको पता होना चाहिए कि क्वैशचन आवर में कोई प्वायंट औफ आर्डर नहीं होता।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वैशचन लगा हुआ है और मैं सप्लीमैंटरी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं।

Construction of Bye-pass in Gohana.

***318. Shri Jagbir Singh Malik** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye-pass in Gohana ?

Public Work Minister (Shri Dharamvir Yadav) : Sir, proposal to construct a Bye-pass in Gohana as a part of development Scheme for National Capital Region is under consideration.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री धर्मवीर यादव : जैसे ही पैसा अवेलेबल होगा, इस पर विचार किया जायेगा।

Strengthening of Narwana Kakrod Road.

***348. Shri Birender Singh :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen and widen the Narwana-Kakrod road ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : No Sir.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल दिया था, वह मेरे द्वारा दिये सवाल को पूरी तरह से सरकार से पूछा नहीं गया। मैं बताना चाहता हूं कि लगातार 2-3 सालों से बाढ़ आने की वजह से यह सड़क लगातार डैमेज होती रही है। मैंने यह पूछा था कि क्या यह रोड बाढ़ में टूटी है, क्या इसकी मुरम्मत हुई है या नहीं। 1995 की बाढ़ आने के बाद जब चौधरी बंसी लाल मुख्यमंत्री बन गए थे कुछ दिनों के बाद ये बड़नपुर गांव में गए थे और ये इस नहर के हैड को देख कर आए थे। वहां पर जो डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा था उस पर रोड़ी डाल दी गई ताकि मुख्यमंत्री यह समझें कि सारी सड़क ठीक है। मैं बताना चाहूंगा कि यह 16 किलोमीटर की सड़क नरवाना से काकड़ा तक की है। वहां पर न कार और न दूसरे वाहन चल पाते हैं। जो प्राईवेट आपरेटर्ज ने वहां पर बस लगा रखी थी वह उन्होंने विदड्रा कर ली है। इसी प्रकार से ट्रैक्टर भी वहां पर नहीं चल पा रहे। यह ठीक है कि नेशनल हाईवे के लिए पैसा केन्द्र सरकार से आता है और हरियाणा सरकार उस पैसे से उसे बनवाती है। जो लिंक रोड हैं उनको निगलैक्ट किया हुआ है। यह रोड भी बहुत महत्व रखती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि काकड़ा से नरवाना जो रोड है जो बाढ़ में डैमेज हो गई थी क्या उसको ठीक कराने पर आप पुनर्विचार करेंगे। दूसरे मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्ट्रैन्थनिंग और वाईडनिंग में कितना फर्क है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं है।

Samples of Pesticides

***410 Shri Jagdish Nayar :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) the Districtwise and yearwise number of dealers who have been given licences for the sale of pesticides in the State during the period 1990-91 todate;

(b) the number of samples of pesticides if any, taken for laboratoty tests during the year 1994-95 to 1996-97; and

(c) @whether any of the samples out of those as referred to in part (b) above were found sub-standard; if so, the names of the firms whose samples were found sub-standrad together with the action taken against them ?

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal) : The statements are laid on the table of the House.

@ Statement concerning 'C' part of the question kept in the library as per orders of the Hon'ble Speaker dated 2-6-97

Statement (A)

(a) Statement showing the Districtwise & yearwise number of dealers who have been given licences for the sale of pesticides in the State during the period 1990-91 todate.

Sr.No.	District	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (Upto June,'97)
1.	Ambala*	119	115	130	127	143	132	191
2.	Yamuna Nagar	95	88	100	106	125	145	158
3.	Kurukshetra	260	279	310	298	310	377	310
4.	Kaithal	236	232	292	213	244	266	369
5.	Karnal	261	246	289	257	340	343	409
6.	Panipat	145	92	104	155	172	205	235
7.	Sonepat	89	118	130	148	145	153	168
8.	Faridabad	126	114	125	119	76	77	99
9.	Gurgaon	39	39	41	53	60	62	67
10.	Narnaul	62	62	61	89	107	174	199
11.	Rewari	36	36	42	56	63	105	115
12.	Bhiwani	227	275	42	55	82	83	103
13.	Rohtak	115	106	114	100	101	121	143
14.	Jind	229	266	300	376	500	661	722
15.	Hisar	600	819	827	1114	1390	1863	1660
16.	Sirsa	414	455	518	660	607	776	534
	Total	**3045**	**3343**	**3425**	**3926**	**4465**	**5533**	**5480**

*This includes the figures of District Panchkula.

[Shri Karan Singh Dalal]

Statement (B)

Statement showing the number of sample of Pesticides taken for Laboratory Tests during the period 1994-95 to 1996-97 (Upto Jan'97)

S.No.	Year	No. of Samples taken for laboratories tests
1.	1994-95	1071
2.	1995-96	986
3.	1996-97 (upto Jan'97)	1447

Digging of Safidon Drain

***417. Shri Ram Phal Kundu** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to dig out the Safidon drain from Village Chhaper to its tail ?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal) : Safidon Drain is an existing Drain passing through Village Chhaper. There is a proposal to deepen and desilt this drain and the estimates is under preparation. The work is likely to be completed before 30-6-97.

श्री रामफल कुण्डु : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सफीदों ड्रेन बहुत पहले की बनी हुई है। अब तक इसका यह नहीं पता कि यह किसके कन्ट्रोल में है। मैं इरीगेशन विभाग में गया था तो वे कहने लगे कि इस का काम पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट करेगा।

श्री अध्यक्ष : कुण्डु साहब आप बैठिये। अब क्वैश्चन आवर समाप्त हो गया है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Quantity of Wheat Received from Central Pool.

***381 Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state—

(a) the total quantity of wheat received by the State Govenment from Central Reserve Pool during the year 1996-97; and

(b) the district-wise details of the distribution of the wheat as referred to in para (a) above ?

Food & Supplies Minister (Sh. Ganeshi Lal) :

(a) The State Government received 1,56,558.1 MT of wheat from Central Reserve Pool during the period from 1-4-96 to 31-1-1997.

(b) The information is placed on the table of the House at Annexure 'A'

Annexure 'A'

District-wise information about the receipt of wheat by the State Government from the Central Pool.

(Figures in M.T.)

Sr. No.	Name of District	Received under the Scheme Public Distribution System/ Revamped Public Distribution System (PDS/RPDS) (from April, 96 to Jan.,97)	Received under open Market Sale Scheme (Domestic) OMSS (D) (from 20-12-96 to 31-1-1997)
1.	Ambala	1934.3	3600
2.	Bhiwani	23421.6	1817.8
3.	Gurgaon	4074	3090
4.	Faridabad	4076.5	6347
5.	Hisar	10800.5	5211
6.	Jind	1930	3368.5
7.	Kaithal	343	2978
8.	Kurukshetra	655	3600
9.	Narnaul	13550	2627.9
10.	Karnal	1003.4	3650
11.	Panipat	1847	4249
12.	Rohtak	10362.7	7360
13.	Rewari	11358.1	900
14.	Sonepat	2357.7	4158
15.	Yamuna Nagar	2283.1	3930
16.	Sirsa	4555	1300
17.	Panchkula	1839	1980
	Total	**96390.9**	**60167.2**

Setting up of Sugar Mill at Gohana

***399. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill at Gohana; if so, the time by which it is likely to be set up ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान् जी। गोहाना में एक नई चीनी मिल लगाने के लिए भारत सरकार से औद्योगिक लाइसैंस दिसम्बर,1993 में प्राप्त हो गया था। इस औद्योगिक लाईसैंस की वैधता दिसम्बर 1996 में समाप्त हो गई है तथा इस वैधता की बढ़ौतरी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार इस मिल के लिए मिले औद्योगिक लाईसैंस को लागू करना चाहती है तथा शीघ्र अति शीघ्र यह मिल लगाना चाहती है।

Mini Secretariat

***405. Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the time by which the construction work of Mini-Secretariat at Panipat is likely to be started/completed ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजपाल सिंह) : पानीपत में लघु सचिवालय के निर्माण हेतु भूमि अभिग्रहण के लिए कोशिशें की जा रही हैं। निर्माण कार्य शुरू/पूर्ण करने बारे कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता।

Development of Seeds

***385. Shri Ramji Lal** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state the details of the different varieties of seeds developed and released by Chaudhary Charan Singh Haryana Agricltural University, Hisar during the last five years ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : एक तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

तालिका

गेहूं	1.	डब्लयू०एच०-542	1992
	2.	डब्लयू०एच०-533	1993
	3.	डब्लयू०एच०-896	1995
बाजरा	4.	एच०एच०बी०-68	1992
धान	5.	हरियाणा बासमती-1 (एच०के०आर० 228)	1991
	6.	एच०के०आर०-126	1992
	7.	तरावडी बासमती (एच०बी०सी०-19)	1992
मूंग	8.	आशा (एम०एच० 83-20)	1991
मसूर	9.	सपना (एल०84-8)	1991

	10.	गरिमा (एच० 82-6)	1996
रायां	11.	लक्ष्मी	1996
ज्वार	12.	एच०सी०-6	1995
लोबिया	13.	सी०एस०-88	1995
कपास (अमेरिका)	14.	एच०एस०-6	1991
	15.	एच०-974	1991
	16.	धान लक्ष्मी (एच०एच०एच०-81)	1994
	17.	एच०-1098	1996
गन्ना	18.	सी०ओ०एच०-35	1992
	19.	सी०ओ०एच०-99	1996
मेथी	20.	एच०एम०-65	1996
ग्वाले	21.	एच०जी०-8	1991
टमाटर	22.	हिसार अरूण	1992
	23.	हिसार ललित	1992
	24.	हिसार ललिमा	1992
	25.	हिसार आनन्द	1992
भिण्डी	26.	वर्षा उपहार	1996
	27.	एच०आर०बी०-55	1992
बैंगन	28.	हिसार श्यामल (एच०-8)	1991
	29.	हिसार प्रगति (एच०-7)	1991
	30.	हिसार जामूनी (एच०-9)	1991
मिर्च	31.	हिसार शक्ति (एच०सी०-II)	1995
	32.	हिसार विजय (एच०सी०-28)	1995
सेम	33.	हिसार कीर्ति (एच०सी०-28)	1995

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

तोरी	34.	हिसार काली तोरी (एच०आर०जी०-4)	1995
मेथी	35.	हिसार सोनाली (एच०एम०-57)	1994
धनिया	36.	हिसार आनन्द (डी०एच०-5)	1994

Upgradation of Rajond Agriculture Marketing Sub-yard

***428. Shri Satvinder Singh Rana :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Rajond Agriculture Marketing Sub-yard; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Sub-yard is likely to be upgraded ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल)

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

Number of cases of Rape/Murder etc. registered in the State

***244. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the number of cases of rape, kidnapping, abduction and murder registered in the State during the period from 31st March, 1996 todate;

(b) the number of cases out of those as referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes;

(c) the number of cases, out of those as referred to in part (a) above in which the accused have been arrested/convicted and acquitted, separately, during the said period; and

(d) the number of cases category-wise as referred to above which are declared untraced together with the number of cases which are under trial in the various courts during the above said period ?

गृह मन्त्री (श्री मनी राम गोदारा) : विवरण तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

(क)

अपराध का शीर्ष	31-3-96 से 15-2-97 तक दर्ज किये गये मुकदमें।
बलात्कार	294
अपहरण/अपनयन	373
हत्या	523

(ख) उपरोक्त भाग (क) में दर्शाये गये मुकदमों में से अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार है।

बलात्कार	42
अपहरण/अपनयन	55
हत्या	44

(ग) मुकदमों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार, सजा और बरी हुए।

	मुकदमों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए	मुकदमों की संख्या जिनमें दोषी सजा हुए	मुकदमों की संख्या जिनमें दोषी बरी हुए
बलात्कार	279	—	15
अपहरण/अपनयन	279	—	3
हत्या	489	1	18

(घ) अदमपता भेजे गये और विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या।

	अदमपता	विचाराधीन न्यायालय
बलात्कार	2	197
अपहरण/अपनयन	11	152
हत्या	15	286

Setting up of 132KV Power House, Ellanabad

***363. Shri Bhagi Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 132KV Power House at Ellanabad district Sirsa; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : हां, श्रीमान जी बोर्ड के धन उपलब्धि पर निर्भर करते हुये 132 के.वी. उपकेन्द्र ऐलनाबाद को वर्ष, 1998-99 तक चालू किए जाने की सम्भावना है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

कृषि मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, आज के सारे अखबारों में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का विषय छाया हुआ है। उस काण्ड में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्य मन्त्री और इस सदन के सदस्य चौधरी भजन लाल का नाम भी आया है। नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए झारखण्ड मुक्ति मोर्चे के एम०पीज० को इस्तेमाल किया गया। हरियाणा सरकार के लोगों ने हरियाणा की सम्पति को दांव पर लगा दिया। (विघ्न) श्री शैलेन्द्र मेहता ने आज हल्फिया ब्यान दिया है कि उन्हें नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए कितना पैसा दिया गया। उन्होंने यह माना है कि नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए उनको रिश्वत दी गई है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर किया है। इस बारे में अखबार में यह छपा है——

> "On July, 28, added Mahato, Suraj Mandal said that every thing had been finalised and we have to vote against the no confidence motion. All the four of us, voted against the no confidence motion. ``Mahato said."

Shri Bhajan Lal : Speaker, Sir, on a point of order....(Interruptions.)

Mr. Speaker : Mr. Bhajan Lal, you please take your seat. Let Shri Karan Singh Dalal continue. You will get a chance. (Interruptions).

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी आज यहां पर बैठे हुए हैं। एक सच्चाई को श्री शैलेन्द्र मेहतो ने उजागर किया है। श्रीमान भजन लाल जी का नाम भी उसने लिया है। अध्यक्ष महोदय, जब ये सत्ता में थे उस समय आप विपक्ष में हुआ करते थे। उस वक्त की बातों का आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सत्ता और सरकार में होते हुए किस प्रकार से सरकारी धन और शक्ति का दुरूपयोग किया करते थे। आपको तो स्वंय को याद होगा क्योंकि आप इसके स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं। आज के सदन के नेता चौधरी बंसी लाल और उनके पुत्र सांसद को दफा 302 के मुकदमें में इन्होंने फंसा दिया था। आपको अच्छी तरह से पता है कि चौधरी भजन लाल जी अपने विरोधियों को दबाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा दिया करते थे। ये इस प्रकार अपनी पावर और पद का दुरुपयोग किया करते थे। आपके खिलाफ भी इन्होंने मुकद्दमा दर्ज करवा दिया था। हमारे एक चेयरमैन हुआ करते थे उनके ऊपर भी इन्होने मुकद्दमा बनवा दिया था। अध्यक्ष महोदय, नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए इन्होंने हरियाणा की प्रोपर्टी के साथ खिलवाड़ किया और अपने पद का दुरुपयोग किया। उस समय इन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। अध्यक्ष महोदय, शैलेन्द्र मेहतो ने एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाया है पिछले सत्र मे भी जब हमने इस बात को उठाने का प्रयास किया था तो इन्होंने हमें बोलने तक नहीं दिया था। (विघ्न एंव शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में जवाब दूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप अभी बैठिये वे अभी अपनी बात कह रहे हैं पहले आप उनको अपनी बात पूरी कहने दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने विपक्ष के भाईयों से एक बात कहना चाहूंगा कि सदन की एक गरिमा होती है। इन्सान से गल्तियां होती हैं क्योंकि इन्सान गल्तियों का पुतला है। चौधरी भजन लाल जी से भी गल्तियां हुई हैं और हरियाणा की जनता के सामने तथा सदन के सामने उन्हें अपनी गल्तियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। पिछली दफा जब इनकी सरकार थी उस वक्त भी मैंने इनको कहा था कि ये अपनी गलती को मान कर उस गलती को सुधारने की कोशिश करें और इस तथ्य को मान लें लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इसे नहीं माना था। (विघ्न) तो ये भी अपनी आत्मा के अन्दर झांके और जो इन्होंने गल्तियां की हैं उसके बारे में इनको मानना चाहिए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी कर्ण सिंह दलाल जी ने बोलते हुए मेरे बारे में बात कही है। ये दूसरी बार मैम्बर बन कर सदन में आए हैं। इस बात की हमें खुशी है। लेकिन मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो भी बात यहां पर बोलें वह सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। इन्होंने यहां पर पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चे के बारे में अखबार से कहानी पढ़ी है। यह जो कल का ब्यान है उसमें भजन लाल का कहीं पर भी नाम नहीं है। (विघ्न) मैं यह कहता हूं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चार एम.पी. हैं मैं उनको जिन्दगी में कभी भी कहीं नहीं मिला हूं। इन्होंने एक बात उनको प्लाट देने के बारे में कही है। अध्यक्ष महोदय, आज इनकी सरकार है और रिकार्ड भी इनके पास है। ये रिकार्ड देख लें और यहां पर बता दें कि मैंने किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एम.पी. को कोई प्लाट दिया है। अगर एक भी प्लाट ऐसा निकल आए तो मैं अस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। इसके अलावा जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि वह सरकारी गवाह बन गया है या बनना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी पर कौन विश्वास करेगा जो एक बार पहले भी गवाह बन गया था जब बाद में उसे किसी ने कहा कि तेरे को सजा हो जाएगी तो वह अदालत में जाकर मुकर गया। अब फिर वह कहता है कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे झूठे आदमी पर कौन विश्वास करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह मामला वैसे ही सब-जुडिस है इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा और न ही किसी को इस बारे में बात करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनको क्या तकलीफ है, इनको तकलीफ यह है कि मैंने अपने वक्त में कोई भी गलत काम नहीं होने दिया था। उस वक्त जो भी नाजायज काम थे उन पर मैंने रोक लगा दी थी लेकिन आज इनके वक्त में उन सबको छूट मिल गई है। अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने जिन्दल का नाम लिया। जब हमें पता चला कि वह निर्दोष है तो हमने 24 घंटे के अन्दर टाडा का केस वापिस लिया था।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 20-25 आदमियों को एक छोटी सी कोठरी के अन्दर बंद करके रखा था। इस बारे में पार्लियामैंट में बात आई तो इन्होंने उनको छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, जिन्दल साहब की फैक्टरी में एक सिक्योरिटी गार्ड वाइस एडमायरल रैंक का था। जिस को इन्होंने अन्दर किया था। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी तरह गलत बातें नहीं करता हूं और न ही गलत बात कहता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये जो गलत बातें हाउस में कहते हैं इनको नहीं कहनी चाहिए। सदन में सच ही कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं जीरो आवर में एक बात और कहना चाहता हूं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि जीरो आवर में प्वांयट आफ आर्डर नहीं होता है।

Mr. Speaker : He has not been allowed to raise the point of order. Please take your seat.

गृह मंत्री (श्री गनीराम गोदारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरीफिकेशन के लिए एक बात कहना चाहता हूं मैंने दलाल साहब से भी यह बात कही थी और मैं अब यही बात कह रहा हूं कि मेहतो ने कहा है कि उसे पश्चाताप करने की भावना जेल में जाने के बाद ही हुई है तो हो सकता है कि जेल में जाने के बाद इनको भी वैसी ही भावना आ जाए। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी तरह से कच्ची बात नहीं करता। आपको इस तरह की बातें कहना अच्छा नहीं लगता। आप मेरे से उम्र में बड़े हो इसलिए अगर मैं आपके बारे में ज्यादा कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल आप गुस्सा कहीं और होकर आए होंगे लेकिन आपने वह गुस्सा हमारे ऊपर उतारने की कोशिश की। आपने कल हमारे दो मैम्बर्ज को नेम भी कर दिया। कल तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी तरह से आपने अपोजीशन के लीडर को जब तक हाउस चलेगा तब तक के लिए सस्पैंड कर दिया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस फैसले को रिव्यू करें और ओम प्रकाश चौटाला जी को हाउस में बुलाएं। अगर आप उनको हाउस में नहीं बुलाएंगे तो यह कोई अच्छी बात नही होगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केस के बारे में तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। अध्यक्ष महोदय, ये अपनी बातों से ध्यान हटाकर दूसरी बातों पर ले आते हैं। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप चौटाला साहब को सदन में बुलाएं और अपने फैसले को रिव्यू करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यहां पर किसी का भी बैठना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हमें बोलने ही नहीं देंगे तो हमें भी फिर सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप हाउस की गरिमा को कायम रखिए और जब तक हाउस के अंदर अपोजीशन नहीं होता है तब तक हाउस के कोई मायने नहीं होते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। सबको बोलने का टाईम दिया जाएगा। जसविन्द्र सिंह, आपको भी बोलने का समय मिलेगा। आप बैठें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। चौधरी भजन लाल जी तो मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं लेकिन मैंने यह बात अपनी तरफ से नहीं कही थी बल्कि यह बात आज तमाम हिन्दुस्तान के अखबारों में आयी है। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी ने अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अब तो यह बात हो ली फिर अब ये क्यों इस बारे में कह रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने मेहतो साहब का गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। मैंने तो इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया बल्कि यह सब तो अखबारों में लिखा हुआ है।

श्री भजन लाल : लेकिन क्या किसी ने मेरे नाम के बारे में कहा है। किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी और चौधरी मनीराम जी मैंने आपसे कई बार रिक्वैस्ट की है। Please listen to him. Let Mr. Dalal finish his speech then I will ask you to speak.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने कल भी इसी सदन में यह बात दोहरायी थी। इन्होंने मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठकर उस समय बड़े घमंड से कहा था कि जब तक चौधरी भजन लाल बैठा हुआ है तब तक नरसिम्हा राव की सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला फरीदाबाद में सूरजकुंड नाम का एक कॉम्प्लैक्स है। यह ठीक है कि आज समाजवादी जनता पार्टी के हमारे भाई विपक्ष की भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हूं। आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हूं। अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहते तो मुझे नेम कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। अभी धीरपाल जी ने कहा था कि जीरो आवर में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता तो फिर आप प्वाइंट ऑफ आर्डर पर क्यों खड़े हैं।

श्री धीरपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चेयर में विश्वास करता हूं। कोई भी बात पूछनी होगी तो आपसे पूछूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप सदन की कार्यवाही निकाल लीजिए। धीरपाल जी पिछली दफा जब हमारे साथ विपक्ष में बैठा करते थे तो इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर यह इल्जाम दोहराया करते थे। (विघ्न एंव शोर)

श्री धीरपाल सिंह : यह झारखंड मुक्ति मोर्चा आपस की बात है। मुझे अभी अपनी बात कहनी है। (शोर एंव विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा था कि सूरजकुंड टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स पर (विघ्न) मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज चाहे चौधरी भजन लाल जी मना करें मगर नरसिम्हा राव जी की सरकार को बचाने के लिए न सिर्फ इन्होंने उन सांसदों को प्लौट दिए बल्कि उन संसद सदस्यों को अपनी देखरेख में उस टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स में रखवाया था। इनके गुंडों और हरियाणा पुलिस की देखरेख में उन सांसदों को ठहराया गया था। हरियाणा के खर्च पर उनकी सेवा की गई थी, लाखों करोड़ों रुपये उन पर खर्च किए गए थे। आज इस सच्चाई से ये क्यों मना करते हैं। (शोर एंव व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने दोहरा दिया। मैं कह रहा हूं कि यह मामला सब-जुडिस है इसलिए इस पर यहां डिसकशन नहीं होनी चाहिए। न ही मेरा कोई होटल से वास्ता है और न

[श्री भजन लाल]

मैं किसी को होटल में ठहराता। दुनियां होटल में जाती है और ठहरती है मेरी उसमें क्या ठेकेदारी है। बंसी लाल जी और आप लोगों ने दो विधायक समाजवादी पार्टी के तोड़े और आपने उन्हें मंत्री पद दिया। (शोर एंव व्यवधान) इससे ज्यादा प्रलोभन और इससे ज्यादा सही सबूत और क्या हो सकता है। मुझे यह बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है। अगर सरकार बचाने की बात स्टेट की हो तो मुख्यमंत्री को विधायक से बात करनी पड़ेगी। इसी प्रकार सैन्टर में होता है। (विघ्न) कल से दोनों बाप-बेटों की नींद हराम हो रही है। दोनों 5-5 मिनट में लौबी में जाकर मिलते हैं।एक सतेन्द्र डी.आई.जी. है और एक इनका बेटा सुरेन्द्र है जैसे प्रताप सिंह कैरो का उनके बेटे ने नाश करा था इसी तरह से ये दोनों इनका नाश करेंगे। (शोर एंव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठ जाइए। (शोर एंव व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय चौधरी भजन लाल ने कहा कि ये जो दो मैम्बर बैठे हैं इनको हमने तोड़ा है। लेकिन इन दोनों मैम्बर्ज को इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी से एक्सपैल किया है और इस बारे में आपको लिखकर दिया कि हमने इन दोनों मैम्बर्ज को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। फिर मैं कैसे इनको तोड़ कर लाया था। ये यहां पर बैठे बैठे डींगें हांक रहे हैं। जो सूरजकुण्ड का किस्सा है उसके बारे में थोड़े ठहर जाओ सारा सामने आ जाएगा कि पेमैंट किसने की थी और क्या-क्या कुकर्म वहां हुए थे। एक-एक चीज हम निकालकर लायेंगे कि ये भजन लाल जी कहां खड़े हैं।ये कहते हैं कि बाप-बेटे की नींद हराम हो रही है। हम तो बाप-बेटा फटकार कर सोते हैं। नींद तो हराम इनकी हो गई है 24 घंटे की। इनको पता है कि ये कहां खड़े हैं।

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा चौधरी बंसीलाल जी ने कहा है। आप मेरी बात भी सुनिये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजनलाल जी आप बैठिये, लीडर आफ दी हाउस बोल रहे हैं और आप बीच में बोलते है Ch. Bhajan Lal Ji, it is very bad, when the Leader of the House is speaking, you stand up. Kindly take your seat. (Noises & Interruptions.) Chaudhary Bhajan Lal Ji, kindly take your seat.

श्री बंसी लाल : हकीकत तो यह है कि नींद तो इनके पूरे कुनबे को नहीं आती है। सी.बी.आई. ने हमको लिखकर दिया कि इनके बैड रूम से शराब मिली है। इनकी गोदरेज की अलमारी से शराब मिली है। ये कहते हैं कि मुनीम की शराब है। मुनीम पांच हजार वाली शराब पीयेगा क्या, उस मुनीम को एक घूंट तो पिलाकर दिखा दो। इनके बेटे के घर से शराब मिली। इनके दामाद के घर से 80 बोतल शराब मिली और वह भी इम्पोर्टिड शराब। अभी तो और चीजें भी मिलनी बाकी है और ये कहते है कि वह शराब नहीं पीता। बिशनोई धर्म में तो (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये (विघ्न)

Mr. Speaker : Ch. Bhajan Lal Ji, Please take your seat. (Interruptions). Chaudhary Bhajan Lal Ji, I warn you. You kindly take your seat. Don't Interrupt like this, when the Leader of the House is speaking.

श्री बंसी लाल : हमने तलाशी नहीं ली, तलाशी तो सी.बी.आई. ने ली थी। हमें तो सी.बी.आई. ने लिखकर दिया कि यह शराब मिली है। वह शराब भी चार-पांच हजार रुपये की बोतल आती है। यह

इतनी महंगी शराब पीता है और कहता है कि वह शराब नहीं पीता। कहता है कि बिश्नोई तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब तो देने दीजिये (विघ्न)

Mr. Speaker : No, No, Chaudary Bhajan Lal Ji, please take your seat. I have asked Ch. Dhir Pal Ji, to speak. He will speak, first. (Interruptions.)

Shri Bhajan Lal : Mr.Speaker, Sir, ...

Mr. Speaker : Chaudary Bhajan Lal Ji, I warn you again, you kindly take your seat. (Interruptions.).

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल बजट अभिभाषण पर हुई चर्चा की रिप्लाई के समय सदन का माहौल बहुत खराब हुआ। स्पीकर सर, आप भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि विरोधी पक्ष की भी कोई जिम्मेदारी होती है। हमारी पार्टी के विरोधी पक्ष के नेता चौधरी ओम प्रकाश जी ने विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार से तथ्यों की जानकारी चाही थी। लेकिन उन तथ्यों को छिपाया गया था। आप भी पांच साल ईमानदारी से विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो तथ्य रह गये थे प्रकाश में नहीं आये थे उसकी जानकारी हम सरकार से जानना चाह रहे थे। टीका टिप्पणी का माहौल पक्ष की तरफ से तो होता ही रहता है। उसी आधार पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाउस का माहौल खुश करने के लिए अगर टीका टिप्पणी का माहौल बनता है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। टीका-टिप्पणी विरोधी पक्ष की तरफ से होती रहती है। किसी चीज के बारे में जानकारी लेना विरोधी पक्ष का फर्ज बनता है। कल सदन का माहौल खराब नहीं हुआ था। इसलिए यह बहुत ही दुःखदाई बात है। हाउस के नेता ने चेयर को संबोधित करते हुए कहा कि या तो स्पीकर सर आप इनको ठीक कर दो या हम ठीक कर देंगे। इस प्रकार से जो ईलाज किया गया, वह यह किया गया कि विरोधी पक्ष के नेता को पूरे बजट सैशन के लिए सस्पैंड कर दिया गया। बजट सैशन में विरोधी पक्ष का नेता न हो तो इस पर चर्चा का कोई महत्व नहीं रहता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कल कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं थी जिसके लिए विरोधी पक्ष के नेता को सस्पैंड किया जाए। चूंकि आप पर हमारा पूरा भरोसा है, इसलिए आपसे विनती है कि जो कल यहां पर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पैंड करने का फैसला लियां गया, वह वापिस लिया जाए। इस बारे में मेरी न केवल आपसे ही प्रार्थना है बल्कि हाउस के नेता चौधरी बंसी लाल जी से भी गुजारिश है। ये मेरे से बड़े हैं। इन्होंने भी तो 5 साल विरोधी पक्ष में बैठकर बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया है। (विघ्न) यहां पर हरियाणा के और प्रैस के लोग बैठे हैं। क्या आप लोग हाऊस के नेता से गुजारिश करने का हमारा अधिकार भी छीन लेंगे ? मैं आपके माध्यम से हाऊस के नेता से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो परम्पराएं हैं, ये ठीक नहीं हैं। चौधरी बंसी लाल जी तो कई बार लोकसभा के, जो कि देश की सर्वोच्च पंचायत है, उसके सदस्य रह चुके हैं। वहां पर इन्होंने चर्चाएं देखी हैं तथा उन चर्चाओं में हिस्सा लिया है। वहां पर चर्चाओं का जवाब भी दिया है। ये डिफैंस मिनिस्टर भी रहे हैं और रेलवे मंत्रालय भी वहां पर इनके पास रहा है। इसलिए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए यह जरूरी है कि उस आदेश को वापिस लेने में कोई पाप नहीं है। क्योंकि बजट चर्चा में अगर विरोधी पक्ष का नेता हिस्सा न ले तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वह चर्चा नीरस हो जाती है। चौटाला साहब आपकी अनुमति से ही खड़े हुए थे तथा आपकी अनुमति से ही सरकार से जानकारी ले रहे थे। यह विपक्ष का फर्ज भी बनता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस आदेश पर पुनर्विचार करते हुए उस आदेश

[श्री धीरपाल सिंह]

को वापिस लिया जाए और चौटाला साहब को बजट चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हाउस में बुलाएं। स्पीकर सर, श्री सुर्जेवाला जी बहुत अच्छे वकील हैं। ये पहली बार चुनाव जीतकर सदन में आए हैं। उनके बोलने का अंदाज इतना बेहतरीन है कि सभी उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन कल जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको भी नेम कर दिया गया। मैं आपके आदेश को चेलेंज नहीं करता हूं और न ही मेरी ऐसी कोई मंशा है। लेकिन जो सदस्य सभ्य ढंग से बोले, हम भी उनकी तारीफ करते हैं, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कैप्टन साहब देश की सेवा करके आए हैं, उनको भी नेम कर दिया गया है। (विघ्न) इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आपने उनको बोलने की अनुमति दी, यह एक अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की परंपराएं या मर्यादाएं नहीं डाली जाएं तो अच्छी बात होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं विपक्ष के उप नेता को बताना चाहता हूं (विघ्न) पार्टी के अध्यक्ष श्री धीरपाल सिंह जी को बताना चाहता हूं कि यह निर्णय मेरा नहीं था। यह तो हाऊस का फैसला था। This is for your kind information.

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, उनकी सस्पैंशन का प्रस्ताव उधर से मूव हुआ। आप इस 11.00 बजे हाउस में सदन के नेता से सुप्रीम हैं। इसलिए अगर कोई प्रस्ताव पास हो गया तो उसके बारे में आखिरी फैसला आपका होता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप उस फैसले पर पुनर्विचार करके उसको रद्द करें। हाउस में अच्छी परम्पराएं कायम की जानी चाहिएं। स्पीकर साहब, आपका लोकतंत्र में भरोसा है, हमारा आप में भरोसा हो।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात हो चुकी अब आप हाउस का बिजनैस शुरू कराएं। (शोर)

नियम 104 का निलम्बन तथा श्री भजन लाल एम०एल०ए० का सदन की सेवा से निलम्बन

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बहुत सीरियस मैटर लाना चाहता हूं। हमने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है इसलिए हाउस का दूसरा बिजनैस शुरू करने से पहले उस पर विचार किया जाए। (शोर)

(इस समय विपक्ष की ओर से बहुत सारे सदस्य खड़े होकर बोलने लग गए। अध्यक्ष महोदय के बार बार आग्रह करने पर भी वे बोलते रहे।)

Mr. Speaker : Mr. Bhajan Lal, please take your seat. This is not a fish market.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है..

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal): Speaker Sir, I seek your permission to move a motion regarding suspension of Shri Bhajan Lal, from the House and suspension of Rule 104 also.

I beg to move —

> That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Bhajan Lal.

Mr. Speaker : Motion moved —

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Bhajan Lal.

Mr. Speaker: Question is -

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Bhajan Lal.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I also beg to move -

That Shri Bhajan Lal, M.L.A. be Suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this August House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved -

That Shri Bhajan Lal, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct most irresponsible behaviour unbecoming of theMember of this August House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is -

That Shri Bhajan Lal, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this August House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, I request Shri Bhajan Lal to leave the House.

(At this stage Shri Bhajan Lal left the House.)

वाक-आउट

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, आप ये गलत परम्पराएं डाल रहे हैं इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (शोर)

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी उपस्थित माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, हम भी एज ए प्रोटैस्ट सदन से बाक आउट कर रहे हैं।

(इस समय समता पार्टी के सभी उपस्थित माननीय सदस्य सदन से बाक आउट कर गए।)

वर्ष 1996-97 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the supplementary Estimates for 1996-97 will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands on the order paper (Nos. 1 to 11, 13to 18 and 21 to 25) will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,32,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,37,73,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 30,71,86,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 86,38,67,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,64,38,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.5- Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 38,92,33,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,69,46,76,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.7-Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,73,65,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come

in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.8-Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 59,93,77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46,30,09,000 for revenue expenditure and Rs. 1,07,39,08,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.10-Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 33,04,75,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,71,74,000 for revenue expenditure and Rs. 49,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,17,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,39,22,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 15-Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 50,24,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,82,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,74,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,45,87,000 for revenue

[Mr. Speaker]

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No.21-Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,67,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 22-Co-operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,32,69,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 34,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 25-Loans ans Advances by State Goverbnment.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,32,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,37,73,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 30,71,86,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 86,38,67,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,64,38,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come

in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 38,92,33,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,69,46,76,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,73,65,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 8-Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 59,93.77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46,30,09.000 for revenue expenditure and Rs. 1,07,39,08,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 33,04,75,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

Mr. Speaker : Question is-

The motion was carried.

नियम 104 का निलम्बन तथा सर्वश्री धीरपाल सिंह और रमेश कुमार एम०एल०एज़० का सदन की सेवा से निलम्बन

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, हम डिवीजन चाहते हैं (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने डिमांडज़ मूव करने के बाद बोलने का मौका दिया था लेकिन कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उस समय आप डिवीजन भी मांग सकते थे लेकिन अब वह स्टेज निकल चुकी है।

(इस समय विपक्ष के सभी सदस्य खड़े होकर बोलने लग गए। अध्यक्ष महोदय के बार-बार कहने पर भी बोलते रहे)

Mr. Speaker : Mr. Dhirpal, I warn you. Please take your seat. (noise)

(अध्यक्ष महोदय के बार-बार कहने पर भी विपक्ष के सदस्य बोलते रहे।)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं एक मोशन मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मूव करें।

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir. I beg to move-

> That Rule 104 of the Rules of procedure and Conduct of business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Dhirpal Singh, M.L.A.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That Rule 104 of the Rules of procedure and Conduct of business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Dhirpal Singh, M.L.A.

Mr. Speaker : Question is-

> That Rule 104 of the Rules of procedure and Conduct of business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Dhirpal Singh, M.L.A.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I also beg to move-

> That Shri Dhirpal Singh, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That Shri Dhirpal Singh, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is-

> That Shri Dhirpal Singh, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

Shri Ramesh Kumar : Speaker Sir,..... (Noise & Interruptions)

Mr. Speaker : Mr. Ramesh Kumar Khatak, I warn you. Please sit down. (Noise & Interruptions). (At this stage the members of the Samta party continued raising slogans and there was great desorder in the House).

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं एक मोशन मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मूव करें।

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move-

That Rule 104 of the Rules of procedure and Conduct of business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Ramesh Kumar Khatak, M.L.A.

Mr. Speaker : Motion moved-

That Rule 104 of the Rules of procedure and Conduct of business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Ramesh Kumar Khatak, M.L.A.

Mr. Speaker : Question is -

That Rule 104 of the Rules of procedure and Conduct of business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Ramesh Kumar Khatak, M.L.A.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I also beg to move-

That Shri Ramesh Kumar, Khatak M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved-

That Shri Ramesh Kumar, Khatak M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is -

That Shri Ramesh Kumar, Khatak M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

वर्ष 1996-97 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,71,74,000 for revenue expenditure and Rs. 49,00,000 for capital expenditure be granted to the

[Mr. Speaker]

Governor to defray charges that willl come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,17,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,39,22,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 15-Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 50,24,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,82,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,74,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr.Speaker : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,45,87,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 21-Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,67,20,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 22-Co-operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,32,69,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 34,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in

the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि आप मेरी सुनें। मुझे आप मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र पाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) Virender pal Ji, I warn you. Please take your seat. (Interruptions.)

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, हम डिवीज़न चाहते हैं। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Virender Pal Ji, please take your seat. This is not the stage, those demands have since been passed. You please have patience. Kindly take your seat. वीरेन्द्र जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) आप मेरी बात सुनिये। ये डिमांड पिछले साल की थी। अभी डिमाण्ड्स आने वाली हैं। (विघ्न एवं शोर) I request all the members to take their seats. (Interruptions.).

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, डिमांड फार ग्रांटस आन बजट पर तो बहस होगी। क्या आप उस पर हमें बोलने देंगे ? (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने तो पहले ही यह कहा है कि आप उस पर बोल लेना। (विघ्न एवं शोर)

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on demands for grants on Budget for the year 1997-98 will take place. As per past practice, in order to save the time of the House, the demands for grants on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding Rs. 3,37,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 64,90,66,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs.2,40,80.11,000 for revenue expenditure and Rs. 14,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 53,05,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 23,64,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 2,51,72,83,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 36,95,28,24,000 for revenue expenditure and Rs. 3,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 1,18,31,02,000 for revenue expenditure and Rs. 1,77,34,80,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 7,41,06,39,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 3,69,70,17,000 for revenue expenditure and Rs. 1,13,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 37,70,68,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 35,34,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course

of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 2,36,05,96,000 for revenue expenditure and Rs. 2,98,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 12,64,31,000 for revenue expenditure and Rs. 5,06,13,36,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 5,91,84,00,000 for revenue expenditure and Rs. 2,93,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 33,53,92,000 for revenue expenditure and Rs. 13,11,35,000 for capital expendirture be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 1,97,59,12,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 56,96,70,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 6,56,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 57,98,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 80,81,28,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 16,05,00,000 for revenue expenditure

[Mr. Speaker]

and Rs. 11,72,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 22-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 3,59,73,73,000 for revenue expenditure and Rs. 46,32,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 30,27,000 for revenue expenditure and Rs. 4,03,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 3,72,34,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 25-Laons and Advances by State Government.

Mr. Speaker : I have also received notices cut motions on the various demands from some M.L.As. These will be deemed to have been read and moved. However, I will put the various cut motions to the vote of the House when the respective demands are put to the vote of the House. Such members may, however, participate in the discussion.

Demand No. 3 (Home)

Shri Birender Singh,
Capt. Ajay Singh,
Shri Randeep Surjewala : That the Demand be reduced by Rs. 2/-.

Demand No. 5 (Excise and Taxation)

Capt. Ajay Singh,
Shri Randeep Surjewala,
Shri Dharambir Gauba : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 8 (Buildings and Roads)

Shri Dharambir Gauba : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 9 (Education)

Capt. Ajay Singh : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 10 (Medical and Public Health)

Capt. Ajay Singh,
Shri Jai Singh Rana,
Shri Randeep Surjewala : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 11 (Urban Development)

Shri Birender Singh,
Shri Dharambir Gauba,
Capt.Ajay Singh,
Shri Chander Mohan : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 12 (Labour and Employment)

Capt. Ajay Singh,
Shri Randeep Singh Surjewala : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 13 (Social Welfare and Rehabilitation)

Capt. Ajay Singh,
Shri Randeep Singh Surjewala : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 15 (Irrigation)

Shri Birender Singh,
Capt. Ajay Singh,
Shri Randeep Singh Surjewala,
Shri Narender Singh,
Shri Jai Singh Rana ; That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 16 (Industries)

Shri Birender Singh,
Shri Dharambir Gauba,
Capt. Ajay Singh : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 17 (Agriculture)

Capt. Ajay Singh,
Shri Jai Singh Rana,
Shri Randeep Singh Surjewala : That the Demand be reduced by Rs. 1/-.

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 3 गृह विभाग से सम्बन्धित है, डिमान्ड नं० 11 अर्बन डिवैल्पमैंट से सम्बन्धित है, डिमान्ड नं० 15 इरिगेशन से सम्बन्धित है और डिमान्ड नम्बर 16 इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित है इनके बारे में मैंने कट-मोशन दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जब बजट पर डिस्कशन हुई तो उसमें बहुत से मैम्बर्ज को चर्चा करने का मौका मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों,समस्याओं और मांगों पर भी बात कही और सरकार का उन बातों पर ध्यान आकर्षित किया। मुझे उम्मीद है कि अब आप बहुत से सदस्यों को डिमान्डज़ पर भी बोलने का मौका देंगे। इसके साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल पर भी आनरेबल मैम्बर्ज को बोलने का मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलते हुए मैंने यह कहा था कि सरकार ने जो 1997-98 का बजट पेश किया है। इस बजट के बारे में डिवैल्पमैंट औरियंटिड बजट कहा था लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह लगता हो कि यह सरकार बिजली बढ़ा सकती है। इसमें सिंचाई के जो साधन है उसको बढ़ाने के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं है। इस विषय में सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। ऐसा लगता है कि सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय,

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

पिछले दिनों में मुझे पता चला है कि हर ट्रेजरी से सुबह शाम यह सूचना दी जाती थी कि फलां ट्रेजरी से इतना पैसा निकाला गया है और इतना पैसा रैवेन्यू के तौर पर जमा हुआ है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि ये अपने वित्तीय संसाधनों की वजह से डे टू डे निर्भर कर रहे है जिससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह का काम चल सके। पिछले नौ महीनों में सरकार ने हरियाणा को प्रगति पर लाने के जो वायदे किए थे वे सारे आज खोखले होकर रह गए हैं। बिजली के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि 1986 से लेकर आज 1997 तक 11 साल हो गए हैं, आज तक हरियाणा के अन्दर बिजली का संकट खत्म नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी आप यह बताएं कि आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नं० 3, 11, 15, और 16 पर बोल रहा हूं।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें जनरल भी बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बीरेन्द्र सिंह जी आप बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने हरियाणा में आज तकरीबन चार करोड़ यूनिट बिजली देने का क्लेम किया है। कहीं पर यह 4.20 करोड़ यूनिट है, कहीं पर 3.90 करोड़ यूनिट भी है और कहीं पर 4.80 करोड़ यूनिट है लेकिन इन्होंने क्लेम किया है 4 करोड़ यूनिट बिजली देने का । हमने जो बिजली ऐग्रीकल्चर सैक्टर में, इंडस्ट्रियल सैक्टर में या दूसरे सैक्टर्ज में उपलब्ध कराई है, अगर उसको सही मायनों में देखा जाए तो हरियाणा राज्य को आज जितनी बिजली की जरूरत है,उससे यह लगभग आधी बिजली है जिसको सरकार मुहैया कराने का दावा करती है। स्पीकर सर, अगर मैं इसमें भी प्रो० गणेशी लाल जी के आकंडों को सही मान लूं तो 31 प्रतिशत से ज्यादा बिजली ट्रांसमिशन और लाईन लौसिज में ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तिहाई बिजली यानी एक करोड़ तीस लाख से लेकर एक करोड़ चालीस लाख यूनिट बिजली उपभोक्ता को नहीं मिलती, चाहे वे इंडस्ट्रियल सैक्टर में हों, चाहे वे किसान हों। एक तिहाई बिजली तो लाईन लौसिज के नाम पर ही खत्म हो जाती है। जिसका अभिप्राय यह है कि अगर उस एक करोड़ तीस लाख यूनिट बिजली को रुपयों में परिवर्तित किया जाए तो करोडों रूपये साल के लाईन लौसिज के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो मान सकता हूं कि इंटरनैशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रांसमिशन लौसिज और डिस्ट्रीब्यूशन लौसिज 14 एवं 16 प्रतिशत के बीच हो सकते हैं। आज बहुत से डिवैलपड कंट्रीज है ईवन जापान में भी लाईन लौसिज चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होते।इसी तरह से दूसरे अन्य विकसित देश हैं जिनमें लाईन लौसिज 6 या 8 प्रतिशत ही रहते हैं। परन्तु हम अगर यह भी मान लें कि 14 प्रतिशत लाईन लौसिज हैं तथा बाकी के जो और 18 प्रतिशत के लाईन लौसिज हैं, (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) वह बिजली बोर्ड की अपनी इनएफीशिएंशी की वजह से ही हैं, उसकी अपनी कमी की वजह से ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा बंसीलाल जी ने कहा था कि हमको टोटल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बदलने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये चाहिएं। (विघ्न) आज उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि टोटल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को तबदील करने के लिए 6 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

श्री बंसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय,-मैंने यह कहा था कि अगले पांच साल में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन एवं दूसरे संसाधनों को ठीक करने के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये हमको चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : चलो, पांच हजार करोड़ रुपये ही होंगे लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। चाहे यह बात 6 हजार करोड़ की हो या सात हजार करोड़ की हो लेकिन जब मैं शुरू में विधानसभा का सदस्य था तब इसकी जरूरत सिर्फ 900 करोड़ रुपये में पूरी हो सकती थी जबकि आज आप ट्रांसमिशन को बदलने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अपने विधानसभा के दूसरे सत्र में यह कहा था कि हम उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश से कुछ बिजली लाकर हरियाणा की आपूर्ति करना चाहते हैं। इन्होंने उस समय यह भी कहा था कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपनी वर्तमान लाईनों पर उस बिजली को यहां ला सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने तो मुख्यमंत्री जी को कहा था कि हम इस बात को पार्टी लेवल से ऊपर उठकर सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज इसका दोषी किसान नहीं है, इसका दोषी उद्योगपति नहीं है, इसका दोषी हरियाणा का नागरिक नहीं है लेकिन वे इसको भुगत रहे हैं। आपने वहां पर भी बिजली की दरें बढ़ा दी जहां पर स्लैब रेट्स थे, फ्लैट रेट्स थे। जो महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, भिवानी या कालका का कुछ हिस्सा था, वहां पर भी आपने बिजली के रेट्स दूसरे और हिस्सों के बराबर कर दिए जिसकी वजह से किसानों में बड़ी भारी निराशा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दरें बढ़ाने का काम था, इसको अगर आप एक तरफ रखकर बिजली बोर्ड को यह कहते कि मैं यह चाहता हूं कि एक साल के अंदर जो 700 करोड़ रूपये का आप नुकसान करते हैं इसे कम करो। बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों और इंजीनियर्स की एफिशिएंसी आप बढ़वाते और उनसे कहते कि इस नुक्सान को आधा करो। इसको 18, 19 या 20 प्रतिशत तक लेकर आओ। इस तरह से 250-300 करोड़ रुपये का बोझ बिजली बोर्ड पर होना था, उसके साथ-साथ बिजली की कमी थी। आखिर हम क्यों गए प्राइवेट सैक्टर की तरफ इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार इस बात में असमर्थ है कि हम 700 करोड़ रूपया हर साल पूल करें और बिजली बोर्ड के खाते में डाल दें। जब डालने की बात आती है तो उसका बोझ या तो हुड्डा पर पड़ता है या मार्किटिंग बोर्ड पर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अर्बन डिवैल्पमैंट की डिमांड पर कट मोशन दी है। किस नजरिए से यह कह दिया गया कि बहादुरगढ़ जहां इंडस्ट्रीयल एरिया है वहां अढ़ाई हजार रूपये स्कवैयर मीटर के हिसाब से कम की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी और गुड़गांव में यह कह दिया कि छह हज़ार रुपये स्कवैयर मीटर से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी वजह यह थी कि हुड्डा के पास पैसा आए और उस सरप्लस मनी को आप बिजली बोर्ड के अंदर या आपके जो अदायरे घाटे में चल रहे है उनकी पूर्ति करें। यह इस बात की कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : मैं बीरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि ये सारी बातें ठीक कह रहे हैं लेकिन साथ-साथ हमको उनका ईलाज भी बता दें। सुझाव भी देते जाएं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : आपके विधायक आपके पास पता नहीं शिकायत करते हैं या नहीं ? भारत की कैपिटल दिल्ली में जो 39 हजार फैक्ट्री रैजिडैंसिज में लगी थी उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको शिफ्ट किया जाए। उनमें से 70 प्रतिशत फैक्ट्री हरियाणा में शिफ्ट होतीं लेकिन अगर किसी को बहादुरगढ़ में एक हजार गज का प्लाट लेना पड़े तो 25 लाख की रजिस्ट्री कहां से कराएगा और 5 लाख रूपये उस पर खर्च आएगा। 20 लाख रूपया व्हाइट में कहां से आएगा। मेरा इस बारे में सुझाव है कि जहां-जहां आपने एकदम इतनी बढ़ौतरी की है उस बढ़ौतरी पर पुनर्विचार करें। साउथ दिल्ली के लोगों का हरियाणा में कारखाने स्थापित करने के लिए जो आकर्षण बना था, जो लोग साउथ दिल्ली में पौल्यूशन से परेशान हैं वे सारे के सारे गुड़गांव में शिफ्ट करना चाहते थे। वे सारे के सारे परेशान हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी रही है। अब ठीक है कि चिदम्बरम जी ने प्रोग्राम दिया है

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

कि 30 प्रतिशित जमा कराओ और कितना भी काला धन सफेद में परिवर्तित करा लो। पता नहीं इस बात का लोगों में कितना उत्साह होगा लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो ऐस्टेट डील है उसमें 10 प्रतिशत तो हो सकता है कि व्हाइट मनी हो लेकिन 90 प्रतिशत लोग उसमें ब्लैक मनी इन्वैस्ट करते हैं। आपने हरियाणा में उन लोगों के निवेश को रजिस्ट्री की दर बढ़ाकर रोक दिया है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : इसका सुझाव दो।

श्री बीरेन्द्र सिंह : आपने दो स्लैब रखे हैं अगर अर्बन एरिया में रजिस्ट्री है तो स्टाम्प ड्यूटी मिला कर साढ़े पन्द्रह प्रतिशत खर्च है और रूरल एरिया में साढ़े बारह परसैंट के करीब पड़ता है। मेरा सुझाव है और मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि टोटल टैक्स स्ट्रक्चर में उसका हिस्सा है टैक्स स्ट्रक्चर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ओवर हालिंग करने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप स्टैम्प डियूटी घटा देंगे तो आपकी आय बढ़ेगी। रजिस्ट्री के बारे में आपने कहा कि गुड़गांव में छः हजार रु० स्क्वेयर मीटर से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी अगर इसको आप स्लो डाउन कर देंगे, कम कर देंगे तो काफी हद तक, आपका रैवन्यू बढ़ेगा और इन्वैस्टर्ज को मौका मिलेगा कि वे हरियाणा में ज्यादा पैसा इन्वैस्ट करें। यू०पी० में आज लॉ एण्ड आर्डर की हालत कैसी भी हो लेकिन ज्यादातर इन्वैस्टर आज नोयडा में जाना पसंद करते हैं, हरियाणा की तरफ मुंह भी नहीं करते। हरियाणा का रास्ता आप बंद मत कीजिए आप अपने सारे सिस्टम का पुनर्निरीक्षण करें और इस इन्वैस्टर को हरियाणा की तरफ आने के लिए जोर दें। अगर आप दिल्ली को ज्यादा हरियाणा की तरफ आकर्षित करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि जनता की काफी परेशानियां है। आपके नौ महीने के कार्यकाल में डिवैल्पमैंट का काम नजर नहीं आया। लोग कहते हैं कि चौधरी बंसी लाल वह बंसी लाल नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों ये नये कारखाने हरियाणा की तरफ आने शुरू हुए हैं तब से नेशनल हाईवे पर ज्यादा कंजैक्शन और एक्सीडेंट ज्यादा होने शुरू हो गये हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा समय लगता है। यहां पर एक मशरूम ग्रोथ शुरू हो गया है और गांव के चौराहे जैसा माहौल हो गया है क्योंकि एक फैक्टरी जहां लगती है वहां पर चार-पांच दुकानें बना ली जाती हैं। मेरा एक सुझाव है खासकर हुड्डा और एच.एस.आई.डी.सी. के लोगों से कि आप अगर मेन रोड़ के साथ फैक्ट्री लगाओगे तो दस साल के बाद आपको चार किलोमीटर के बाई पास बनाने की बजाये चालिस किलोमीटर के बाई पास बनाने पड़ेंगे। मेरा आपसे एक सुझाव है कि जहां सड़कों के पास नई-नई फैक्ट्री आनी शुरू हो गई हैं उन सड़कों के जो लिंक रोड़ हैं उनको वाईडन कीजिए और उसी स्तर का जो नेशनल हाई वे है उसको आप दो किलोमीटर अंदर ले जायें अगर आप दो किलोमीटर अंदर ले जायेंगे तो जो उद्योगपति हैं वे डेढ़ या एक किलोमीटर अंदर जाकर फैक्ट्री को बनाना पसंद करेंगे। इससे क्या होगा कि जिसकी दो किलोमीटर के अंदर जमीन है उसकी जमीन की कीमत जो आज एक लाख रूपये एकड़ है उसका भाव दस दिन के अंदर 5,6,7,8 और दस लाख रूपये एकड़ हो जायेगा और जो सड़कों पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं वे घट जायेंगे। औद्योगिक विकास का असर सड़कों पर सीधा नहीं रहेगा। आप कभी केरल गये हों तो वहां त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक यह पता नहीं लगता कि गांव कौन सा है। (विघ्न) वहां एक गांव की सीमा जहां खत्म होती है वहीं दूसरे गांव की शुरू हो जाती है इसलिए इस महकमे को सोचना चाहिए जिससे आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा और दस साल बाद जो समस्या पैदा होगी उस समस्या का भी समाधान हो जायेगा। दूसरा मैं इरीगेशन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र नरवाना में जिसमें कुछ नौल्था का क्षेत्र भी है यानि आधे जिला जींद की भूमि यमुना कैनाल से सिंचित

की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, दस साल पहले एक आदेश जारी हुआ था जिसके मुताबिक नहरी पानी रोटेशन से 15-15 दिन मिलता था यानि 15 दिन एक नहर का तथा 15 दिन दूसरी नहर का। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने एक सवाल दिया था लेकिन आपके विधान सभा सचिवालय ने वह सवाल रूल्ज और प्रौसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 46 की क्लाज-6 के तहत डिसअलाऊ करा दिया है। मैंने इस क्लाज को पढ़ा भी, लेकिन मैं समझ नहीं सका हूं कि वह डिसअलाऊ क्यों कर दिया। मुझे बोलने का मौका मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो दस साल पहले रोटेशन सिस्टम था उसके 3 सैट बना दिए गए और 7-7 दिन के लिए पानी की व्यवस्था कर दी गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसान की पानी की बारी होती है, उनके खेतों में एक बार में पानी नहीं आता है। पहले यह स्थिति थी कि अगर एक बार में पानी नहीं मिले तो दूसरे बार में मिल जाता था। अगर नहर में पानी ज्यादा होता था तो पूरे महीने भी पानी मिल जाता था। लेकिन अब स्थिति बहुत खराब है। हमारे साथ इस मामले में भेदभाव हुआ है। कुछ सर्कल की नहरों में तो पुराना सिस्टम लागू है लेकिन हमारे यहां नया सिस्टम लागू है। कुछ नहरों में तो पानी 15-15 दिन तक चलता है लेकिन हमारे यहां एक सप्ताह भी पानी नहीं चलता है। इसलिए सिस्टम यह होना चाहिए कि नहरों का पानी 15-15 दिन रोटेशन के हिसाब से चले। मैं कैथल सर्कल, हिसार-और नरवाना एरिया की बात कर रहा हूं। आप बेशक रिकार्ड से पता करवा लें। अगर रोटेशन से किसानों के खेतों को पानी दिया जाएगा तो उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। गुंदड़ी से सुदखान डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। वहां 191 आर.डी. पर कैथल के एक्सियन का कंट्रोल है तथा उसके 15 आउटलैट हैं। नरवाना के एक्सियन के 75 आउटलैट हैं। मैं यह चाहता हूं कि जिस एक्सियन के पास 80 प्रतिशत पानी की युटिलाईजेशन का कार्य हो, उसका कंट्रोल होना चाहिए। मैंने नहर के अधिकारियों से भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने टेल पर पानी न पहुंचने की समस्या के बारे में कहा था कि हमारे डिवीजन का कंट्रोल हमें मिल जाएगा तो किसानों की टेल पर पानी न पहुंचने की समस्या हल हो जाएगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो समस्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से ही हल हो सकती है, जिसमें कोई और खर्चा भी नहीं पड़ता है, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उसको हल किया जाना चाहिए।

श्री बंसी लाल : यह जो कंट्रोल वाली बात कह रहे हैं, इसके बारे में एक चिट्ठी लिखकर के हमें दे दें, उसको हम लागू कर देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : दूसरी बात सिंचाई विभाग पर निगाह मारने की है। उपाध्यक्ष महोदय, इनको 1600 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक या विश्व की दूसरी ऐजेन्सीज से मिला है। उस पैसे की बहुत वेस्टेज हो रही है। सिंचाई विभाग में बहुत हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप कभी उसके खर्चे की फिगर्ज देखें तो पता चलेगा कि 72 प्रतिशत बजट उनकी तनख्वाहों तथा दूसरे कामों में चला जाता है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग पब्लिक की आंखों में धूल झौंक रहे हैं। मैं एक महीना पहले कैथल गया था। कैथल का कैनाल रैस्ट हाऊस डी०सी० के कब्जे में है। जब से कैथल जिला बना है, तब से वहां पर डी.सी. का निवास है। मैंने वहां के एस.ई. से पूछा कि क्या यहां पर कोई बैठने की जगह है तो कहने लगे कि हां हमारा कमेटी रूम है। मैंने कहा कि वहीं चलते हैं। मैं वहां गया तो देखा कि रिकार्ड के मुताबिक तो वह कैनाल रैस्ट हाउस नहीं है तथा कान्फ्रैंस हाल है। लेकिन वास्तव में रैस्ट हाउस है। सिर्फ नाम का कान्फ्रैंस हाल लिखा हुआ है ताकि पब्लिक के किसी आदमी को मौका न मिल सके कि वहां पर ठहर जाए। अपने निजी कामों के लिए तो बहुत पैसा इनके पास है, कोठियां भी बना लेते हैं लेकिन नहरों को पक्का करने की जब बात आती है तो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

कि सिंचाई विभाग का 72 प्रतिशत बजट सिर्फ तनख्वाहों पर जाता है। लेकिन जिस चीज की ज्यादा जरूरत है जैसे जो खालें टूट गई हैं, उनको पक्का करने का काम तक नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय तो नबार्ड से भिवानी में खालें पक्के करने के लिए 60 करोड़ रू० ले गए, लेकिन हमें कौन पैसा देगा ?

श्री बंसी लाल : वह सारा पैसा भिवानी में खर्च नहीं होगा। जो 60 करोड़ रूपया है इसके बारे में मैंने कल परसों भी बताया था। उपाध्यक्ष महोदय, वह पैसा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्ज के लिए है जिसमें भिवानी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम भी है, लौहारू लिफ्ट इरीगेशन स्कीम भी है और जूई लिफ्ट इरीगेशन स्कीम भी है। इसमें सबसे बड़ी स्कीम जे०एल०एन० की है उसके लिए हम सबसे ज्यादा पैसा देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन मेरी फरियाद यह है कि जिन नहरों की टेल पर पूरा पानी नहीं आता है वहां पर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं। उन नहरों की टेल पर पानी न आने की वजह से वहां के किसानों के खाल अभी तक कच्चे पड़े हैं।

श्री बंसीलाल : ऐसा है कि स्टेट में जितनी टेल हैं उनमें से सिर्फ 62 टेल ऐसी हैं जिनमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा है उनमें भी हम 30 जून तक पूरा पानी पहुंचा देंगे। सबसे ज्यादा जिस इलाके की टेल पर पानी नहीं पहुंचा है वह बहादुरगढ़ का इलाका है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : जो 1600 करोड़ रूपया हरियाणा सरकार को विश्व की ऐजेंसियों से या वर्ल्ड बैंक से या आई०एम०एफ० से मिला है।

श्री बंसी लाल : वह 1858 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट है उसमें से आधा पैसा हरियाणा गवर्नमैंट का है और आधा वर्ल्ड बैंक का लोन है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अगर वह प्रोजैक्ट 1800 करोड़ रूपए का है तो यह ठीक बात है कि उसमें से 900 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का होगा। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि उस पैसे का इस्तेमाल आप ठीक से कराएं ताकि हरियाणा के किसानों के खेतों में पानी देने की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। उसमें अगर आप दो तीन प्रायर्टीज ले लें तो ठीक रहेगा। मैंने देखा है कि वाटर मैनेजमैंट के नाम से पैसा आया है वह स्प्रिंकलर सैटस के लिए लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के लिए और खालें पक्का करने के लिए है। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे पर हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा का यह सदन और हरियाणा के सारे राजनैतिक दल इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए चाहे हमें उसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े। चाहे कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े सारा हरियाणा प्रदेश उसके लिए तैयार है। मुख्य मंत्री जी मेरे पास आंकड़े हैं, हम एस०वाई०एल० नहर के एग्जिसिटंग वाटर में से जो 1.80 एम०ए०एफ० पानी अपने एग्जिस्टिंग चैनल्ज से कैरी करते थे आज उन चैनल्ज की यह हालत हो गई है कि उनकी सिर्फ बन एम०ए०एफ० पानी कैरी करने की कैपेसिटी रह गई है। उनके अन्दर सिल्टिंग की वजह से 0.80 एम०ए०एफ० पानी कम कैरी होता है। पंजाब की टैरीटरी में जहां से हमारी नहर आती है उसके अन्दर विडीसाइडज होने के कारण और नहर के टूटी फूटी होने के कारण आज उसकी एडीशनल पानी की कैरिंग कैपेसिटी घट कर आधी रह गई है। हम आज 0.80 एम०ए०एफ० पानी नहीं ले सकते हैं। आज हमारी यह भी प्रायर्टी होनी चाहिए कि पंजाब को उसकी सफाई कराने के लिए मजबूर किया जाए।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, उस बारे में हमने पंजाब से बात कर ली है उनको उसकी सफाई के लिए पांच करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उनको सवा दो या अढ़ाई करोड़ रुपया दिया जा चुका है। उसकी कैपेसिटी हम जल्दी बढ़वा रहे हैं। हमने अपने औफिसर्ज की भी ड्यूटी लगा रखी है वह उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। हमने उसका काम शुरू करवा रखा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी घग्गर, टांगरी और मारकण्डा नदियों पर बैराज बनाने की स्कीम थी उसको रिवाईज करने की कोशिश करें उससे हरियाणा के लोगों को बड़ी भारी राहत मिलेगी। मैंने पहले भी सदन में यह कहा था कि इन तीनों रिवलैटस पर बैराज बना दिए जाएं तो जो दो महीने का बारिश का पानी बह कर बेकार चला जाता है उस पानी की इन तीनों बैराज को बनाने से हम सारे हरियाणा की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हमारी फसलों की पैदावार ज्यादा हो सकती है। आज वह इलाका जिस इलाके से खुद मुख्य मंत्री जी आते हैं वहां पर दो तिहाई वाटर ब्रैकिश है। उस इलाके की पानी की भूख मिटाई जा सकती है।आज हरियाणा के 8-10 ऐसे जिले हैं जहां पर किसान साल में सिर्फ एक फसल लेता है। रोहतक का इलाका है सोनीपत का इलाका है, जीन्द का इलाका है, भिवानी का इलाका है, नारनौल का इलाका है, महेन्द्रगढ़ का इलाका है और रिवाड़ी का इलाका है गुड़गांव का इलाका है। गुड़गांव में मेव भाई बसते हैं। वे सिर्फ सरसों के अलावा और कोई फसल नहीं ले पाते। वहां पर बहुत गरीबी है।

श्री बंसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पुरानी स्कीमों को रिवाईज करो। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम उन स्कीमों को रिवाईज करने के बारे में सोच रहे हैं। पूरे हरियाणा में अन्डर ग्राउंड वाटर कितना है, रीवर्ज का वाटर कितना है, इन सब के लिए हम एक स्कीम बना रहे हैं। कुछ अर्से के बाद हम इन कामों के लिए ग्लोबल टेन्डर मंगाएंगे हम यह पता करवायेंगे कि कहां पर कितना पानी है और उस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है जो ग्लोबल टैंडर की कंडीशंज होंगी उस को अगर कोई सदस्य साथी देखना चाहेगा तो उसको हम दिखा देंगे। हम परमानेंट समाधान करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अगर ये सारी जरूरतें पूरी हो जाएं तो समस्याओं का समाधान हो जायेगा। मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो डिच ड्रेन बनाई हुई हैं वह भी किसानों पर एक तरह से अत्याचार है जो नहरें पक्की हुई हैं उनके दोनों तरफ 3-3, 4-4 किल्लों की लम्बाई तक जमीन खराब हो जाती है क्योंकि पक्की नहरों के साथ साथ डिच ड्रेनें भी बना रखी हैं। इंजीनियर्ज ने डिच ड्रेन बनाने के लिए आपको भी कहा होगा, मैं कहता हूं कि डिच ड्रेनें नहीं बनाई जानी चाहिए। इन्जीनियर्ज को आप कहें कि जहां पर पक्की नहरें बनी हैं या बनाई जाएंगी वहां पर डिच ड्रेनें नहीं बनाई जाएंगी। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे इन्जीनियर्ज की टैक्नोलोजी की कमी की वजह से नहरें ठीक तरह से पक्की नहीं हो पा रही। यदि नहरें ठीक ढंग से पक्की हों तो फिर यह वाटर लोगिंग नहीं हो पायेगी। हमारा जो वर्कमैन है, जो हमारे काम की क्वालिटी है, उसमें कहीं न कहीं कमी है। पी०डब्ल्यू०डी० की ही बात ले लें। पी०डब्ल्यू०डी० से कोई काम करा ले तो पी०डब्ल्यू०डी वाले 14 परसेंट डिपार्टमेंटल चार्जिज ले लेते हैं। 14 परसेंट ठेकेदार को जे०ई०,एस०डी०ओ०, एक्सीयन, और एस०ई०, चीफ और मंत्री जी तक को कमीशन देना पड़ता है, यानि 14 परसेंट का यह सलैब बना हुआ है। फिर 14 परसेंट ठेकेदार को भी चाहिए । यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि 42 परसेन्ट पैसा तो यूं ही खूह खाते में चला जाता है। अब जो 58 परसेंट बचता है उसमें से कितना पैसा जाता होगा, आप अन्दाजा लगा सकते हैं। इसके लिए मैं सुझाव देता हूं कि आप कोई कार्पोरेशन स्थापित कीजिए, इस काम के लिए 1 जैसे नैशनल बिलडर्ज के नाम से

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

और एनकोन के नाम से बहुत बड़ी बड़ी कम्पनीज काम कर रही हैं। उसी ढंग की कार्पोरेशन आप यहां बना कर काम करवा सकते हैं। हमारे यहां की जो टूरिज्म कार्पोरेशन है, उसकी कंसलटेंसी दूसरी स्टेटस की टूरिजम कार्पोरेशंज लेती है, इसी प्रकार की आप कोई हैवी कार्पोरेशन स्थापित कीजिए ताकि यहां के लोगों को रोजगार भी मिल सके और आपका काम भी हो सके। जैसे यूनिटैक है, कोन्टीनैंटल है। इनसे आप सड़क बनवाइये, आप इस तरह की कार्पोरेशन बनाएंगे तो हजारों लड़कों को रोजगार मिलेगा। उन कार्पोरेशंज को आप बड़े बड़े काम ट्रांसफर कीजिए। आपने एक छोटा सा तुजर्बा किया था लेबर फैडरेशन को बना कर। यह 25-30 साल से काम कर रही है। वह कुछ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी कार्पोरेशन बनाएंगे उसमें उतने ही ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे बाद में लायब्लिटीज ही बन बैठें। उनको फ्लोट इक्विटी देने का प्रावधान करें बाकी का काम उनके ऊपर ही छोड़ दें, कारपोरेशन्ज में ऐसा न हो कि वह गवर्नमैंट का एक डिपार्टमैंट ही बन कर रह जाए। उससे हरियाणा में क्वालिटी वर्क भी इम्प्रूव होगा। उससे हम वित्तीय साधन पैदा कर के वह पैसा हरियाणा प्रदेश की डिवैल्पमैंट पर लगा सकते है। उपाध्यक्ष महोदय, राम बिलास शर्मा जी जब सवालों का जबाव दे रहे थे मैने एक बात कही थी। आम तौर पर यह कहा जाता है कि मिडिल से दसवीं तक या दसवीं के स्कूल को जमा दो तक अपग्रेड करके उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने की मांग की जाती है या कहा जाता है कि जमा दो स्कूल है उसको कालेज बना दो। इस बारे मेरा एक सुझाव है कि दस जमा दो की बजाए डिग्री कॉलेज मांगने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा की डिवैल्पमैंट के लिए हमें अपने शिक्षा के नज़रिये को बदलने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय को शिक्षा के बारे में अपना नज़रिया बदलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सैंबियत रूस दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश था और दुनियां की एक ताकत था। करीब 12 साल पहले मैं वहां पर लगभग एक महीना घूम कर आया हूं। मैंने वहां के मास्को और कुछ अन्य बड़े शहरों में तथा देश के रिमोट ऐरिया के स्कूलों को भी देखा था। (विघ्न) वहां पर 12 किलोमीटर के एरिया में एक कोआप्रेटिव फार्म में एक स्कूल को देखने के लिए भी मैं गया था। वहां के स्कूल के बच्चों को देख कर मैं काफी प्रभावित हुआ। उन बच्चों के चलने फिरने, उठने-बैठने और बातचीत करने के तरीके से साफ पता चलता था कि यह गांव के बच्चे हैं या यह शहर के पढ़ने वाले बच्चे हैं। (विघ्न) यह मजाक का विषय नहीं है इसलिए इसे सीरियसली लेना चाहिए। बच्चे चाहे शहर के पढ़ने वाले हैं अथवा गांव के, उन्हें एक परोपर एनवायर्नमैंट मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री श्री राम बिलास शर्मा जी से एक बात कहना चाहता हूं कि वे स्वंय अपनी पार्टी में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गांव की बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। वैसे तो उनकी पार्टी बी०जे०पी० शहरों की पार्टी है लेकिन वे गांव की भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं इसलिए उन्हें गांव के स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है यदि सरकार इसको स्वीकार करे तो जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े-लिखे है उन सभी को सरकार नौकरियों में तो नहीं लगा सकती है लेकिन उनको स्व-रोजगार देने के लिए सरकार एक योजना बनाए। आज कहने को तो ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक स्कूल्ज़ खुले हुए हैं और मां-बाप अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए भेजते भी हैं। वे स्कूल बच्चों को टाई वैगरह लगा कर तो स्कूलों में बिठाते हैं और नाक पोंछने के लिए लोग बच्चों को रूमाल भी दे देते हैं लेकिन जिन स्कूलों में वे बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें पढ़ने का एटमॉसफीयर नहीं होता है। केवल बैल्ट टाई लगाने से या बच्चों को रिक्शा पर स्कूल भेजने मात्र से उनमें शहरों के मुताबिक पढ़ने का एनवायर्नमैंट नहीं मिलता है। सरकार एक कारपोरेशन स्थापित करें। हजारों ऐसे पढ़े-लिखे नौजवान हैं जो बी०ए०, बी०ए०बी०एड० या

एम०ए०एम०एड० या एम०ए०बी०एड० किये हुए हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। अगर सरकार उनको सहायता दे तो उनका इस्तेमाल हो सकता है। वे अपने साधनों से स्कूल नहीं खोल सकते हैं सरकार उनको स्कूल खोलने के लिए साधन उपलब्ध करवाए, उन स्कूलों में बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायर्नमैंट पैदा किया जाए जिससे ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को राईज कर सके। शहरी बच्चों के साथ कम्पीट करने का उनको भी बराबर का मौका मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात उद्योगों की बाबत भी कहना चाहता हूं। हरियाणा की धरती पर उद्योग लगाने के लिए कई उद्योगपति आते हैं। बहुत से उद्योग दिल्ली में लगे हुए हैं और उद्योगों के हिसाब से दिल्ली छोटी पड़ती जा रही है। बाहर से अनेकों मल्टीनेशनल कम्पनीज यहां पर आ रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बम्बई को देश की इकोनोमी कैपिटल कहा जाता था लेकिन आज दिल्ली उससे भी आगे निकल गई है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप उसके लिए कंसलटेंसी सिस्टम बनाएं जो किसान अपनी जमीन 50 लाख, एक करोड़ और दो करोड़ में बेचता है या किसान की जमीन एक्वायर की जाती है उसको उद्योग लगाने का मौका मिले। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी व्यवस्था के लिए कंसलटेंसी सिस्टम बनाने की जरूरत हैं तो वह जरूर बनाया जाए। यदि वहां पर कोई भी गांव का आदमी आए और वह वहां पर आकर यह कहे कि मैं उद्योग स्थापित करना चाहता हूं तो उसको वहां सभी सुविधाएं मिल सके। मैं यह चाहूंगा कि उनको भी उद्योग लगाने का मौका मिले। उस किसान की जमीन तो चली गई अगर उसे पैसे को लगाने का सही तरीका न मिले तो उसका वह पैसा भी चला जाएगा और वह किसान एक लेबर बन कर रह जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को कंसलेटैंसी सुविधा देने का प्रावधान करना चाहिए। इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी क्षेत्र को बूस्ट करने का प्रावधान नहीं है, यह बजट बिल्कुल नीरस है इसलिए मैं यह कट-मोशन लेकर आया हूं और मुझे इस पर वोटिंग का अधिकार है तथा मैं यह चाहता हूं कि इसको वोटिंग के लिए लगाया जाए। (विघ्न)

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नम्बर 17 जो कृषि से संबधित है, पर चर्चा करना चाहूंगा। यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर इस प्रदेश का किसान सम्पन्न और समृद्ध होगा तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश समृद्ध हो सकता है। इस प्रदेश में खुशहाली आ सकती है। आज इस प्रदेश में कृषि के लिए बहुत से साधनों की आवश्यकता है। इसके लिए आज बहुत से साधन जुटाने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर जो बजट पेश हुआ है उसमें इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है जिससे इस प्रदेश के किसानों को कोई राहत मिलने वाली हो, किसानों को कोई सबसिडी दी गई हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस पर विचार करें कि आज किसान 12.00 बजे को किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। किसानों को आज पानी की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं।

श्री जय सिंह राणा : मैं कृषि वाली डिमांड पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, लेकिन आप दस मिनट में ही अपनी बात कंक्लूड करें।

श्री जय सिंह राणा : ठीक है जी, जैसा आप कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा क्योंकि यह हमारी मजबूरी है। स्पीकर साहब, सरकार को सर्वप्रथम किसानों के लिए पानी और बिजली का प्रबन्ध करना बहुत ही जरूरी है। आज प्रदेश में बिजली की बड़ी भारी कमी है। बिजली की कमी का प्रभाव सीधा खेतों पर पड़ता है। लगता है कि निकट भविष्य में भी सरकार इस समस्या को दूर नहीं कर सकती। मैं सरकार को इसके लिए कहूंगा, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, कि जो किसान अपने खेतों को सिंचित करने के

[श्री जय सिंह राणा]

लिए अपने जैनरेटर सैट लगा सकते हैं और जैनरेटर सैट से बिजली पैदा करके अपने ट्यूबवैल्ज चला कर वे अपनी खेती को अच्छी बना सकते हैं तो ऐसे किसानों को सरकार को जैनरेटर सैट्स पर उद्योगपति की तरह सबसिडी देनी चाहिए ताकि किसान बिजली पैदा करने के लिए अपने जैनरेटर सैट्स लगा सकें।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर साहब, जहां पर किसानों के पास बिजली के कनैक्शंज नहीं है वहां पर हम किसानों को जैनरेटर सैट पर सबसिडी देते हैं। अगर कोई किसान यह खरीदना चाहता हैं तो उसको यह सबसिडी हरियाणा ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के माध्यम से दी जाती है। कितने परसैंट तक दी जाती है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है लेकिन सबसिडी जरूर दी जाती है।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि सबसिडी दी जाती है ये कह रहे हैं कि जहां पर बिजली के कनैक्शंज नहीं है वहां पर यह सबसिडी दी जाती है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर बिजली के कनैक्शंज भी हों तो आपको वहां के किसानों को भी जैनरेटर सैट पर सबसिडी देनी चाहिए ताकि किसान बिजली के बगैर अपने ट्यूबवैल्ज की मोटरें चला सकें। आज उनको बिजली न मिलने की वजह से उनकी मोटरें नहीं चल पा रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, उनके ट्यूबवैल्ज की मोटर्ज को चलाने के लिए जैनरेटर सैट्स पर सबसिडी देना जरूरी है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। किसानों को उन पर सबसिडी देनी चाहिए ताकि किसान जैनरेटर सैट्स खरीद कर लगा सकें। इसके अलावा जहां तक मेरे क्षेत्र करनाल और कुरूक्षेत्र का सवाल है, वह धान उत्पादक क्षेत्र है और यह क्षेत्र बहुत ही अच्छी जीरी पैदा करता है। आज वहां पर जीरी को पैदा करने के लिए बहुत पानी की जरूरत है। इसलिए मेरे एरिये में खास तौर पर जैनरेटर सैटस पर सबसिडी देने का प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह से नहरी पानी की बात है। नहरी पानी किसानों के लिए सबसे सस्ता पानी है। किसान उस पानी को बड़े चाव से लेना भी चाहता है। वह बड़े चाव से उसका इस्तेमाल करता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में जो सिरसा नहर से जो चौटंग नाला निकलता है वह बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करता है लेकिन वहां पर सिर्फ दो या अढ़ाई महीने ही पैडी सीजन में वह नहर चलती है। नहर केवल जुलाई में पानी देती है जबकि लोग मई में ही जीरी लगाना शुरू कर देते हैं। अगर दो महीने बाद पानी मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि, यह पानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं जीरी के लिए मई या जून के फर्स्ट बीक में से चौटंग नाले में पानी को छोडना शुरू करें जिससे लोग जीरी की फसल सही समय पर उगा सकें।इसी तरह से कृषि की जो समस्या है मैंने इस बारे में पहले भी अनुरोध किया था लेकिन मेरी बात बीच में काट दी गई। जैसे हमारे यहां की फसल की बात है। हमारा गन्ना आज भी बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में खड़ा है। शुगर मिल उस गन्ने को नहीं ले रहे हैं। किसानों को मजबूरन अपने गन्ने को कोल्हूओं में पेलना पड़ रहा है। इस दफा पहली बार किसान का गन्ना यू०पी० में जा रहा है। पहले हमेशा गन्ना यू०पी० से हरियाणा में आता था। इस बार यू०पी० के किसानों ने जमुना के बार्डर पर हरियाणा के किसानों को यू०पी० में गन्ना ले जाने से रोका। करनाल जिले के भादसों गांव में पिकाडली शुगर मिल है वहां पर किसान को गन्ने का रेट 62 रूपये क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं। जिला करनाल के डी.सी. ने फैसला किया और इससे किसान नाराज हो कर आ गए। किसानों ने उनकी बात नहीं सुनी। किसानों से कहा कि गन्ने का पैसा एक साल बाद दिया जाएगा और वह भी तीन किश्तों में दिया जाएगा। यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्या डी०सी० का यह फैसला उचित है ? मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों के हितों की रक्षा करते हुए गन्ने का जो निर्धारित मूल्य है वह किसान को दिलवाया जाए यह सरकार का फर्ज बनता है। स्पीकर सर, इसी

तरह से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर ये सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है तो सरकार को चाहिए कि पड़ौसी राज्य पंजाब की तरह इस प्रदेश के किसान को भी बिजली और नहर का पानी मुफ्त मुहैया करवाए।

श्री अध्यक्ष : पिछले साल जब आप यहां बैठे थे तब आपके दिमाग में यह बात नहीं आई ?

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, पंजाब ने अब यह फैसला किया है इसलिए यह बात आई है।

श्री अध्यक्ष : हर बात में हम पंजाब को फौलो थोड़े ही करेंगे। We are not to follow Punjab.

श्री जय सिंह राणा : कृषि के जो यंत्र हैं, वे सभी टैक्स से मुक्त होने चाहिए उन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए चाहे वह ट्रैक्टर का टायर है या बुग्गी का टायर है। कृषि के सभी यंत्र टैक्स से मुक्त होने चाहिए। धूप बत्ती पर टैक्स माफ करने से लोगों को कोई फायदा नहीं हो सकता। किसान जो ईमानदारी से रोटी कमाता है उसे तो कृषि के यंत्रों से ही लाभ होता है। मैं मांग नं० 10 के बारे में जो जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है इसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राणा जी आपको बोलते हुए साढ़े आठ मिनट हो चुके हैं।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, पीने के पानी की हर जीव को जरूरत है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ये भी ओपोजिशन के माननीय सदस्य हैं इनको बोलने दीजिए।

श्री जयसिंह राणा : स्पीकर साहब, यह जो जन स्वास्थ्य विभाग की बात मैं कहना चाहता हूं यह बहुत जरूरी है क्योंकि पीने के पानी की जो बात है वह हर जीव से जुड़ी हुई है। आज भी यह सरकार कहती है कि हमने हर गांव में पीने के लिए पानी पहुंचा दिया है। लेकिन ऐसे गांवों के नाम मंत्री जी को बताना चाहता हूं जिन गावों में आज तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है। मेरे हल्के नीलोखेड़ी में जिन गावों में पानी नहीं पहुंचा है वे हैं बुडेड़ा, भागपुर, पछताना और निगदू। इनमें से निगदू गांव तो ऐसा है जिसकी आबादी दस हजार से भी ज्यादा है। इस गांव में जो ट्यूबवैल लगा हुआ है वह छः महीने से खराब पड़ा है। मैंने कई बार एक्सीएन और एस०डी०ओ० से कहा है किन्तु उस बारे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं उनके सामने पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : आपने अपनी सरकार देखी, चौधरी देवीलाल जी की सरकार देखी और चौधरी भजन लाल जी की सरकार भी देखी। फिर भी आप इस क्षेत्र में पानी का इंतजाम क्यों नहीं करवा पाये। हम तो पानी का इंतजाम जरूर करेंगे।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : हम पानी इस इलाके में जरूर पहुंचायेंगे।

श्री अध्यक्ष : राणा साहब, आप अपनी सरकार से तो नहीं करवा पाये लेकिन अब मंत्री जी ने इस बारे आश्वासन दे दिया है।

श्री जयसिंह राणा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल से कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार अपने कार्यकाल में सभी समस्याओं को दूर नहीं कर सकती। हमारी सरकार ने बहुत से गांवों में पीने का पानी पहुंचाया होगा और कुछ रह भी गये होंगे तो इनकी सरकार ने भी तो कुछ करना है। जो लोगों की भलाई के अच्छे काम हैं, वह सरकार का फर्ज बनता है कि वे काम करने चाहियें। मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्य को अवश्य करेंगे। इसी तरह से सिंचाई और बिजली की बात है। (घंटी)

[श्री जय सिंह राणा]
सर, मैं एक मिनट में खत्म करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट में कंक्लूड करें।

श्री जयसिंह राणा : स्पीकर सर, बिजली का जहां तक सवाल है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिजली इस प्रदेश के लोगों की बड़ी भारी समस्या है और प्रदेश के हर आदमी को बिजली की चिन्ता है। क्योंकि गेहूं निकालने के लिए ट्रैशर्ज को बिजली चाहिए। उसके बाद जीरी निकालने के लिए किसानों को बिजली चाहिए। किसानों को चिन्ता है कि वे फसल बोये या न बोयें, बिजली के बगैर गुजारा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ बिजली के निजीकरण की बात हमेशा आती हैं। हम बिजली के निजीकरण के हक में नहीं हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है तथा हाउस में कहा गया कि 4 जिलों, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और करनाल में बिजली का निजीकरण होने जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूगां, मुख्यमंत्री इस समय हाउस में नहीं बैठे हैं, कि भिवानी, महेन्द्रगढ़, सिरसा और हिसार में बिजली का निजीकरण करें ताकि लोगों का संदेह दूर हो सके। धन्यवाद।

श्री चन्द्र मोहन (कालका) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सारा सदन जानता है 12 मार्च को वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट पेश किया। जब वे बजट पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके मन पर बहुत भारी बोझ हो। बड़ी मजबूरी में ये बजट पढ़ रहे थे क्योंकि मौजूदा सरकार लोगों को जो वायदे करके सत्ता में आई थी कि विकास के कार्य करेंगे। उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन इस बजट को पढ़कर तथा 3 दिन से जो बहस हो रही है, उसको सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि विकास नाम की कोई चीज हरियाणा प्रदेश में होने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 11 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि अर्बन डिवैल्पमैंट से रिलेटिड है। जैसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं इस में सिर्फ 37,70,68,000 रु० रखे गए हैं जिसमें से विकास कार्य में सिर्फ 18.73 करोड़ रु० ही खर्च होने हैं। इसमें से 10 करोड़ रु० दिल्ली के आस-पास सैटलाइट नगरों के विकास के लिए और 3 करोड़ 65 लाख रु० गंदी बस्तियों के सुधार के लिए रखे गए हैं। नगरपालिकाओं के लिए 4 करोड़ 15 लाख रु० रखे गए हैं। अतः आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शहरों का विकास होने वाला नहीं है। सरकार क्या करने जा रही है ? हरियाणा में 82 नगरपालिकाएं हैं तथा यह 4 करोड़ 15 लाख रु० किस-किस के पल्ले पड़ेगा ? जहां तक गंदी बस्तियों के सुधार की बात है, इसमें 3 करोड़ 65 लाख रु० रखे गए हैं। जो हमारे बुजुर्ग और भाई इन गंदी बस्तियों में रहते हैं, जिससे इनकी सेहत खराब होती है। इनमें रहकर वे क्या तो पढ़ाई कर सकेंगे तथा इससे क्या देश और हरियाणा का विकास हो सकेगा ? इसलिए यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इसी प्रकार से हरियाणा में जितनी भी नगरपालिकाएं नकारा हैं, जहां पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, जहां पर पीने के पानी की तथा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार से हुड्डा ने गरीब लोगों को प्लाट देने की जो प्लान बनाई थी, वह बहुत बढ़िया थी लेकिन अब इस सरकार ने हुड्डा के प्लाटों की भी ओक्शन शुरू कर दी है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से गरीब आदमी कैसे प्लाट खरीद पाएगा। एक तरफ तो आज प्लाटों की ओक्शन कर रहे हैं दूसरी तरफ गरीब आदमी जो पंचकूला की आजाद नगर वगैरह कालोनियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन सब को नोटिस आ गए हैं कि वे यहां से शिफ्ट करें। अध्यक्ष महोदय, वे गरीब आदमी कहां जाएंगे ? इस बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। पंचकूला के विकास में इन गरीब आदमियों का विशेष योगदान रहा है। इसलिए इन

गरीब आदमियों को उसी प्रकार से जगह की आल्ट्रनेटिव अलॉटमैंट की जाए जिस प्रकार से चौ0 भजन लाल सरकार ने इंदिरा कालोनी बना कर की थी। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जो हमारे भाई वहां पर रहते हैं, उन्होंने पैसा जमा कर रखा है, उन्हें प्लाटों के अलाटमैंट लैटर मिलने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हुड्डा के बारे में तथा टाउन एंड कंटरी प्लानिंग के बारे में नोटिस आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई अपनी दुकान चला रहा है, किसी का घर है, कोई 15 साल से वहां पर काम कर रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना यह है कि नो प्रोफिट नो लौस बेसिज़ पर उनके लिए कोई ऑल्ट्रनेटिव प्रबंध किया जाए पिछली सरकार के समय में इस बारे में फाईल चली थी, उस समय वह फैसला हो पाता उससे पहले आपकी सरकार आ गई। मेरी गुजारिश है कि इस बारे कोई न कोई प्रबंध जल्दी करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पंचकूला, गुड़गांव, फरीदाबाद और हिसार इन चार जोन में जब कोई आदमी मकान बनाता है और वह अगर हुडा के रूल्ज की वायलेशन करता है तो इन चारों जोन में कम्पाउंड फीस लगाने के अलग अलग रेट हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस बारे में सबको एक नजर से देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, समस्याएं तो पंचकूला हल्के में बहुत हैं लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस सरकार के सभी मंत्रीगण का एक ही जवाब है कि जब फण्ड अवेलेबल होंगे तब यह काम करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है।इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, मैं डिमांड नंबर 5,8,11 और 16 के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 5 के बारे में बोलूंगा जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट से रिलेटिड है। स्पीकर साहब, जो बजट पेश हुआ है उसमें इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यह सरकार सेल्ज टैक्स से 1618.95 करोड़ रूपया इकट्ठा करेगी, चार करोड़ रूपया एक्साइज से इकट्ठा करेगी और 298.80 करोड़ रुपया गुड्स टैक्स से इक्ट्ठा करेगी। मैं एक बात इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जो गुड्स टैक्स का मामला है उसके बारे में आप ध्यान दें। इन्होंने जो ट्रक पास कर रखा है वह तकरीबन 9 टन लोड का पास कर रखा है। मैनुफैक्चर्र सारे हिन्दुस्तान में अपना माल सप्लाई करते हैं सिर्फ हरियाणा में सप्लाई नहीं करते। हिन्दुस्तान की बाकी स्टेटस ने किसी ने 10 टन, किसी ने 11 और किसी ने 13 टन लोड पास कर रखा है लेकिन हरियाणा में सिर्फ 9 टन लोड अलाउड है। उसका नतीजा यह है कि यदि कोई ट्रक जयपुर से माल लाद कर आता है तो उसको तीन हज़ार रुपया किराया मिलता है तो हरियाणा के अन्दर उससे 1500 रुपये ओवर लोड के हिसाब से ले लेते हैं। इसके अलावा एक मजेदार बात यह भी है कि यह कोई देखने वाला नहीं है कि किसी ट्रक पर 900 रुपये जुर्माना ओवर लोड का लगा देते हैं, और किसी पर 200 रुपए लगा देते हैं उनकी मर्जी है जिसको चाहें उस ट्रक को छोड़ देते हैं और मर्जी आए किसी ट्रक पर ओवर लोड का जुर्माना लगा देते हैं। रसीद पर भी यह नहीं लिखा जाता कि उस ट्रक में कितना ओवर लोड है और उसका कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया है। इसके कारण आज हरियाणा के अन्दर गुडस ट्रांस्पोर्ट तकरीबन तकरीबन बंद होती जा रही है। ट्रक हरियाणा के अन्दर से हो कर निकलना बंद हो गये हैं वह राजस्थान से सीधे यू०पी० चले जाते हैं हरियाणा को पास नहीं करते। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है आप टैक्स लगाएं बगैर टैक्स लगाए गुजारा भी नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि फलां चीज पर टैक्स माफ कर दो, फलां चीज पर माफ कर दो। एक डिवैल्पिंग स्टेट के लिए अगर सोर्सिज नहीं आएंगे तो उसके विकास के काम कैसे होंगे? हमें लोगों को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि हम आपके डिवैल्पमैंट के काम क्यों नहीं कर पाए? मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि आप किसी चीज पर टैक्स माफ कर दें। यदि आप किसी चीज पर टैक्स माफ करते हैं तो यह आपकी मर्जी है। मैं कहना

[श्री धर्मबीर गाबा]

चाहता हूँ कि टैक्स लगाने का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ट्रक से ओवर लोड का 1500 रुपया ले लिया जाता है और किसी ट्रक से कोई पैसा नहीं लिया जाता। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेहरबानी करके इसको रीस्ट्रकचर कीजिए। सबके लिए आसान काम हो जाएगा किसी को कोई गिलाशिकवा नहीं होगा। अब मैं इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा। इंडस्ट्रीज को डिवैल्प करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। स्पीकर साहब, आज गुड़गांव के अन्दर जितनी तरक्की हुई है वह इंडस्ट्रीज लगने के कारण हुई है। ये सारी हमारी सरकार के वक्त में लगीं थी। आपने कोई इण्डस्ट्री परमोट की हो या ऐसी कोई प्लानिंग इस फाईनैंस बिल के अन्दर की हो तो बताएं कि आप इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं और गुड़गावां की इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह बात सही है हमने सोचा था कि बहुत सारी इण्डस्ट्रीज जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से दिल्ली से निकलेंगी वे गुड़गांव में या फरीदाबाद में आएंगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यूथ को उनमें एम्पलायमेंट मिल जाएगी और हमारी स्टेट में पैसा बाहर से आयेगा। लोगो की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक इन्डस्ट्रीयल स्टेट हमने पंचकूला-बरवाला के साथ डिवैल्प करना था। आज तक कोई बता दे कि वहां पर कोई इन्डस्ट्री लगाई गई हो। इसी प्रकार से कुण्डली के अन्दर भी कुछ नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि हम गुड़गांव के अन्दर बेहतरीन इण्डस्ट्रीज लेकर आये थे। हमने शोर सुना था कि आप गुड़गांव को एक माडर्न इण्डस्ट्रीयल टाउन बनाने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी क्या प्रोग्रैस है। इस बजट में इस के बारे में कोई जिकर नहीं है। ये कहते हैं कि हम काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कब करेंगे और क्या करेंगे। कौन कौन सी एस्टेट डिवैल्प होंगी। क्या जापानी टैक्नोलॉजी अपनाएंगे या और कोई बाहर से किसी इण्डस्ट्रीज के बारे में कोई ऐसी स्कीम आपने बनाई है जिससे कि हम यह कह सकें कि हमारी स्टेट में कोई डिवैल्पमेंट हो रही है। आप मेहरबानी करके स्टेट की डिवैल्पमेंट के लिए कुछ काम करें। मैं फखर के साथ कहना चाहता हूँ कि हमने इण्डस्ट्रीज की तरक्की के लिए पिछले पांच सालों में जो जो सुविधाएं दी थीं, उनको बढ़ावा दिया था, जो आपने कभी नहीं दिया। हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से बढ़ावा दें। उसको खत्म न कीजिए, उसको बर्बाद न कीजिए। आपने 1618 करोड़ 95 लाख रुपये इस इण्डस्ट्रीज की इन्वैस्टमैंट के उपलक्ष में लिखा है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जितनी इण्डस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना सेल्ज टैक्स आपके पास आयेगा। आपके पास कोई मिनरल्ज नहीं हैं। आपके पास सोर्सिज ऐसे नहीं जिससे आप यह कह सकें कि स्टेट की इन्कम बढ़ सकती है। मेरा कहना यह है कि आप मेहरबानी करके इण्डस्ट्रीज को जितना डिवैल्प करेंगे उतना स्टेट का भला होगा, उतना ही यूथ का भला होगा। उतनी ही हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उतना ही सब का भला हो जायेगा। मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि आपने कोई ऐसी स्कीम, सोलिड स्कीम कोई इस बजट में दी हो जिससे इण्डस्ट्रीज डिवैल्प हो सकें। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। एन०सी०आर० के अन्दर जो भी पैसा हमें सैन्टर गवर्नमैंट से मिलता है क्या वह सिर्फ हुड्डा के सैक्टरों के लिए ही मिलता है। जहां तक मैं समझता हूँ कि एन०सी०आर० के अन्दर जो पैसा मिलता है उसमें कम्यूनिकेशन, रोडज, इलैक्ट्रीसिटी और पानी के लिए भी मिलता है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के साथ लगते एरिया को अधिक डिवैल्प कीजिए ताकि दिल्ली का बोझ कुछ हल्का हो सके और हमारे यहां पर लोग बसने लग जाएं। हमने कहीं नहीं देखा कि आज तक कहीं पर एन०सी०आर० का जो पैसा ग्रांट के तौर पर सैन्ट्रल गवर्नमैंट से आता है वह सिवाय हुड्डा के कहीं और खर्च हुआ हो। अगर कहीं और काम आया हो, तो ये बता दें। एन०सी०आर० का जो पैसा है वह दिल्ली के साथ लगते टाउन्ज को मिलना था। मैं समझता हूँ कि एन०सी०आर० के पैसे से जिस एरिया की डिवैल्पमैंट होनी चाहिए थी वह

मिलता था। मैं समझता हूँ कि एन०सी०आर० के पैसे से जिस एरिया की डिवैल्पमैंट होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने यह बात ठीक कही कि दिल्ली के लोग शिफ्ट करके गुड़गांव के अन्दर पोल्यूशन से बचने के लिए अपनी कोठी बेच कर आये। इसमें कोई पैसा उनको नहीं बचा। जो पहले एक फ्लैट में रहते थे वे अब 500-500 गज के प्लाट के मकान में रहने लगे हैं। क्या हम समझें कि जो एन०सी०आर० का पैसा है वह अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए ही है या उन लोगों के लिए है जो प्रिविलेज क्लास के हैं। गरीब लोगों के लिए नहीं है। क्या गरीब आदमी को कोई फैसेलिटीज नहीं मिलेंगी। क्या हम यह समझें कि जो पैसा बाहर से आ रहा है वह सिर्फ शहरों के एक हिस्से के लिए है। यहां पर बहन कमला वर्मा जी लोकल बाडीज की मंत्री बैठी नहीं हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज इसमें जितने सुधार की जरूरत है, उतने नहीं हो रहे। मैं भी 5 साल तक इस महकमें का इन्चार्ज रहा हूँ हमें कुछ पैसा स्लम कलोनियों के लिए मिलता है। इस बार हमें इस काम के लिए 3 करोड़ 62 लाख रुपये मिले हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पैसे को ऐरिया में स्लम क्लीयरैंस के लिए ही लगाना चाहिए, अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए नहीं लगाना चाहिए। यह ग्रान्ट जहां पर खर्च करनी चाहिए वहां पर खर्च नहीं होगी। पिछली बार शहरों के स्लम की क्लीयरैंस के लिए जो ग्रांट मिली थी उस में से सात लाख रूपये के करीब गुड़गांव के स्लम ऐरिया में स्लम क्लीयरैंस के लिए लगाए जाने थे। स्लम ऐरिया के बारे में हर शहर में एक लिस्ट बनी होती है कि यह स्लम ऐरिया है, इसकी डिवैल्पमैंट होनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार की इत्तला के लिए बताना चाहता हूं कि डिपार्टमैंट ने जो ऑफिसर्ज वहां पर लगा रखे हैं हमने उनसे कहा कि यह पैसा स्लम क्लीयरैंस के लिए लगना है लेकिन उन्होंने फिर भी वह पैसा वहां लगा दिया जहां उनके पार्षद रहते थे। जब मैंने उनसे यह कहा कि यह इल्लीगल है आप यह पैसा यहां पर नहीं लगा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि इस पैसे के बारे आपने जवाब नहीं देना है। इस पैसे को खर्च करने का जवाब तो हमने देना है। बिना नक्शा पास किए अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हो सकती है कि यह बिल्डिंग नाजायज तौर पर बन रही है। वहां पर एक बिल्डिंग की एफ०आई०आर० दर्ज हुई थी लेकिन वहां के एक ऑफिसर ने 22 तारीख को नक्शा देखे बिना ही उस बिल्डिंग को पास कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार डिपार्टमैंट कैसे चलेगा। अर्बन डिवैल्पमैंट ऐसे नहीं हो पाएगा जिस तरीके से यह कहना चाह रहे हैं। मैंने आपसे उस दिन भी अर्ज की थी कि 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से अर्बन पापुलेशन हर साल 10-12 प्रतिशत बढ़ जाती है। 40 साल के बाद हम महात्मा गांधी जी का यह सलोगन भी नहीं कह पाएंगे कि India lives in villages. शहरों में आबादी बढ़ने का कारण यह है कि शहरों में मैडिकल फेसिलिटिज़, इम्पलॉयमैंट फेसिलिटिज़ एजुकेशन फेसिलिटिज़, रिसर्च फेसिलिटिज़ और दूसरी और भी बहुत सी ऐसी फेसिलिटिज़ हैं जो बहुत ज्यादा है जिन के कारण शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। अगर यह पापुलेशन इसी तरह और इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए इसलिए जो ग्रान्ट्स जिस काम के लिए हैं उनको वहीं पर खर्च किया जाए किसी मखसूस हिस्से पर खर्च न करके उस पैसे को सही जगह पर लगाएं, जो पैसा गांवों की डिवैल्पमैंट के लिए होता है वह गांवों की डिवैल्पमैंट के लिए ही लगना चाहिए ताकि शहरों पर आबादी का प्रैशर बहुत ज्यादा न बढ़े। स्पीकर साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूं जिससे अर्बन डिवैल्पमैंट रुकता है। अगर आज आंकडों के हिसाब से देखा जाए तो गुड़गांव में जमीनों की जो रजिस्ट्रीज़ होती हैं उनका काम तकरीबन आजकल बन्द पड़ा है। इसका कारण भी मैं बता देता हूं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां पर 5-6 हजार रूपये गज के हिसाब से जमीन मिल जाती है लेकिन गवर्नमैंट ने आर्डर्ज़ कर दिए हैं कि यहां की रजिस्ट्री10 हज़ार पर स्केयर गज के रेट से कम की नहीं होगी। इस वजह से वहां रजिस्ट्रियों का काम

[श्री धर्मबीर गाबा]

रूक गया है और सभी सौदे रुक गए हैं। स्पीकर सर, बजट में प्रोविजन है कि 333 करोड़ रूपया सरकार को रजिस्ट्री फीस से मिलेगा। रजिस्ट्रीज़ का जो अतिरिक्त रैवैन्यू सरकार को मिल सकता है वह गुड़गांव, फरीदाबाद तथा पंचकूला से मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा न हो कि रैवैन्यू की यह राशि घट कर 33 करोड़ ही रह जाए इसलिए इस प्रोविजन पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसी तरह से इण्डस्ट्रीज के प्लाट्स के बारे में बात है। लैण्ड लौर्ड के लिए चेंज ऑफ लैण्ड यूज़ का जो प्रोविजन रखा गया है उससे लैण्ड का जो अट्रैक्शन लोगों को मिला करता था क्या उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह एक चार्म था कि एच०एस०आई०डी०सी० उसे हुड्डा से प्लॉट दिला देगा। सरकारी रेट पर उसको प्लॉट मिल जाएगा और वे इन्डस्ट्री लगा लेंगे। इस पर भी अगर रोक लग जाएगी तो फिर इण्डस्ट्रियलिस्ट को क्या चार्म रह जाएगा कि वह गुड़गांव में इंडस्ट्रीज लगाए। (घण्टी) वही पैसा जो आप एनहान्समैंट करके ले लेंगे तो इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए वहां पर कोई चार्म नहीं रहेगा इसका नतीजा यह हुआ है कि इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट वहां पर बिल्कुल बन्द हो गया है। इस परपोज़ल को भी रि-इन्स्टेट करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सारी इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट रुक जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में कहना चाहता हूँ इस बारे में डिमान्ड नं0 16 है मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले चार दिन के अन्दर सड़कों की मरम्मत के बारे में बारह सवाल किए गए उनके जवाब में यह कहा गया कि फंड उपलब्ध नहीं हैं। क्या इनको अगले पांच सालों में ऐसे कोई फंड मिलेंगे जिनसे यह रिपेयर का काम किया जा सकेगा। इन्होंने एक प्रपोजल दी कि 550 किलोमीटर सड़कें बनेगी और 828 किलोमीटर सड़कों को ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब बजट के अन्दर सड़कों की मरम्मत के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है तो ये कैसे ठीक करेंगे। इस बारे में मुझे फाईनैंस मिनिस्टर जी बता दें। कैप्टन साहब,ने भी कहा था कि रिवाड़ी के अन्दर बाई-पास बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा इसका भी जवाब दे दें। इसके अलावा मुढानपुर में टूरिज्म कम्पलैक्स पड़ता है वह मेरे घर से 12 किलोमीटर है वहां पर भी बाई-पास बनाने की बहुत जरूरत है। हमारा कहना यह है कि आप पी०डब्ल्यू०डी० की मद से इनके लिए पैसे का प्रोविजन रखें। शहरों के अन्दर जहां जहां पर भी टूरिज्म कम्पलैकिसज़ है वहां पर बाई-पास प्रोविजन रखें ताकि वहां पर आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो। लोगों को राहत मिले। यह काम गवर्नमैंट के प्राईम पार्ट पर होना चाहिए। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं बैठ ही जाता हूँ जिससे आपको भी तकलीफ न हो और मुझे भी न हो। धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे डिमांडज पर बोलने का मौका दिया क्योंकि अध्यक्ष महोदय, यह जो 1997-98 का बजट पेश किया गया है यह किसी तरह से भी विकासशील नहीं है। 1996-97 के बजट में जो बढ़ौतरी 22 प्रतिशत थी वह इस बार केवल 15 प्रतिशत है। अब जबकि मंहगाई बढ़ी है, पैट्रोल, डीजल और कंस्ट्रक्शन मैटीरियल के दाम बढ़े हैं। इसलिए बढ़ोतरी की परसैन्टेज ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन वह कम हुई है। यह जो बजट है यह बिल्कुल दिशाहीन है। मैं डिमान्ड नं0 3 पर बोलना चाहूँगा। यह जो क्राईम रेट है इस बारे में आज के प्रश्न के जवाब में यह बताया गया है कि 31-3-96 से 15-2-97 तक रेप के केसिज में 279, अपहरण और अपनयन के केसिज में 279 और मर्डर के केसिज में 489 लोग गिरफ्तार किए गए। जिसमें से मर्डर के केस में एक दोषी को सजा हुई और 18 बरी हुए, रेप के केसिज में 15 बरी हुए, अपहरण और अपनयन के केसिज में 3 बरी हुए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूँगा कि मंत्री जी मेरी बातों का जवाब बाद में दे दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे सैशन

कोर्ट हैं वहां पर जजिज की जो संख्या है वह बहुत कम है। चार जिले पानीपत, रिवाड़ी, कैथल और यमुनानगर हैं जहां पर सैशन कोर्टस नहीं है। इस बारे में सरकार की तरफ से इन जिलों में कोर्टस खोलने की जो कार्यवाही चल रही है उसको ये जल्दी से जल्दी पूरा करें। अगर वहां पर सैशन कोर्ट बनेंगे तो अच्छा काम होगा। इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि अगर पूरे जजिज़ हों तो कोर्टस का काम सुचारू रुप से चल सकता है। इस समय जो आपकी पुलिस फोर्स है, उसकी संख्या थानों में बहुत ही कम है। उनके पास जो जीप्स हैं वे बहुत पुरानी हैं। जब मैं मंत्री था तो उस समय जो हमारे आगे-आगे पुलिस की जीप चलती थी उसकी रफ्तार बीस या 25 किलो मीटर से ज्यादा नहीं होती थी। तो यह हालत आज जीप्स की हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : आपके साथ जो जीप चलती थी क्या वह भी खराब होती थी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्टस बता रहा हूँ लेकिन आप मुझे बीच में टोक रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पुलिस फोर्स हैं उसके मोडर्नाइजेशन एवं कम्प्यूट्राइजेशन की बात आपने अपने बजट में कही है। जिस प्रकार से आज शराब की स्मगलिंग बढ़ रही है, जो लीकर माफिया आज प्रदेश में बन रहा है उसको देखते हुए पुलिस फोर्स को और भी मज़बूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि लीकर माफिया वालों के पास बहुत बढ़िया साधन हैं। अध्यक्ष महोदय, कम से कम चार पांच घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर पुलिस फोर्स पर अटैक किया गया। दो फरवरी को गोहाना में पुलिस फोर्स पर अटैक किया गया। ऐसी ही घटना जींद और सिरसा में भी हुई। चार फरवरी को जूई, भिवानी जिले में पुलिस फोर्स पर अटैक हुआ है। इसी तरह से पांच मार्च को दड़बाकलां में अटैक हुआ है। ऐसी ही घटनाएं कादमां और सतनाली में हुई हैं। बहादुरगढ़ में जहां पहले एक घटना रेप केसिज के बाद हुई थी वहां अब यह नया कांड हुआ है। इसके अलावा डूंडाहेड़ा में कुछ लड़कों ने तीन लड़कियों के सैप्स लिए तथा उनको परेशान किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज पुलिस फोर्स कम है इसलिए आज क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, कन्वीकशन कम हुई हैं क्योंकि जजिज कम हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि शराबबंदी से 600 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ लेकिन मैं कहता हूँ कि 3500 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है क्योंकि आज इस शराब के धंधे में हमारे बेरोज़गार नौजवान भी शामिल हो गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शराब बंदी के लिए कानून सख्त बनाया जाए। आज प्रदेश में लिकर माफिया बहुत मज़बूत बन गया है। जहां पहले उन लोगों के पास टूटी फूटी साईकिल होती थी वहीं आज उनके पास कारें हैं। जिसके कारण आज आम व्यक्ति के लिए अपना जीवन जीना दूभर हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पहले ही बता दें कि मुझे कितने समय तक बोलना है क्योंकि मैंने दस डिमांडज पर बोलना है उसके बाद मैं उसी हिसाब से बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आपने 12.38 मिनट पर बोलना शुरू किया था और आपका बोलने का समय केवल 12 मिनट ही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने गवर्नर ऐड्रैस पर भी मुझे बोलने के लिए केवल 9 मिनट दिए थे और बजट पर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। फिर आप ही बताएं कि क्या मैं हर डिमांड पर एक मिनट में बोल सकता हूँ। फिर तो हमारे कट मोशन देने का कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे हर डिमांड पर बोलने के लिए समय मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऐक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट की बात है। आपका जो एच०एफ०सी० है उसने गुड़गांव के अंदर विद आउट वैरीफिकेशन लोन दे दिया जिसकी बाद में रिकवरी भी नहीं हो पायी। इसी प्रकार से सी०ए०जी० की जो रिपोर्ट दी हुई है उसमें है -Loss of Rs. 4

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

crores on account of under assessment on various heads - जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस या मोटर व्हीकल्ज ऐक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन फीस में अंडर असेसमैन्ट की गयी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो टैक्स के विशलेषण का तरीका है वह गलत है। जो 31 मार्च, 96 की सी०ए०जी० की रिपोर्ट दी हुई है उसमें यह बात है। जहां तक टैक्सिज की बात है यह ठीक है कि आपने शराबबंदी कर दी लेकिन लाटरीज के ऊपर आपने सैल्ज टैक्स कम किया जिसमें आज हमारे लाखों बेरोज़गार नौजवान शामिल हो रहे हैं और गरीब आदमी अपने जीवन भर की सारी पूंजी इसमें लगा देता है। सरकार इसको क्यों बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से रिवाड़ी के अंदर दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने फर्जी वाउचर पकड़ कर जमा करवाए। जी०एम० ने यह बात पकड़ी। वहां से वे फर्जी बाउचर पकड़ कर जमा करवा देते थे। जब वे बाउचर दिल्ली डिपो में आए तो कोई पैसा नहीं मिला। इसमें तकरीबन एक करोड़ रुपये की गड़बड़ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 8 पर बोलूंगा। रिवाड़ी शहर बहुत बड़ा शहर है। वहां बाई-पास बनाने की बहुत जरूरत है। इसके अंदर जो 28 करोड़ रुपया दर्शाया गया है वह आप रोडज की रिपेयर पर खर्च करेंगे। जब से रिवाड़ी में इंडियन ऑयल का डिपो बना है, वहां से दुनिया भर के ट्रक निकलते हैं इसलिए वहां पर बाई-पास का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय हमने जितने शहरों में कंक्रीट रोड बनवाई थी वह कंक्रीट रोड आज 5 साल हो रहे हैं कहीं से टूटी नहीं हैं। जहां भी सर्कुलर रोड हैं वहां कंक्रीट रोड हों, तो जो बार बार मेंटीनैंस पर खर्च होता है वह नहीं होगी। आप इसके लिए कोई पौलिसी बनाएं कि जो पी०डब्ल्यू०डी० रोड बनाती है उसमें ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए। इसी प्रकार से जयपुर हाइवे है। (विघ्न) नैशनल हाइवे की फोरलेनिंग करने की बात चल रही है। इसके अलावा फ्लड की वजह से और मसानी बैराज पर शटर लगाने की वजह से भी काफी सड़कें टूटी हैं। माननीय मंत्री जी हर चीज में कह देते हैं कि सड़कें फंडज की उपलब्धता के आधार पर बनाएंगे। जो उनका बजट है उसमें से पैच वर्क और वाइडनिंग पर जरूर काम करें यह मैं उनसे अनुरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मेरे और आपके पड़ोस में एक सड़क बास गांव को जाती है वह कितने साल से टूटी पड़ी है, मेरे ख्याल से वह छह साल से टूटी पड़ी है।

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप वाले गांव की सड़क की वाइडनिंग कैप्टन अजय सिंह ने करवाई थी वह कंपलीट हो चुकी है। आप देख लीजिए। मेरे समय में अगर मैं काम नहीं करवाता तो जनता मुझे 3 बार चुनकर नहीं भेजती। जब कांग्रेस पार्टी के 5 सदस्य चुनकर आए थे और उस समय भी मैं चुनकर आया था और इस समय 9 हैं तब भी चुनकर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं मैंने कट मोशन दी हुई है इस लिए मुझे कम से कम हर डिमांड पर बोलने का मौका मिलना ही चाहिए। अब मैं सिंचाई के बारे में बोलना चाहूँगा। जहां तक सिंचाई का सवाल है। पिछले दिनों जो बाढ़ आई, मसानी बैराज पर शटर न लगाने की बजह से, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आन दि फलोर ऑफ दि हाउस यह आश्वासन दिया था कि शटर लगा देंगे। लेकिन वहां 7.2 फुट की दीवार खड़ी कर दी। अगर वह दीवार टूट गई तो 50 गांव पानी में बह जाएंगे इसलिए शटर लगने चाहिए। इसके अलावा कुचावास गांव में सड़क टूटी पड़ी है उसकी रिपेयर होनी चाहिए। मसानी बैराज के इलाके में जो छोटी छोटी ढाणियां हैं वे सारी ड्रेन से भर रही हैं। इस पर मेरा सझाव है कि जे०एल०एन० कैनाल में जो यमना

का पानी आता है उस वक्त फ्लड आ जाता है इसलिए जे०एल०एन० कैनाल को मसानी बैराज पर डाईवर्ट कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि हम जे०एल०एन० पर काम कर रहे हैं और इस बारे दस लाख की रकीम है। तो इस स्कीम के तहत यह काम कर दिया जाए। इस सरकार ने माना है कि इतना पैसा इस स्कीम में रखा है। इसी प्रकार से जे०एल०एन० कैनाल के पम्पस की कैपेसिटी लिफ्ट करने की कम रह गई है। वे केवल 25 फीट के करीब ही पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी कनकलूड कीजिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं इररैलेवैंट बात तो बोल नहीं रहा हूँ आपने मुझे समय दे दिया इसके लिए आपकी बड़ी कृपा है। जहां तक भाखड़ा और डब्ल्यू०जे०सी० का सवाल है जब तक इसकी सफाई नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। साउदर्न हरियाणा का पानी हिसार और सिरसा को दिया जा रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग से होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा यह भी बतायें कि जो हिसार-सिरसा को ज्यादा पानी देने की बात आप मानते हैं वह कब से दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : पहले जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री रहे और दूसरे मुख्यमंत्री रहे तभी से हमारे क्षेत्र के साथ ज्यादती होती रही है। यह टाईम है आप इसको डिस्ट्रिब्यूट करें।

श्री अध्यक्ष : जब हम आपकी जगह बैठा करते थे तब आप इस बात को नहीं मानते थे चलो आज मान लिया यह अच्छी बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : हमारे पास जितना पानी अवेलेबल है उसकी डिस्ट्रिब्यूशन तो ठीक से होनी चाहिए उधर पंजाब से पानी मांगने की बात करते हैं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। हमारे साथी कैप्टन अजय सिंह जी ने ठीक बात कही है। स्पीकर सर, इससे पहले कभी भी कट मोशन पर किसी सदस्य को बोलने के लिए इतना समय नहीं दिया गया और इतनी लम्बी चर्चा नहीं हुई। कैप्टन अजय सिंह ने यह माना है कि जब ये पहले की सरकार में वजीर थे उस सरकार के समय में महेन्द्रगढ और रिवाड़ी का पैसा हिसार और सिरसा में गया चौधरी भजनलाल के समय में गया इसके लिए इनका धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव : एस०वाई०एल० के बारे में जहां तक बात है इसको बनवाने में यह सरकार जानबूझकर डिले कर रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप कंक्लूड करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : राजस्थान सरकार जिसमें रामबिलास जी के साथी वहां वजीर बैठे हैं हमारे पानी को रोक लेते हैं। जब फालतू पानी होता है तो हमारे इलाके को डूबो देते हैं। ऐसे ही कृष्णावती नदी और दोहान नदी हैं। सरकार ने इस पर काम नहीं किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गये हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे पूरा समय दिया हर कट मोशन पर बोलने के लिए आपने हमें समय दिया यह आपने बड़ी दरियादिली दिखाई लेकिन आप किसी के प्रैशर में है यह बात हम समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कट मोशंज़ पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अभी डरते डरते खड़ा हुआ था क्योंकि कल जब मैं सिर्फ यह बताने के लिए खड़ा हुआ था कि सांगवान साहब ने सदन की कार्यवाही में रुकावट डाली है तो आपने बजाए उनकी गलती के मुझे नेम कर दिया था। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है। मैंने इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब ये मुझे कम्पैल कर रहे हैं कि मैं इनको डिस्टर्ब करूं। ये डिस्टर्ब करने के लिए मुझे इन्वाइट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब आराम कर रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब न करें। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हम तो उनका बहुत आदर करते हैं। वे हम से उम्र में बहुत बड़े हैं। मेरी अपनी बात करने से पहले मुझे डर लगने लग रहा है। किसी ने कहा है :-

'मेरा मुन्सिफ ही मेरा कातिल है,
कौन भला मुझे यहां सिला देगा।'

मंत्री महोदय, थोड़ा बहुत कभी कभी सरकार चलाने की बातों की बजाए और दूसरी बातें भी कर लेनी चाहिएं। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं डिमांड नं० 15 जो कि सिंचाई के संबंध में है, उस पर बोलने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। बजट स्पीच के पैरा 40 में वित्तमंत्री जी ने जिक्र किया है कि डब्ल्यू.आर.सी.पी. प्रोजैक्ट के तहत 1858 करोड़ रूपये का ऋण वर्ल्ड बैंक से 6 साल के लिए लिया जाएगा। स्पीकर सर, आज इस सदन का हर माननीय सदस्य यह मानता है कि बजट चाहे आज की मौजूदा सरकार का हो या विपक्ष के साथी जब सत्ता में थे, उनकी सरकार का हो, बजट की एक मूलभूत बात यह है कि वह जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। यह उन नीतियों का स्वरूप है जो सरकार जनता के समक्ष पेश करना चाहती है। आज इस बजट स्पीच जो वित्तमंत्री जी द्वारा दी गई थी, को पढ़कर यह साफ मालूम होता है कि यह पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। इस बजट में 80 प्रतिशत जनता को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया गया है। इस बजट में न किसानों के लिए, न हरिजनों के लिए, न बैकवर्ड क्लासिज़ के लिए, जो कि हरियाणा में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसंख्या का हिस्सा है, कोई खास प्रावधान रखा है। उनके लिए मात्र 10 प्रतिशत का प्रावधान ही है। यह एक शर्मनाक बात है। यह एक बहुत बुरी बात है। (विघ्न) मैं अभी एक एक प्वायंट पर आपको बता दूंगा (विघ्न) मैं सारा पढ़कर बताउंगा। (विघ्न) आप बुजुर्ग हैं। मैंने तो कभी आंकड़ों के बगैर इस सदन में बात ही नहीं कही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने 12.54 बजे बोलना शुरू किया था और 1.04 बजे तक आपके बोलने का समय है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले ही बैठ जाता हूँ। स्पीकर सर, 1858 करोड़ रूपए जो ऋण 6 साल के अर्से में ले रहे हैं। जो उम्मीदें हरियाणा के किसानों को बार-बार बंधाई जाती हैं वे एक तो यह कि किसानों के खालों को पक्का करने का मुद्दा, दूसरा नहरी आबियाना का मुद्दा, जिसकी चर्चा मैंने आगरा कैनाल के परिप्रेक्ष में भी की थी। वर्ल्ड बैंक से जो ऋण लेने की बात है उसके बारे में मुझे नहरी विभाग के अफसरान ने लोक लेखा समिति की बैठक के दौरान बताया था कि सन् 2000 तक यह जो पैसा खर्च होगा और अब जो सालाना नहरी सिस्टम आया करेगा, वह इस प्रकार का प्रावधान है, जो नहरी आबियाना एक साल में सरकार लेगी और जो खर्चा

13.00 बजे आएगा वह बराबर होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो नहरी पानी का आबियाना सन् दो हजार तक 200 प्रतिशत बढ़ेगा इस बात का प्रावधान है और इस बात की मंशा सरकार की है। स्पीकर साहब, दो बातों की साफ तौर पर नजरअंदाजी की गई है। हरियाणा सरकार के पास आय के दो स्रोत हैं जिनसे हरियाणा के किसानों पर नहरी आबियाने का बोझ न डाल कर उनसे वह पैसा रिकवर किया जाए। स्पीकर साहब, आज हरियाणा मार्किटिंग बोर्ड को मार्किट फीस से करोड़ों रुपये की आय हो रही है। वह सारा पैसा मार्किटिंग बोर्ड मार्किट कमेटीज से रिकवर करता है। कृषि मंत्री महोदय खास तौर से इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि किसान जब अपनी जमीन के अंदर नहरी पानी लगाता है उस पानी से जो फसल पैदा होती है उस फसल को किसान मार्किट में बेचता है। सरकार उस पर मार्किट फीस लगाती है तो अगर मैं यह कहूं कि उस मार्किट फीस का सीधा-सीधा कनैक्शन उस नहरी पानी के साथ जुड़ा हुआ है तो यह गलत नहीं होगा। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि सरकार को नहरी पानी के आबियाने का सारे का सारा खर्चा हरियाणा के किसान के ऊपर डालने की बजाये जो मार्किट फीस का पैसा आता है उसका 25, 40 या 50 प्रतिशत पैसा नहरी सिस्टम के मोडरेनाइजेशन पर और उसके रखरखाव पर सालाना जो खर्चा हो वह उसमें से दिया जाए। इसके अलावा स्पीकर साहब, मेरा एक सुझाव यह भी है कि वन विभाग नहरों और रजबाहों पर किसानों की जमीनों के साथ-साथ अपनी जमीन पर पेड़ लगाता है। वह जो प्लांटेशन करता है उससे सालाना सरकार को तकरीबन 27 करोड़ रुपये आय होती है। उस जमीन में वन विभाग की प्लांटेशन से जो आय होती है उसका नहरी पानी के साथ सीधा संबंध है क्योंकि वह पानी रिस कर उस जमीन के अंदर चला जाता है और उस जमीन में वन विभाग जो पेड़ लगाता है और जहां जहां पर पेड़ लगते हैं उनसे चार-चार और पांच-पांच फुट दूर तक किसानों की फसलें ठीक नहीं हो पाती हैं, जिससे किसानों को उसका नुक्सान है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जो नहरी पानी के आबियाने का खर्चा आपने सन् दो हजार तक किसानों पर डालना है वह किसानों पर डालने की बजाए आप वन विभाग को जो प्लांटेशन से आय होती है उसमें से वह आधा पैसा नहरी महकमे को दें। इस तरह से अगर सरकार चाहे तो सरकार किसानों का नहरी पानी का आबियाना माफ कर सकती है। सारा नहरी पानी किसानों को मुफ्त मिल सकता है। स्पीकर साहब, हरियाणा का गरीब किसान जिनके पास 3-3, 4-4 और 5-5 एकड़ जमीन है, वह नहरी पानी के आबियाने का पैसा व्यय क्यों सहन करे। वह सिर्फ इसलिए कि पहले स्टैप पर वह पानी लगाता है उस पानी से सरकार को भिन्न-भिन्न तरीकों से आय हो रही है। सरकार को वह पैसा बराबर बांटना चाहिए। यह एक न्यायसंगत बात होगी। स्पीकर साहब, जो नहरी पानी के खालों को पक्का करने का मामला था वह एक अलग मुद्दा है और वह बार-बार हरियाणा की जनता को चुभता है। स्पीकर साहब, 1985 के अन्दर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय उस सरकार ने एक क्रान्तिकारी फैसला लिया था कि किसानों की तरफ उन खालों को पक्का करने की जो साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की अर्जित राशि थी वह उस सरकार ने माफ कर दी थी।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : कांग्रेस पार्टी की सरकार 1985 में भी थी लेकिन यह फैसला चौधरी बंसी लाल ने किया था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, उससे पहले चौधरी भजन लाल जी की सरकार भी थी उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई थी। वह किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं थी। न आज है न उस दिन थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अभी सदन में एक सुझाव दिया कि जो नहरी पानी है उसके आबियाने का बोझ हरियाणा के किसानों पर पड़ता

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

है, क्यों न वह पैसा हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड भरे। वह उसकी भरपाई करे। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से श्री सुरजेवाला से कहना चाहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा का सारा पानी आप अपनी तरफ ले गये। चलो हम मान लेते हैं कि ये अपने खेत में ज्यादा पानी लगा लें। लेकिन यह जो सुझाव हमें आज दिया, उस बारे में मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि यह सुझाव इन्होंने अपने पिताश्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को देना चाहिए था जब वे सिंचाई मंत्री थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने या तो बजट स्पीच नहीं पढ़ी या ये तैयारी ठीक करके नहीं आये। यह जो 1858 करोड़ रुपये का ऋण लिया है यह तो पिछले साल लिया है और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी तो 1991 तक बिजली और सिंचाई मंत्री थे, उसके बाद नहीं थे। जरा ये अपने तथ्य जांच करके फिर खड़े हुआ करें। शमशेर सिंह जी तो बड़े पढ़े लिखे और सूझ-बूझ वाले व्यक्ति हैं। हमें उनसे जरूर उम्मीद है और किसी को हो या न हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी तो 1992 तक सिंचाई मंत्री थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : हां जी, यह 1994-95 की स्कीम है। स्पीकर साहब मैं आपको बता रहा था कि 1985 में हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जैसा कि माननीय श्री मनीराम गोदारा जी ने भी माना है। उस समय एक क्रांतिकारी फैसला लेकर 350 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार ने किसानों के जो पक्के खाले बनाये थे, उसका पैसा किसानों से पहले लेना था, लेकिन बाद में हमारी उस वक्त की सरकार ने उस पैसे को माफ किया था और आगे के लिए सरकार ने यह फैसला किया था कि अब खाल पक्के सरकार खुद बनायेगी। (विघ्न)

श्री मनीराम गोदारा : देखिये, आप कांग्रेस पार्टी का नाम उस हालात में लें कि कांग्रेस पार्टी के उस वक्त कौन मंत्री थे और कौन नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के मंत्री तो बाद में भी बनते रहे हैं। उन्होंने कौन से प्रोग्रेसिव स्टैप लिए, जिनको आप मैंशन कर रहे हैं, यह किसने किये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं यही बता रहा था कि उस समय मैंने जैसा अभी माननीय गोदारा साहब ने सुना, उन्होंने यह कहा था कि 1985 में पहले चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री थे फिर चौधरी बंसी लाल मुख्यमंत्री थे। व्यक्ति का सवाल नहीं था, पार्टी का सवाल है। पार्टी की नीतियों का सवाल है।

श्री मनीराम गोदारा : यह फैसला 1986 में लिया गया था (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, उस समय हमने यह फैसला लिया था कि हरियाणा के किसानों के खाल सरकार मुफ्त में पक्के करेगी, हमेशा के लिए। मुझे नहीं पता कि किस कारणवश सरकार ने बाद में पक्के खाल नहीं किए। किसान अपने खाल पक्के करवाने में, उनकी लाईनिंग करवाने में और उनकी मुरम्मत करवाने में असमर्थ हैं। (विघ्न)

श्री मनीराम गोदारा : मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बात वही कहेंगे जो सही और रियलिटी है। आपने एक बात कही कि यह फैसला 1985 में हुआ था जबकि यह फैसला 1986 में हुआ था। उस वक्त यह फैसला हुआ था कि महकमा नहर के भविष्य में जितने भी खाल पक्के होंगे, उनको सरकार अपने खर्च पर पक्के करेगी। मैं बताना चाहूंगा कि 1986 के बाद जो भी सरकार आई उन्होंने उस फैसले को नहीं माना तभी वे सारे फैसले टूट गये थे।

Shri Mani Ram Godara : When you put the things, you must know everything.

Shri Randeep Singh Surjewala : I was only pointing out for your consideration that the decision to waive off Rs. 350 crore was taken in the year 1985-86 and at that time congress party was in power.

Mr. Speaker : That was the year 1986-87.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, it is a fact that at that time Congress Party was in power. यह एक सत्ता रूढ दल था यानि कि हरियाणा के अन्दर यह एक सच्चाई है। यह कड़वी घूंट तो आज सरकार को पीनी ही पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय से मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं कोई भी गलत बात नहीं कहूंगा। किसानों की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो फैसला 1986-87 में लिया वह बहुत महत्वपूर्ण फैसला था उस पर सरकार को दोबारा से सोचना चाहिए। अगर अब किसान को ही खालों और रिजरवायर्ज की मुरम्मत करवानी होगी, उनकी रिपेयर की जिम्मेदारी किसान को खुद ही लेनी पड़ेगी और आगे आने वाले समय में उनका रखरखाव भी किसान को खुद ही करना होगा, इसका सीधा-साधा नतीजा यह निकलेगा कि कुछ काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब यह सारी जिम्मेदारी किसान के ऊपर डाल दी गई है। कोई कमेटी नहीं बन पाएगी, न पैसा इकट्ठा हो पाएगा और न ही पैसा जमा करा पाने की शक्ति किसी में हो पाएगी। इससे सरकार की मन्शा साफ़ झलकती है कि किस प्रकार से खालों पर करोड़ों रुपये का जो खर्च आ रहा है उसको बचाया जाए। स्पीकर सर, मैं आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इससे किसानों में बड़ी भारी बेचैनी है इसलिए सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इस फैसले को वापिस लेने की कृपा करे। इस पर पुनर्विचार करके जो सहूलियत 1986-87 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसान को दी थी उसको ही जारी रखा जाए। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान समाज कल्याण विभाग की तरफ भी दिलाना चाहूंगा। समाज कल्याण विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। सरकार ने तीन तरह के प्रावधान बजट में रखे हैं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट स्पीच पढ़ी उसमें वर्ष 1997-98 के दौरान हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है उसके आंकड़े भी मैं हाउस में रखना चाहता हूँ। वर्ष 1997-98 में हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज़ के लोगों के उत्थान के लिए 27.29 करोड़ हरिजनों के उत्थान के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम में 35.79 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है और आई०आर०डी०पी० के तहत 7.70 करोड़ रूपये रखे गये हैं। नेहरू रोजगार योजना में 8.47 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है और इन्दिरा विकास योजना के तहत 8.11 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, कुल 1575 करोड़ रुपये का टोटल बजट अनुमान है। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज़ लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 40% है लेकिन उनके लिए टोटल बजट का 5.54 परसैंट राशि का प्रावधान रखा गया है जो कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है तथा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमने जो कट मोशन दिये हैं उन पर आप वोटिंग करवाएं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ तथा यह मांग करता हूँ कि इस पर डिबीज़न होनी चाहिए और जो कट मोशन हमने दिया है उस पर वोटिंग होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री देवसज दीवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपसे विनती करता हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी आप ध्यान रखने की मेहरबानी किया करें। आज करीब 5-6 दिन के बाद मुझे

[श्री देव राज दीवान]

बोलने का मौका मिला है। मुझे अपने हल्के के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना है क्योंकि पहले मेरे हल्के के साथ जो अन्याय होता रहा है, पिछली सरकार ने मेरे हल्के की उपेक्षा की है। मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बराबर ख्याल रखते रहे हैं। जब भी आप कोई सवाल पूछने के लिए खड़े हुए, आपको मौका दिया गया है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह जो हविपा और भाजपा की गठबन्धन की सरकार के वित्त मंत्री जी ने 12.3.97 को जो बजट पेश किया है, उस बजट के बारे में हरियाणा राज्य की जनता ने रेडियो, अखबार और टी०वी० के माध्यम से सुना और पढ़ा है। जब यहां से दो दिन की छुट्टी हुई थी तब मैं अपने हल्के में गया था और वहां पर मुझे पांच सौ के करीब आदमी मिले थे। उन्होंने इस बजट के लिए हमारी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट कर मुक्त, किसानों के हित और गरीबों के हित के लिए पेश किया है। उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी बंसी लाल जी इतना अच्छा बजट कहां से लाए। आपने बजट की चर्चा के दौरान हिस्सा क्यों नहीं लिया उनका धन्यवाद क्यों नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं यहां पर तीन दिन से हाथ उठा रहा था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग इस बजट से संतुष्ट तो हैं। उन्होंने मुझे कहा कि इससे अच्छा बजट और क्या होगा ? इससे पहले आज तक ऐसा बजट नहीं आया है। मैंने कहा कि अपोजिशन वाले तो इस बजट में खामियां निकालते हैं कि यह बजट ठीक नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है उनके दिल में यह बजट बहुत ही अच्छा है। अपोजिशन में होने की वजह से वे इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इसलिए वे इसमें खामियां निकालते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इनकी आधी हां है और इनकी आधी हां को पूरी हां मान लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, 12 मार्च को जो बजट पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। शराबबंदी या कानून व्यवस्था के बारे में जो जो बातें यहां पर कही गयी हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में बल्कि यह कहिए कि सोनीपत जिले में आज के दिन पूरी तरह से शराबबंदी है। वहां पर बिल्कुल शराब नहीं बिकती। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, सी०एम० साहब ने तो कहा था कि 85 परसैंट शराबबंदी हुई है लेकिन ये तो पूरी तरह से शराबबंदी की बात कह रहे हैं।

श्री बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जो 85 परसैंट शराबबंदी की बात बताता हूँ, यह मैं पूरी स्टेट की एवरेज निकाल कर बताता हूँ। सोनीपत में तो पूरी तरह से शराब बंद है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, ऐक्सीडैंट्स में, कत्ल के केसिज में, लड़ाई झगड़ों में यानी हर तरह के केसिज में कमी आयी है। पिछली सरकार की कानून व्यवस्था के मुकाबले में आज जो कानून व्यवस्था का हाल है वह बहुत ही अच्छा है। आज से दो साल पहले अगर आप देखते तो आप पाते कि शाम को सात बजे के बाद माँ, बहन, कोई बुजुर्ग सड़क पर नहीं निकलता था। उस समय यह डर रहता था कि पता नहीं कब कहां से दो नौजवान आएंगे और मां-बहन की चुन्नी खींचकर ले जाएंगे। (विघ्न)

Mr Speaker : I request all the Hon'ble Members not to interrupt.

श्री देवराज दीवान : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो शराबबंदी के बारे में कमेटी बनी

है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इसके और अच्छे परिणाम बाद में सामने आएंगे। मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि अभी तो इस सरकार को बने हुए केवल आठ महीने ही हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी पंजाबी में एक कहावत है कि जब कोई आदमी बिजनैस करता है, कोई काम करता है तो कहते हैं कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी और तीसरे साल खट्टी (कमाई)। इसलिए आप कम से कम तीन साल देखने के बाद ही कहना कि यह सरकार कुछ कर रही है या नहीं। आपको थोड़ा समय तो देखना चाहिए। अगर तीन साल बाद सरकार कुछ करके न दिखाएं और तब जनता खुश न हो तब आप कह सकते हैं। अगर जनता यह कहे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, 24 घंटे बिजली देती है तथा कानून व्यवस्था ठीक है तब आप कुछ नहीं कह सकते। सरकार अगर तब कुछ न करें तब हम आपके साथ होंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है। हाउस में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी की कोई छटनी नहीं की जाएगी। किसी तरह की सबसिडी की कटौती नहीं होगी। किसान को पूरी सबसिडी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की हर सैक्टर में जरूरत है। इंसान के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, इंसान को आराम के लिए और पानी पीने के लिए अगर बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं आता। खेती के लिए और उद्योगों के लिए बिजली की जरूरत है। आज जनता चाहती है कि आप बिजली का निजीकरण करो। निजीकरण की कमियां जो बिपक्ष के साथी बता रहे हैं वह सही नहीं है। आज हमारी सरकार के पास पैसे की कमी है, बिपक्ष के साथी सोचते हैं कि इसलिए बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिन देशों के पास पैसे की कमी नहीं है वे भी बिजली के निजीकरण में विश्वास रखते हैं। वहां हर चीज, चाहे बिजली है, चाहे फलाई ओवर हैं, चाहे सड़कें हैं, हर काम को निजीकरण के आधार पर किया जाता है। इसलिए वे देश तरक्की कर रहे हैं। आज कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो जो निजीकरण की पोलिसी को अपनाएगा वही राज्य तरक्की करेगा और जो नहीं अपनाएगा, वे तरक्की नहीं कर सकता। मैं अभी यूरोप और अमेरिका में घूमकर आया हूँ। वहां के लोग कहते हैं कि हमारी तरक्की का कारण निजीकरण है। उन्होंने फ्लाई ओवर, हाइवे और शहर से गांवों को जोड़ने की सड़कें भी निजी क्षेत्र को दी हुई हैं। उससे काफी तरक्की हो रही है। लेकिन निजीकरण से किसी गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हांगकांग में एक शहर से दूसरे शहर तक समुद्र के नीचे से सड़क निकाली हुई है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सैंस हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री देवराज दीवान : उस सड़क से अगर कोई कार जाती है तो उससे 10 डालर टैक्स लिया जाता है लेकिन वह टैक्स किसी स्कूटर, साइकिल, रिक्शा वाले या किसान से नहीं लिया जाता है। इसलिए

[श्री देव राज दीवान]

मैं कहता हूँ कि यह चीजें अपने यहां पर अपनाई जाएं तो हमारा राज्य हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आकर बहुत तरक्की कर सकता है। यह मैं निजीकरण के बारे सलाह दे रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि बाकी साथी भी इस चीज को देखें। बेशक आप बाहर देखकर आएं। वैसे दिल से सभी इस बारे में जानते हैं। राज्य की जनता भी यह चाहती है और कहती है कि चाहे निजीकरण करो चाहे कहीं से बिजली लाओ वह 24 घंटे हमें मिलनी चाहिए। सड़क अच्छी चाहिएं। हाइवे अच्छे चाहिएं। शहर से गांव को जोड़ने के लिए सड़कों की अच्छी स्कीम लाई जाएं। जहां तक सड़कों की बात है सड़कों के लिए सरकार ने 108 करोड़ 90 लाख रूपये रखे हैं। उसमें से 50 करोड़ रुपये सोनीपत के लिए रखे जाएं। कम से कम 15 साल हो गये सोनीपत की सड़कें टूटी हुई हैं। गांव की सड़कों में 3-3 फुट गहरे गड्डे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। सोनीपत के बाई-पास के लिए जो राशि पास की है उसको जल्दी से जल्दी भिजवाया जाये ताकि काम शुरू हो सके। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत बाई-पास के साथ वाली सड़कों और शहर के अन्दर की सड़कों की रिपेयर का काम भी करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में 1997-98 की परियोजना में इस योजना के अन्तर्गत जो सोनीपत के लिए राशि रखी है उसको जल्दी भिजवाया जाए ताकि इस योजना के अन्तर्गत जो काम हैं वे पूरे किये जा सकें। हरियाणा राज्य फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने राजमार्गों पर रिंग बांध बनाने के लिए और पम्पों की व्यवस्था के लिए योजना तय की है और इस योजना के अन्तर्गत 1997-98 में 48 करोड़ 70 लाख रुपये रखे गये हैं। मैं चाहूंगा कि सोनीपत की तरफ इस योजना के अन्तर्गत अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए क्योंकि पिछली बरसात के दौरान सोनीपत के इलाके में फ्लड के पानी से बहुत नुकसान हुआ था। उस वक्त भी मैंने मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बताया था और कई महीने तक वह पानी निकालते रहे। लेकिन अभी दो महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी ने फ्लड का पानी निकालने की 30 दिसम्बर की तारीख रखी थी तब जाकर वह पानी निकल पाया था। जूंआ एक बहुत बड़ा गांव है उसकी दो पंचायतें हैं। इसी तरह से पिनाना बहुत बड़ा गांव है और उल्देपुर गांव है जब पिछली बार वर्षा हुई तो इन गांवों में बाढ़ का पानी बड़ी देर तक खड़ा रहा। पिनाना गांव को बचाने के लिए एक बांध बनाया गया है। अब पिनाना-दहा सड़क और पिनाना-बाहला सड़क पर बांध बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये गांव फिर डूब जायेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन गांवों की तरफ स्पेशल तौर पर ध्यान देते हुए इन गांवों के बांध बनाये जायें क्योंकि बरसात के दिनों में कई महीनों तक इन गावों के लोगों को पानी में रहना पड़ता है। (विघ्न) सरकार ने इस साल के दौरान 80 डिस्पैंसरियों का दर्जा बढ़ाने का प्रावधान रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चिटाना गांव में वैट्रनरी हस्पताल और चढियाली गांव की डिसपैंसरी को शीघ्र से शीघ्र बनाया जाये क्योंकि इनकी वहां के लोगों के लिए बहुत जरूरत है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) परिवहन के क्षेत्र में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सोनीपत क्षेत्र में जो प्राईवेट बसों को परमिट दिये जाते हैं उनका रूट निर्धारित किया जाये क्योंकि पिछले दो साल से प्राईवेट बसें अपनी मर्जी से भिन्न-भिन्न रूटों पर चल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सोनीपत डिपो की बस बड़ौत से सोनीपत और सोनीपत से बागपत चल रही थी, जो की करीब डेढ़ महीने से बंद है। जिसके कारण बहुत से लोग परेशान हैं। इसके बारे में मुझे समझ नहीं आता है कि बस बंद करने के क्या कारण हैं? कई बार इस बारे में वहां के जी०एम० से बात की गई लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला। इसके लिए मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ध्यान दें क्योंकि यू०पी० से हरियाणा आने वाले और हरियाणा से यू०पी० जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए ये बसें जल्द शुरू करवाई जायें। उपाध्यक्ष महोदय, जल सप्लाई और सफाई के लिए चालू वित्त वर्ष 1997-98 में गांवों में पीने के पानी के लिए उपलब्ध साधनों की

बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जल-स्रोतों की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गांवों में जल सप्लाई की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। सोनीपत हल्के के कुछ गांव जैसे पिनाना, पल्देपुर, खीरजपुर, माजरा, माहरा, ठरू, बड़वासनी, शहजादपुर इत्यादि में पानी का यह हाल है कि 4-4 फुट गड्ढे नीचे खोदकर वहां से गिलास या मग द्वारा पानी बाल्टी में भरते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दें कि इन गांवों में पीने के पानी की जल्द से जल्द व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, शहरों की सफाई अब ठीक-ठाक हो रही है। क्योंकि पहले तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी इसलिए सफाई नहीं हो रही थी। म्यूनिसिपल कमेटियों में जैसे सोनीपत म्यूनिसिपल कमेटी में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन में से 26 या 30 सफाई कर्मचारी आफिसर्ज़ जैसे डी०सी०, एस०डी०एम०, जज़िज, एस०पी० के घरों की सफाई करने के लिए 2-2, 3-3 चले जाते हैं। इस बारे में मैं सरकार को एक नेक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इन आफिसर्ज़ को अपने घरों की सफाई करवाने के लिए कोई आदमी चाहिए तो वह अपने स्तर पर डेली वेजिज़ वगैरह पर कर्मचारी रख लें। अगर वे म्यूनिसिपल कमेटियों के सफाई कर्मचारी ले जाते हैं तो उससे नुक्सान होता है। जैसे एक मिस्त्री के साथ 3-4 मजदूर होते हैं अगर वे चारों ही सफाई करने के लिए उन औफिसर्ज के घरों में चले जाएंगे तो उस मिस्त्री को खाली बैठे ही तनख्वाह देनी पड़ेगी क्योंकि वह मिस्त्री उनके बगैर कार्य नहीं कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह है कि वे औफिर्सज डेली वेज़िज पर आदमी रख लें। म्यूनिसिपल कमेटियों से सफाई कर्मचारियों को न लें। वैसे मुझे इस बात का भी विरोध नहीं है कि वे औफिसर्ज़ अपने घरों की सफाई करवाने के लिए उन कर्मचारियों को क्यों ले जाते हैं ? लेकिन ऐसा करने से शहर की सफाई के काम में बाधा आती है। अगर कमेटीज के सफाई कर्मचारी एक घंटा डी०सी० या एस०पी० के घर पर सफाई का काम कर लेंगे तो वे किसी की बात नहीं सुनेंगे। इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, सोनीपत शहर में पानी खारा है। सोनीपत में 20 कि०मी० दूर से पीने के पानी की सप्लाई होती है। सोनीपत शहर के लिए रेलवे लाईन की पश्चिम दिशा में 4 करोड़ 73 लाख 75 हज़ार रुपये की पीने का पानी सप्लाई करने की एक स्कीम कई सालों से पास हुई है लेकिन उस में से अभी तक केवल 20 लाख रु० ही दिया गया है। वह 20 लाख रुपये भी हुड्डा को दे दिया गया है क्योंकि जहां पर वाटर वर्क्स बनना है वह जमीन हुड्डा से ली है। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं पहले भी मंत्री जी को व मुख्यमंत्री जी को लिखित में अनुरोध कर चुका हूँ कि सोनीपत शहर के लिए पीने का पानी बहुत जरूरी है। सोनीपत में जो अनएप्रूवड कालोनियां हैं वहां तो पीने के पानी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात कहनी तो नहीं चाहिए मैं उन कालोनियों के लिए एक ट्रस्ट के माध्यम से पांच टैंकर पानी के पहुंचाता हूँ। वे ट्रक दिन में 60-70 चक्कर लगा कर उन कालोनियों को पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। जब तक उन कालोनियों में पानी के टैंकर नहीं पहुंचते तब तक उन लोगों के पास मुंह हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, उन कालोनीज में खारा पानी है। चुनाव के दौरान मैं एक कालोनी के एक मोहल्ले में गया था तो वहां मैं एक घर के सामने एक छोटी सी टेबल रख कर बात कर रहा था। मेरे सामने एक दरवाजे के अन्दर एक बुढ़िया बैठी थी। मैंने उससे कहा कि माता जी मुझे पानी पिला दो वह घर के अन्दर गई और 5-10 मिनट तक वह वापिस नहीं आई। फिर 5-10 मिनट के बाद आ कर उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने बच्चे को पानी लाने के लिए भेजा है। मैंने उस बुढ़िया से कहा कि यह सामने हैंडपम्प है इसका पानी मुझे पिला दें तो उस बुढ़िया ने कहा कि अगर इसका पानी मैं तुझे पिला दूंगी तो तू यहां से भाग जाएगा क्योंकि यह पानी नमक की तरह खारा है। फिर मैंने उस बुढ़िया से कहा कि आप यह पानी मुखिजा जी को पिला देना मुझे मत पिलाना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि अनएप्रूवड कालोनीज को पीने के पानी की और बिजली

[श्री देव राज दीवान]

सप्लाई की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि उन कालोनीज के लोग भी आम शहरी की तरह रह सकें। जो आम शहरी के लिए सरकार की तरफ से या म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उसी तरह से उन कालोनीज को भी वे सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उन कालोनीज की गलियों और नालियों को पक्का कराया जाए उनकी तरफ ध्यान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : दीवान साहब, आप कनकल्यूड करें।

श्री देवराज दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट का टाईम और दे दें मैं अपनी स्पीच समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सोनीपत शहर में सीवरेज की सुविधा को सुधारने के लिए जो कार्य शुरू किया है उसके लिए मैं सरकार का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सोनीपत में सीवरेज का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जो अनुमानित राशि खर्च की जानी है वह 82.92 लाख रुपये है जिसमें से अब तक विभाग को 22.67 लाख रुपये मिले हैं उसके बाद वहां पर सीवरेज का काम रुक गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे चालू वित्त वर्ष में शेष राशि भिजवाएं ताकि वहां पर सीवरेज का निर्माण कार्य पूरा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समाज कल्याण विभाग का संबंध है मैं राज्य सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगा चूंकि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि विधवा, विकलांग तथा वृद्ध लोगों को पैंशन का प्रत्येक मास की 7 तारीख तक भुगतान कर दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पैंशन बनाने की अवधि राज्य सरकार ने 26 फरवरी 1997 तक रखी थी लेकिन हल्का सोनीपत में बहुत से लोग पैंशन बनवाने हेतु कमेटी के समक्ष पेश नहीं हो सके। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके लिए थोड़ा टाईम और बढ़ाया जाए ताकि वे बुजुर्ग अपनी पैंशन बनवा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि चौधरी बलबीर सिंह जी ने उस दिन बोलते हुए यह बात कही थी कि विकलांगों को हर साल कमेटी के सामने न बुलाया जाए। विकलांगों की जब एक बार पैंशन बनाई जाती है वह पक्की पैंशन बना दी जाए ताकि उनको आने जाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अध्यक्ष महोदय का मुख्य मंत्री महोदय का और सारे सदन के सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मेरी बातों को बड़े प्यार से सुना। इसके साथ ही मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने हमारी सरकार को गिराने की बात की और इस सरकार को तोड़ने की बात की। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत हो जिस बिल्डिंग के खम्बे मजबूत हों क्या उस बिल्डिंग को कोई गिरा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मेरी एक बिल्डिंग गिराई थी उस समय केन्द्र में वी०पी० सिंह और चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी और उस सरकार में बी०जे०पी० भी भागीदार थी। उन्होंने मेरी बिल्डिंग गिराई। उस बिल्डिंग को गिराने में उनको साल सवा साल लग गया। उसको गिराने के लिए 35 लाख रूपये की मशीनरी खरीदी गई। आज तक उस बिल्डिंग के खम्बे खड़े हैं वह इतनी मजबूत बिल्डिंग थी। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में चौधरी बंसी लाल व मनीराम गोदारा, राम विलास शर्मा और भाई सुरेन्द्र सिंह जैसे खम्बे हों उस सरकार को कौन गिरा सकता है। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। जयहिन्द।

श्री मनीराम (डबवाली अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इन डिमांडज पर बोलने के लिए समय दिया। चुनावों से पहले हरियाणा विकास पार्टी के नेता चौधरी बंसी लाल जब लोगों के पास जाते थे तो ये अनेक वायदे करके आये थे। ये कहा करते थे कि

हम विकास के बहुत काम करेंगे। ये-ये विकास के कार्य करेंगे और लोगों को ये-ये सहुलियतें देंगे। गंगा का पानी लाने के लिए भी ये कहते थे और कहा करते थे कि मैं कन्याकुमारी से बिजली लाकर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह गंगा का पानी और कन्याकुमारी की बिजली कहां चली गई। यहां पर बिजली की हालत पर बोलते हुए बंसी लाल जी ने कहा कि इसकी चोरी हम नहीं रोक सकते क्योंकि जे०ई०, मीटर रीडर और जो लाईनमैन हैं उनकी गड़बड़ को रोकना मुश्किल है। इसलिए हम बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं और प्राईवेट हाथों में दे रहे हैं। यदि इन्होंने प्राईवेट हाथों में बिजली दे दी तो किसानों को बहुत महंगी बिजली मिलेगी। आज एक किसान को जब ट्यूबवैल लगाना होता है और उसके लिए बिजली का कुनैक्शन लेना हो तो उस एक किसान का 40 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। जब ये बिजली को प्राईवेट हाथों में दे देंगे तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस प्राईवेट क्षेत्र से किसानों को बिजली मिल पायेगी यह पौसिबल नहीं हो पायेगा। जब हमने कहा कि इसका निजीकरण न किया जाये और चारों तरफ से शोर मचा तो कहने लगे कि नहीं हम इसका निजीकरण नहीं कर रहे बल्कि इसका सुधारीकरण कर रहे हैं। जसवंत सिंह जी हमारे साथ पी०यू०सी० के मैम्बर थे। इनको जब बिजली का मंत्री बनाया गया तो इन्होंने कहा था कि मैं रहूंगा या बिजली रहेगी। मैंने कहा था कि आप इस्तीफा देकर यहीं आयेंगे और यही उनके साथ हुआ। ये उस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इनको बोलने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा। गलती जो एक बार हो जाती है उसकी भरपाई जल्दी से नहीं होती। हमारी सरकार तो सिर्फ 4 साल तक ही सत्ता में रह पाई थी। ज्यादातर समय तो कांग्रेस को और बंसी लाल को मिला है। इन्होंने इस हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया है। जो यमुना का समझौता हुआ था वह भजनलाल ने गलत किया था। उस समझौते के अन्दर बी०जे०पी० के भाई भी शामिल थे। बहन कमला वर्मा बैठी है, इनकी पार्टी शामिल थी। राजस्थान और दिल्ली में इनकी पार्टी की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उस समझौते में शामिल थी या नहीं। इन्होंने उस समझौते का विरोध नहीं किया। जब बंसी लाल जी अपोजीशन में बैठा करते थे तो ये भी इस समझौते का विरोध किया करते थे तो अब ये उस समझौते के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि अब इनका बी०जे०पी० के साथ समझौता हुआ है। गणेशी लाल जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। ये काफी लिखे पढ़े व्यक्ति हैं। इनके पास फूड एंड सप्लाई का विभाग है। मैं भी इस विभाग में रहा हूँ। (विघ्न) मेरी कौन सी ए०सी०आर० खराब थी। (हंसी) मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो डिपो पर गेहूँ मिलता है उसमें और जो मार्किट में मिलता है उसमें मार्जन के अन्दर बहुत ज्यादा अन्तर था। राशन की दुकानों के माध्यम से राशन की डिफैरैंट आईटम्ज़ का वितरण होता है। चावल, मिट्टी का तेल, गन्दम आदि इन राशन की दुकानों से कार्डों पर दिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लायक बजीर जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी अधिकारी ने किसी डिपो पर जाकर यह इन्क्वायरी की है कि जो चीज़ें लोगों को राशन कार्डों पर दी जाती हैं वह उन्हें मिलती भी हैं या नहीं। अधिकारी तो अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं और डिपो होल्डर राशन के वितरण में गड़बड़ घोटाले करते रहते हैं। गांवों के डिपो होल्डर तो महीने में एक या दो दिन ही राशन की दुकान खोलते हैं। लोग जब राशन की दुकानों पर जाते हैं तो वहां पर उनको राशन नहीं मिलता है। गांवों में राशन की दुकानें खोलना बहुत जरूरी है। वजीर साहब इस बात की ओर ध्यान दें कि डी०एफ०एस०ओ० इस बात को एन्श्योर करें कि उपभोक्ता को सही राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप राशन के वितरण का सर्टिफिकेट लें। 10% पैट्रोल पम्पों पर मिट्टी का तेल भी मिलता है लेकिन पैट्रोल पम्प वाले पैट्रोल में मिट्टी का तेल मिक्स करके बेचते हैं जिससे लोगों की गाड़ियों के इन्जनों का भट्ठा बैठ जाता है। सरकार को इस बारे में भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि पैट्रोल में पैट्रोल पम्प वाले मिट्टी के तेल की मिलावट न कर सकें। (विघ्न) जो राशन डिपुओं पर जाता है वह

[श्री मनीराम]

उपभोक्ताओं को नहीं मिलता है बल्कि ब्लैक में बेच दिया जाता है। डी०एफ०एस०ओ० से एक फार्म पर इस बात का सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिए कि राशन का वितरण सही हो गया है। राशन का सही वितरण हुआ है इस बारे में एक फेयर इन्क्वायरी करवाने के लिए ऐसी एजैंसी को भेजें जो कि सही प्रकार से चैकिंग करे। अगर सरकार सही चैकिंग करेगी तो इसमें गड़बड़ घोटाला जरूर मिलेगा। ठीक चैकिंग होने पर ही पता चलेगा कि कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला इसमें हो रहा है। डिपो होल्डर स्वयं सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं से इक्टठे कर लेता है। राशन कार्ड पर जो व्यक्ति गन्दम नहीं ले कर गया उसके कार्ड में गन्दम की एण्ट्री कर दी जाती है जो चावल नहीं ले कर गया उसके कार्ड में चावल की एण्ट्री कर दी जाती है। फिर वह राशन खुले बाजार में बेच दिया जाता है। डिपो होल्डर अपने डिपो भी टाईम पर नहीं खोलते हैं। डिपो होल्डर दुकानें निर्धारित समय पर खोलें यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने इलैक्शन के वक्त लोगों के साथ इतने ज्यादा वायदे कर लिए कि उनको पूरा करना सम्भव नहीं हो पाएगा। एक इन्होंने शराब बन्दी का भी वायदा किया लेकिन वह वायदा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है उल्टे उससे स्टेट को रैवेन्यू का नुकसान ही हुआ है। जो बजट सरकार ने रखा है वह बुल्कुल निकम्मा बजट है क्योंकि जो विकास योजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए। (विघ्न) रेलू राम की रेल तो बिल पानी बिन तेल चल सकती है लेकिन बिना पैसे के यह सरकार कैसे चलेगी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मद्रास में एक स्नेक पार्क बना हुआ है वहां पर सांपों को देखने पर टिकट लगा हुआ है इनको वहां भिजवा दें तो उससे टिकट से कुछ आमदनी सरकार को हो सकती है। (हंसी) शराब बन्दी के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि शराब तो स्टेट में पहले से भी ज्यादा बिक रही है। लेकिन इसके नाम पर हमें यह समझ नहीं आया कि 85 प्रतिशत लोगों पर टैक्स क्यों लगाया। कमला वर्मा जी यहां पर बैठी हुई हैं ये यह बतायें कि इस वजह से इनको एक हजार करोड़ रुपये के टैक्स मिले या नहीं मिले। आज भट्टों के लिए लाईसैंस नहीं मिलते हैं। आज भट्टों पर, होलसेलर, रिटेलर, बड़ा ट्रक, छोटा ट्रक ले लो, स्कूल, वकील, प्राईवेट नर्सिंग होम हैं सब पर टैक्स लगा है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उसने हमारी जान ही निकाल दी है। अगर बंसी लाल जी इसी हिसाब से चलते रहे तो हमारे यहां पर लड़कियों के रिश्ते होने बंद हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह कहावत है या चौपाई है। यहां सूरज भान जी ने पढ़ी थी वह मैं सुना देता हूँ * * * * * * यह जो वे कहते हैं कि आज हरियाणा में शराब बंद हो गई है यह बिल्कुल बंद नहीं हुई है। पिछले सैशन के वक्त भागी राम जी ने कहा था कि यह जो इन्होंने शराब बंदी करी है इससे हरियाणा में शराब बेचने वाला भाफिया पैदा होगा। तो मुख्यमंत्री बंसी लाल जी ने कहा था कि अब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला या भजन लाल नहीं है अब मुख्यमंत्री बंसी लाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मनी राम जी आपको सदन में या बाहर किसी भी देवी देवता के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मनी राम जी ने जो देवी देवताओं के बारे में बात कही है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। मनी राम जी आपको बोलते हुए 13 मिनट हो गये हैं आप जल्दी से कन्कलूड करें।

श्री मनीराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठने ही जा रहा था क्योंकि मेरे पास अब मसाला ही खत्म हो गया है। धन्यवाद (विघ्न) इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप सबको बोलने का समय दिया जाएगा। आप सब बैठ जाएं। जिस मैम्बर

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

को बोलने का समय नहीं दिया गया है उसको पहले बोलने का मौका दिया जाएगा। अब ओम प्रकाश जी बोलेंगे।

श्री ओम प्रकाश जैन (पानीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ वैसे तो मैं बैक बैन्चर हूँ और जब भी हमारा प्रश्न लगता है वह भी हमें पूछने का मौका नहीं लगता है। (विघ्न) मैं अपने सजपा के भाईयों को बताना चाहूँगा (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मनी राम जी ने बोलते हुए कहा कि शराबबंदी नहीं हुई है लेकिन मैं इनको कहे बिना नहीं रह सकता कि इस सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। मैं इस सरकार की कुछ उपलब्धियों के बारे में 14-00 बजे कहना चाहूँगा। मेरे इन भाईयों ने कई बातें शराबबंदी के बारे में कही हैं कि शराबबंदी नहीं हुई। यह सरकार फलां काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं इस सरकार में जब से हूँ उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि बंसीलाल जी जो भी कहते हैं वही करते हैं। जब पिछली सरकार के मुख्यमंत्री पानीपत में गये थे तो उन्होंने वहां जाकर लघु सचिवालय बनाने के लिए एक झूठा पत्थर रखा था। मैंने आज इस बारे में एक क्वैश्चन भी लगाया था लेकिन वह आज पूछा नहीं जा सका। मैं इसके माध्यम से पूछना चाहता था कि क्या लघु सचिवालय बन गया है। मंत्री जी ने उसके लिखित जवाब में बताया है कि अभी तक वह जगह तो डिफैंस के पास है। वह जगह अभी सरकार के पास नहीं आयी है। यानी उन्होंने उस समय झूठा ही पत्थर रख दिया था। जबकि बंसीलाल जी ऐसा नहीं करते। जहां तक शराबबंदी की बात है। ये कहते हैं कि शराबबंदी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये शराब पीकर दिखाएं जब इनको पता लगेगा कि शराबबंदी है या नहीं। यह तो आप मानेंगे ही कि शराबबंदी से पहले बहुत अत्याचार होते थे, बहुत जुल्म होते थे और बहू बेटियों की इज्जत लुटती थी। मैं गुजरात में तथा दूसरी जगहों पर भी गया था लेकिन सही मायनों में जिस तरह से हरियाणा में शराबबंदी हुई है और जितना बंसीलाल जी ने शराबबंदी पर कंट्रोल किया है वह शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। इसलिए मैं अपने इन भाईयों से कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। मैं एक व्यापारी भी हूँ और एक जमींदार भी हूँ। आप देखेंगे कि बिजली की कमी की वजह से ही आज के दिन हरियाणा में कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है। जब बिजली हमारे पास नहीं होगी तो यहां कौन इंडस्ट्री लगायेगा ? बिजली के सुधारीकरण या निजीकरण के लिए जो बंसीलाल जी ने पग उठाया है वह एक सराहनीय कदम है। यह पूरी स्टेट के लिए एक तरक्की का काम है। बंसीलाल जी हरियाणा को आगे ले जाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने बिजली के निजीकरण के बारे में सोचा है। मैं इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूँ। बंसीलाल जी ने हरियाणा में इंडस्ट्रीज लाने के लिए, हरियाणा को फलने फूलने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया है। मेरे यहां पर जो पानीपत की शूगर मिल थी वह पिछली सरकार के कारनामों की वजह से बंद हो गयी थी। लेकिन बंसीलाल जी ने जब ये पहली बार पानीपत में गये तो एक घंटे इन्होंने उसके बारे में ही बातें की कि किस तरह से यह मिल शुरु हो। पहले वह मिल घाटे में चल रही थी, लेकिन अगर आज आप देखें तो वह मुनाफे में चल रही है। ये भाई तो उसको बंद करवाने के लिए तैयार बैठे थे।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है, सर। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने यह बात बतायी थी कि पिछली बार इस मिल में बहुत घाटा था लेकिन अब उसमें सुधार हुआ है जबकि ये कह रहे हैं कि अब वह मिल मुनाफे में चल रही है।

श्री ओमप्रकाश जैन : अगर उसमें पहले बहुत भारी घाटा हो और अब वह घाटा कम हो गया हो तो उसको मुनाफे में ही कहा जा सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस मिल को बंद करने के मामले पर मेरे दल ने और दूसरे विपक्षी दलों ने एक प्रिवलेज मोशन पहले ही दिया हुआ है क्योंकि इस बारे में बातें तथ्यों के विपरीत थीं। रिकार्ड के विपरीत थीं। रिकार्ड के अंदर तो यह लिखा हुआ है कि इस मिल को बंद करने का फैसला किया गया है इसलिए मैं इनसे कहूँगा कि ये सोच समझकर ही रिकार्ड के मुताबिक अपनी बात कहें।

श्री ओमप्रकाश जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पानीपत कांस्टीच्यूएंसी है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। पिछली सरकार ने इलैक्शन के दौरान वहां पर पीने के पानी के ट्यूबवैल चालू नहीं किए। हमारे पानीपत में बहुत मजदूर रहते हैं। इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं और जो आउटर में कालोनियां हैं वहां पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। वहां पर जो दस नलकूप लगे हुए हैं वे एम०एल०ए० की ग्रान्ट से लगे थे उनको पब्लिक हैल्थ वाले टेक-अप नहीं कर रहे हैं। मेरी रिक्वैस्ट है कि उनको पब्लिक हैल्थ को देकर चालू करवाया जाए। मेरे पानीपत शहर में 40-45 कालोनियां ऐसी हैं जो शहर के बाहर हैं, जो न शहर में हैं, न म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में हैं, न देहात में हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन कालोनीज को म्यूनिसिपल कमेटी में लिया जाए ताकि उनमें रहने वाले गरीब आदमियों को सरकारी तौर पर उनका हक मिल सके। आज तक उन कालोनियों में रहने वाले लोगों के राशन कार्ड नहीं बनवाये गए थे। चौधरी बंसी लाल जी ने आते ही उन सब के राशन कार्ड बनवाये और उन्हें राशन दिलवाया । मैं ज्यादा न कहकर आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (नारनौल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (विघ्न) जो बजट सदन में पेश किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस पर पक्ष और विपक्ष सभी ने चर्चा की है। लेकिन जब इसका पूरा अध्ययन किया गया, सर्वेक्षण किया गया, उससे पता चलता है कि इस बजट को लाते समय हर पहलू को छुआ गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। मैं अपने माननीय साथियों को बताना चाहूंगा कि जब मैं चुनाव से पहले किसी भी गांव में या शहर में जाता था तो जनता चर्चा किया करती थी कि शराब ने सारे भारत वर्ष का नाश कर दिया है। इस शराब पर कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं आया, जो इसको बंद कर सके। इसके लिए सरकार को 600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ा यानी दो करोड़ रुपये रोज का रेवेन्यू का नुकसान उठाकर भी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारी सरकार ने तुरंत कानून बनाया। माननीय सदस्य मानते हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी बात है और इसको पूरी तरह से सफल किया जाये। इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का फर्ज बनता है कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा है कि जिस भी भाई को चाहे वह सरकार के पक्ष का हो या विरोधी पक्ष का हो चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो अगर शराब की बिक्री करता हुआ या पीता हुआ कोई आदमी मिलता है तो तुरंत पुलिस को बुलाये या सूचना दे उसको पुलिस उपलब्ध हो जायेगी। इसके साथ ही पिछले दिनों कुछ बातें हमारे सामने आई कि किसी शहर से किसी गांव में आखिरी बस से जाते हैं तो उसमें हमारी माताएं और बहनें नहीं जाती थी क्योंकि उसमें शराबी बैठे होते थे। माताएं बहनें या तो वे 4-5 बजे वाली बस से निकल जाया करती थी या फिर उसी शहर में रुक जाया करती थी। हम यहां से जब नारनौल जाते थे तो रोहतक-पानीपत होते हुए नारनौल जाते थे तो रास्ते में बीसियों शराबी बस में चढ़ जाया करते थे। वे कभी सवारियों पर गिरते थे, कभी कंडक्टर पर गिरते थे या कभी ड्राईवर पर गिरते थे जिसके कारण कई बार बसों का एक्सिडैंट हो जाता था। मेरे माननीय साथी मान रहे हैं कि वह हालत अब नहीं है। आप किसी भी बस

में जायें, किसी भी शहर में जायें किसी भी बाजार में जायें वहां बिल्कुल शांति की व्यवस्था रहती है। कई भाई चोरी छिपे तो पीते हैं इस तरह से कहीं न कहीं शराब की चोरी होती है। शराब बंदी से हमारे प्रान्त को काफी फायदा हुआ है। इसके साथ ही जो बिजली की बात आई है इसके बारे में मेरे सम्मानित साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 सालों से किसी भी गांव में अगर बिजली की समस्या हो और वह उसकी शिकायत करता तो चार-पांच रोज तो शिकायत-कर्त्ता घूमता रहता उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जब शिकायत दूर करने के लिए कर्मचारी जाते तो जो तार टूटा हुआ होता उसका ज्वायंट लगाने में शाम कर देते थे। अगर उस तार को किसी प्राईवेट आदमी से जुड़वाया जाये तो वह दो घण्टे में ठीक कर देता है और 50 रुपये में ही कर देता है जबकि सरकारी कर्मचारी जो दो जाते हैं उनका सारा दिन लगता है। उनकी तनख्वाह का हिसाब लगाये तो 250 रुपये बनते हैं। पिछले दस सालों से यह होता रहा है। इस तरह हिसाब लगाये तो रोजाना 6-7 लाख रुपये का नुकसान होता है। वह घाटा बढ़ता हुआ 2800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जो आज तक हरियाणा में लाईन लोसिज चल रहे हैं वह 31 प्रतिशत तक पहुंच गये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही बिजली के निजीकरण के बारे में सोचा जा रहा है ताकि जो लाईन लोसिज बढ़ते जा रहे हैं उनको दूर किया जा सके और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य इस क्षेत्र में हो सके। कुछ भाई चर्चा कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राईवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। इसका क्या कारण है? इसी से हमें समझ लेना चाहिए कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में और प्राईवेट स्कूलों की पढ़ाई में बहुत अंतर है। जिस तरह से प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है उसी तरह से बिजली का सुधार करने के लिए बिजली का निजिकरण करने की आवश्यकता है। बिजली के निजिकरण से बिजली में ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जा सकेगा। इसके साथ ही मेरी एक समस्या है। मंत्री जी अगर यहां पर बैठे हों तो कृपया ध्यान दें। हरियाणा सरकार के खेल विभाग ने जो गुड़गांव में एक होस्टल खोल रखा है उसमें हरियाणा से जितने भी खिलाड़ी सिलैक्ट होकर आये हैं उन में से 50 प्रतिशत खिलाड़ी मेरे हल्के के एक गांव के हैं। उस गांव में खेलने के ग्राउंड की समस्या है। इसी से संबंधित कुछ और भी समस्याएं हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे हल्के के एक ही गांव से गुड़गांव के होस्टल में 50 प्रतिशत् खिलाड़ी हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश से बाकी 50 प्रतिशत खिलाड़ी हैं। इस गांव में ज्यादा खेल की सुविधायें नहीं है। अगर आप कभी इस गांव में आओगे तो मैं आपको दिखाउंगा कि गांव के चारों तरफ खिलाड़ी खेलते ही रहते हैं। इसलिए उस गांव के खिलाड़ियों को खेलने की ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जानी चाहिए। मैं अपने हल्के की कुछ और समस्याएं रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जन स्वास्थ्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि नारनौल शहर बहुत ही प्राचीन शहर है और वहां पर सीवरेज का कार्य काफी दिनों से अधूरा है। इसलिए मैं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जो नहरों का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें नारनौल से उस तरफ 60-65 गांव हैं, उनमें अभी तक पम्प हाउसिज के काम रुके पड़े हैं। उनमें अभी तक पानी की शुरुआत नहीं हुई है। उन पम्प हाउसिज को जल्दी से जल्दी चालू किया जाये। इसके साथ ही मैंने पहले भी एक प्रश्न किया था कि दोहान और कृष्णावती नदियों पर छोटे छोटे बांध बांधे जाएं जिससे आसपास के गांवों में पानी का जलस्तर ऊपर आ सके। उससे हमारे किसानों को भी काफी फायदा होगा क्योंकि महेन्द्रगढ़ जिले में खास तौर से नारनौल क्षेत्र में ज्यादातर सिंचाई ट्यूबवैलों से होती है। वहां पर नहरें बहुत कम हैं। इसलिए वहां पर जो नदी हैं, उन पर बांध बांधना बहुत ही जरूरी है, जिससे पानी का जलस्तर ऊपर आ सके। इसके अतिरिक्त मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ जिले में जो सबसिडी देने की व्यवस्था है, उसको चालू रखा जाए। उस जिले में गरीब किसान हैं तथा ज्यादातर नौजवान फौज में हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा

[श्री कैलाश चन्द्र शर्मा]

सुविधाएं दी जाएं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि महेन्द्रगढ़/नारनौल में जो पैंशन विभाग के अधिकारी हैं, उनको मैंने 35 विधवाओं की लिस्ट दी थी, अगर बहिन जी चाहें तो मैं इन को भी वह लिस्ट दे दूंगा, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस अधिकारी ने यह कहा कि इस नारनौल अर्थात् महेन्द्रगढ़, जिले में विधवाएं बहुत ज्यादा हैं। इस पर मैंने उसकी पिटाई तो नहीं की। बाकि उसकी 2-3 घंटे खिंचाई जरूर की और उससे हमने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए जो महेन्द्रगढ़ नारनौल की विधवा औरतें हैं उनके बारे में आप ऐसी बात कह रहे हैं। उन विधवाओं के पति देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। भारतवर्ष की फौज में सबसे ज्यादा प्रतिशतता महेन्द्रगढ़ नारनौल और रिवाड़ी जिलों के नौजवानों की है जो देश की सेवा में काम करते हैं और उनकी औरतों की इज्जत सही सलामत है। जो व्यक्ति देश की रक्षा करते हुए युद्ध में शहीद हो गये उनकी विधवा औरतों के बारे में आप यह कहते हैं कि महेन्द्रगढ़ नारनौल जिले में बहुत ज्यादा विधवाएं हैं आपको शर्म आनी चाहिए। उस अधिकारी के बारे में मैं बहन जी को बताना चाहूंगा कि आप उसको बोलना सिखाएं और यह भी बताएं कि इस तरह की बात कहनी होती है या नहीं। मैं एक बात हमारे मंत्री रामा जी को बताना चाहूंगा कि जहां सारे हरियाणा प्रदेश के 50 प्रतिशत खिलाड़ी एक तरफ हों और एक गांव के 50 प्रतिशत खिलाड़ी एक तरफ हों तो उस गांव के खिलाड़ियों का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा कि गुड़गांव के अन्दर खिलाड़ियों के लिए एक होस्टल बनाया हुआ है उसमें केवल दो हज़ार की आबादी के एक गांव के 50 प्रतिशत खिलाड़ी हैं और 50 प्रतिशत सारे हरियाणा से हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उस गांव के खिलाड़ियों को खेल का ज्यादा से ज्यादा सामान दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं इस बजट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि आज की सरकार ने सारे हरियाणा की जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके जरिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जयहिन्द।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु (पेहवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांडज पर बोलने का जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 13 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि 1953-54 में मेरी कांस्टीच्यूएंसी में कुछ पुराने फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को कुछ जमीन पट्टे पर अलाट की गई थी इस बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर जब जनरल इलैक्शन हुए तो इस प्रदेश में चौधरी बंसी लाल जी की सरकार बनी। हमने भी इलैक्शन लड़ा था हमारा भी मैनिफैस्टो था। कांग्रेस पार्टी ने भी इलैक्शन लड़ा था उसका भी मैनिफैस्टो था। लेकिन जब इस प्रदेश में चौधरी बंसी लाल जी की सरकार बनी तो, मैं यह अपनी जाति राय व्यक्त कर रहा हूँ। यह सरकार मेरी सैकिण्ड च्वायस थी क्योंकि हम सत्ता में नहीं आ सके। चौधरी बंसी लाल जी सत्ता में आये तो मैंने एक ही बात समझी कि कम से कम पिछली सरकार से तो हमारा पीछा छूटा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, उस पार्टी की सरकार के वक्त में 1982 के अन्दर जो एशियन गेम्ज हुए थे उस समय और 1984 के रायटस में हमारे साथ जो सलूक किया गया था उसको हम आज भी नहीं भूले हैं। हरियाणा प्रदेश के किसान, मज़दूर और हरिजनों यानी 36 बिरादरियों की जनता के साथ लगातार कई साल तक कुठाराघात हुआ जिसके कारण प्रदेश के गरीब लोग आर्थिक तौर पर पिछड़ गये। हमने तो सोचा था और हमें उम्मीद थी कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में शायद कोई सुधारीकरण आयेगा लेकिन आज 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी जो बात हमें महसूस हुई है उससे हमें निराशा ही हाथ लगी है क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर बिजली का बहुत बुरा हाल है। मेरे से पूर्व बोलने

वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मुझे इस बात की यहां पर विशेष रूप से चर्चा करनी है कि पट्टेदारों को जो जमीन दी गई थी उनकी बात मैं करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, ऐसे ही कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है। वहां पर पट्टेदार जिनके पास 77 हज़ार एकड़ भूमि थी, उनको सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मालिकाना हक दे दिया है। स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्यूएसी के पट्टेदार हैं और कुछ गुहला कान्स्टीच्यूंसी में पट्टेदार हैं। इस सरकार ने बनने के बाद ऐसे पट्टेदारों को बेदखल कर दिया है। इन्होंने एक डिसीजन लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है। स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि इनको 20 साल के पट्टे पर यह जमीन दी गई थी। अब इनका पूरा कब्जा नहीं बनता । स्पीकर साहब, 1953-54 के अन्दर गुहला और पेहवा का इलाका बिल्कुल बियाबान जंगल था। 5-7 साल उन लोगों को जंगल को तोड़ने में लगे और फिर 2-4 साल उसका लैवल करने में लगे। तब कहीं जाकर कोई आमदनी का साधन शुरू हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री जसविन्द सिंह संधु : स्पीकर साहब, मेरी बात सुनें। (विघ्न)

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, कैसी अजीबो गरीब बात है। जब सदन का समय बढ़ रहा है तो ये विरोध कर रहे हैं। (विघ्न) मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी माननीय सदस्यों को बुलाएं ताकि वे अपनी सारी बातें कह लें। परन्तु इनसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जब हम जवाब दें तब ये सब लोग यहां बैठे रहें। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : स्पीकर साहब, मैं आपसे कह रहा था कि उन बहादुर पैंशनरी फौजियों ने 8-10 साल उस जमीन को आबाद करने में लगाए और फिर 3-4 साल उसका लैवल करने में लगाये तो क्या अब उनको बेदखल किया जाना ठीक है ? उनको 10 वर्ष खेती करते हुए हो चुके थे। 1973 में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल थे। हमारे भाई बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि हमें तो पहले वाले चौधरी बंसी लाल चाहिए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमें पहले वाले बंसी लाल नहीं चाहिएं। शायद आज वाले उनसे ठीक हों क्योंकि इस 73 वाले बंसी लाल के स्वयं भुगतभोगी हैं। स्पीकर साहब, उस समय के बंसी लाल के समय में उन पट्टेदारों के हाड तोड़े गये थे। इनको प्रदेश की जनता ने फिर 20 साल बाद याद किया है। उस इलाके के सरदार तो इनको हर सर्दियों में याद करते हैं जब उनके हाड़ दुखते हैं, सर्दी के मौसम में। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने वह 77 हज़ार एकड़ भूमि उन पट्टेदारों को दे दी है, उनको मालिकाना हक दे दिया है उसी तरह से हमारे यहां पर भी उनको हक दे दिया जाना चाहिए। मेरा कहना है और सरकार से निवेदन है कि गुहला और पेहवा के पट्टेदारों को वह हक मिलना चाहिए। यह मेरी बंसी लाल जी से पुरजोर अपील

[श्री जसविन्द्र सिंह संधु]

है क्योंकि इन सब पट्टेदारों ने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था और वे सुभाष चन्द्र बोस की आज़ाद हिन्द फौज के फौजी थे। उन्होंने एक लम्बी लड़ाई लड़ी हुई है। उस समय उनको 10-10 एकड़ भूमि अलाट की गई थी। आज वहां 4-4 परिवार उनके हो गये हैं। उनके पोतों की शादी हो गई है। आज उनके पास डेढ-डेढ किले और दो-दो किले से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं है। इसलिए मैं विधान सभा में पुरजोर यह अपील करता हूँ कि इस फैसले पर सरकार स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करे। जिनको इस जमीन का पट्टा 20 साल पहले दिया गया था उन लोगों को वह पट्टा सरकार को दोबारा देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोबारा पट्टा दिया जा सकता है। स्पीकर सर, इस मांग को लेकर पेहवा से एक डैपुटेशन वित्त मंत्री महोदय को मिला था और उनको यह बताया था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारी दुकानों के नक्शे 30-35 साल पुराने बने हुए हैं और हमारे पास इस बात का सबूत भी हैं। कुछ केसों में मुकद्दमें भी चल रहे हैं। उन दुकानों को तोड़ने के लिए एस०डी०ओ० (सिविल) बार-बार आ जाता है। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि वहां पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए। यहां पर उन्होंने आश्वासन भी दिया था और शायद अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिये थे लेकिन 10 दिन बाद ही फिर से मकान तुड़वाने का काम शुरू कर दिया गया। जब काफी लोगों ने विरोध प्रकट किया तब जा कर वह रुक सका था। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं डिमाण्ड नं०-15 जो कि सिंचाई के बारे में है, पर अपने कुछ सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि एम०आई०टी०सी० के नरवाना ब्रान्च के साथ-साथ डीप टयूबवैल्ज़ लगे हुए हैं। उन टयूबवैल्ज़ की वजह से उस हल्के का वाटर टेबल 70-80 फुट नीचे तक चला गया है। वाटर टेबल बहुत नीचे चले जाने के कारण वहां के किसानों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उन डीप टयूबवैल्ज़ को सरकार द्वारा बन्द कर देना चाहिए। मैं यह बात मानता हूँ कि जिस वक्त ये टयूबवैल्ज़ लगाये गये थे उस वक्त उनकी जरूरत थी लेकिन आज उनकी जरूरत नहीं है। हमारा ऐरिया पैडी ऐरिया है जिला कुरुक्षेत्र और करनाल में पैडी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर पैडी रोज़ सीड दिया जाता था। स्पीकर सर, यह सीड पहले जून की समाप्ति पर दिया जाता था लेकिन आजकल 15-20 अप्रैल के आस-पास पैडी बोने की आवश्यकता है इसलिए वह बीज इन दिनों में मिल जाना चाहिए। इसके साथ ही मेरी यह भी गुजारिश है कि मोघों का साईज़ बढ़ाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस के साथ ही मैं कृषि के बारे में डिमांड नं०-17 पर बोलना चाहता हूँ। सबमर्सिबल पम्प लगाने में किसान का डेढ से दो लाख रूपये तक खर्च हो जाता है उसके लिए न तो कोई लोन दिया जाता है और न ही उसकी इन्श्योरेंस ही हो सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सबमर्सिबल पम्प की इन्श्योरेंस भी जरूर होनी चाहिए ताकि अगर किसी किसान का सबमर्सिबल पम्प फेल हो जाये तो उसको वह पैसा रि-इम्बर्स हो सके, किसान को उसका कम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसके साथ ही किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए। स्पीकर सर, इसी के साथ मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस वर्ष किसान ने गन्ना बहुत ज्यादा बोया हुआ है और अभी भी खेतों में काफी गन्ना खड़ा हुआ है। (विघ्न) (घण्टी) इसलिए सरकार यह प्रावधान करे कि जब तक किसान का गन्ना खेतों में खड़ा है तब तक शूगर मिल बन्द नहीं होने चाहिएं। किसानों का खेतों से गन्ना उठने तक मिलें चलती रहनी चाहिएं। मिलें बन्द हो जाने से गन्ने की रिकवरी कम हो जाती है। इसके साथ ही किसान को गन्ने का मुल्य जो सरकार ने तय किया है वही मिलना चाहिए। उसको आज 62 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। सरकार ने गन्ने का जो भाव तय किया हुआ है, वही भाव 76-78 या 80 रुपये का जो भाव है वही उसे मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं चाहता हूँ कि इन डिमान्डज पर वोटिंग करवाई

जाए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार बीस साल के काफी लम्बे अर्से के बाद आई है इस बारे में मैं आपको एक शेयर सुनाता हूँ।

मस्जिद तो बना दी पल भर में,
इमां की हरारत वालों ने।
यह मन ही पुराना पापी था,
बर्षों में नमाजी बन न सका।।

इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे डिमान्डज पर बोलने का समय दिया।

श्री दिलू राम (गुहला, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं कृषि के बारे में आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूँगा कि यहां पर जितने भी नुमायंदे चुनकर आये हैं उनमें से आधे से ज्यादा कृषि क्षेत्र से हैं और वे कृषि पर निर्भर करते हैं। वे अपने आपको ज़मीदार कहते हैं। स्पीकर साहब, जितने भी कृषि से सम्बन्धित यंत्र हैं उनको कर से मुक्त करना चाहिए। सरकार ने ट्रैक्टर के टायर के ऊपर टैक्स माफ किया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जहां तक इस सरकार ने धूप बत्ती पर टैक्स माफ किया है उसी तरह से सरकार को ट्रैक्टर पर भी टैक्स माफ कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान हूँ। एम०एल०ए० बनने से पहले हमने 10-15 साल अपने इन्हीं हाथों से हल चलाया है। किसान ने जब खेतों में पानी देना होता है तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो उसे दिन रात खेतों में रहना पड़ता है। पानी देते वक्त उसके पैर के नीचे सांप आ जाता है, कभी कुछ आता है। अगर चलते-चलते गिर जाए और नीचे कस्सी आ जाए तो वहीं पर मर जाता है। आज यह सरकार किसानों के बारे में दुहाई देती है। मेरे से पहले दलाल साहब ने कहा था हम डीजल पम्प पर सबसिडी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे 10 हार्सपावर के डीजल इंजन पर सबसीडी देने की बात कर रहे हैं। आप यह सबसीडी जनरेटर सैट पर क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, दिलू राम जी ने यह बात दोबारा से उठाई है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार के वक्त में डीजल पम्प सैट के ऊपर और जैनरेटर सैट पर 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाती थी हम उसको 33 प्रतिशत करने का विचार कर रहे हैं। जहां तक ट्रैक्टरों की बात है तो हमारी सरकार इस बर्ष से किसानों को 30 हज़ार रूपये ट्रैक्टर खरीदने के लिए सबसिडी देने की सोच रही है। (विघ्न)

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, जो ये कहते हैं 30 हज़ार रूपये हमने ट्रैक्टर की सबसिडी के लिए रखे हैं तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि ये इस पैसे को कहां से देंगे क्योंकि इस बारे में इन्होंने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। लेकिन ट्रैक्टर्ज पर सबसिडी देने के बारे में बजट में तो कुछ नहीं है। (विघ्न) कितने हार्स पावर पर इन्होंने छूट दी है यह तो ये ही जानें। (विघ्न) सर, मैं वही बात कहूँगा जो सबके हित में होगी। आज मेरे हल्के में पानी 70-75 फुट तक नीचे चला गया है। पहले यह पानी दस या पन्द्रह फुट तक होता था। इसके अलावा वहां पर कूओं में गैस होने लग रही है। इस सरकार के आने से पहले वहां काफी लोगों की मौतें गैस की वजह से हो गयी हैं। पहले वहां पर ट्यूबवैल के लिए सात हार्स पावर की मोटर ही लगाया करते थे लेकिन अब पानी का लेवल नीचे चले जाने के कारण दस हार्स पावर से कम पावर की मोटर काम नहीं करती है। अगर कोई किसान अपने यहां पर सबमर्सिबल ट्यूबवैल लगाए तो क्या सरकार उसको उस ट्यूबवैल पर अपने जैनरेटर सैट लगाने के लिए कम से कम

[श्री दिलू राम]
50 परसैंट सबसिडी देगी ? अध्यक्ष महोदय, जैसे सरकार एक उद्योगपति को छोटी सी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसिडी देती है वैसे ही सरकार को किसान को भी जैनरेटर सैट पर सबसिडी देनी चाहिए। किसान के लिए तो उसकी वही इंडस्ट्री है। मेरा सरकार को सुझाव है कि इस पर वह पूरी तरह से गौर करे। अगर जमींदार को ऊपर उठाना है तो जब तक यह सबसिडी उसको नहीं दी जाएगी तब तक वह ऊपर उठने वाला नहीं है।

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) अध्यक्ष महोदय, अभी एक फरवरी को सरकार ने गंगा कल्याण योजना नाम की एक स्कीम लागू की है। इसके तहत 75 परसैंट सबसिडी हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोगों को ट्यूबवैल पर तथा 50 परसैंट सबसिडी स्माल फार्मर्ज के लिए ट्यूबवैल पर दी जाएगी। अगर चार पांच फार्मर्ज मिलकर कोई सोसायटी बनाकर ट्यूबवैल लगाना चाहें तो उनको चालीस हज़ार रुपये की सबसिडी मिलती है और अगर कोई सिंगल फार्मर ट्यूबवैल लगाना चाहता है तो उसको मैक्सीमम 12.5 हज़ार रुपये की सबसिडी मिलती है।

श्री दिलू राम : मैं छोटे किसानों की नहीं बल्कि सभी किसानों की बात कर रहा हूं। लेकिन चलो आपकी मेहरबानी कि आप छोटे किसानों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं भी छोटा किसान ही हूँ। स्पीकर साहब, मैं एक बात और अपने हल्के गुहला के बारे में कहना चाहता हूँ। उस हल्के का अभी तक यह दुर्भाग्य ही रहा है कि 1972 से लेकर आज तक वहां से कोई एम०एल०ए० रूलिंग पार्टी का नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष : आप 1977 के बारे में बताएं।

श्री दिलू राम : 1977 में जो एम०एल०ए० बना था अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो मेरे ये भाई चिढ़ जाएंगे। वह एम०एल०ए० जनता पार्टी का था लेकिन जिस तरह से जनता पार्टी चली गयी उसका आपको पता ही है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। (विघ्न) जैसा कोई बोएगा वह वैसा ही काटेगा। सर, मैं अपने हल्के के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर आज सड़कों की बहुत ही बुरी दशा है। उस दुर्दशा का मेन कारण यह है कि वहां पर 1993 में और 1995 में बाढ़ आयी। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने उस हल्के की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हर साल बाढ़ आती है जिस वजह से सड़कों की हालत और खराब होती जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद जानते हैं क्योंकि आप भी देहात के ही रहने वाले हैं। आज वहां पर यह हालत है कि लोग पक्की सड़कों पर चलना ही नहीं पसन्द करते क्योंकि उन पर पक्की नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। बाढ़ ने सब सड़कें खत्म कर दी। आज लोग पक्की सड़कों के बजाए कच्ची सड़कों पर ही चलना चाहते हैं। इसी तरह से मेरे यहां पर नहरों की भी बहुत बुरी दुर्दशा है। जब बंसी लाल जी मुख्य मंत्री बने थे तो मैं स्वयं इनसे मिला था और इनसे कहा कि आपके बारे में लोगों की यह सोच है कि चौधरी बंसी लाल की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। क्या आप वही हैं तो ये कहने लगे मैं वही हूं। मैंने कहा 5-6 साल से मेरे हल्के में टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो ये कहने लगे कि आप लिखकर दे दो। मैंने सभी गांवों के नाम लिखकर इनको दे दिए जहां टेल पर पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन आज तक किसी टेल पर पानी नहीं पहुंचा। यह सबूत है मैं इस बारे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। जब वह नहरें कच्ची थी तब कुछ पानी फिर भी पहुंचता था लेकिन पक्की होने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पहुंचता है। मैं वहां के जे०ई० और एस०डी०ओ० से पूछता था कि पानी क्यों नहीं पहुंचता है ? वे कहने लगे कि इसका टेल का जो लेवल बनाया गया है वह आगे से ऊंचा कर दिया गया है लेवल ऊंचा होने की वजह से पानी का बहाव कम हो गया है और टेल पर

पानी नहीं पहुंचता है। मेरा पैडी एरिया है वहां पर जीरी लगती है।सरदार जसविन्द्र सिंह जी और मेरे हल्के की एक ही बात है 40-45 साल पहले जब भारत/पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब वहां से जो लोग आए थे वे लोग उस समय से वहां बैठे हुए हैं। वह लैंड पंचायत की है। उन लोगों के दिलों में यह डर बैठा हुआ है कि सन् 1970 में जब चौधरी बंसी लाल मुख्य मंत्री थे, तो उस समय इन्होंने कई गांव खाली करवाए थे तो वे लोग यही सोचते हैं कि हमारे साथ कहीं वही बात तो नहीं हो जाएगी। स्पीकर सर, अगर ऐसा हुआ तो यह अनर्थ हो जाएगा। वे लोग कहां जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि उस जमीन की कीमत तय करे और उनको किश्तों पर दे दे ताकि वे लोग उस जमीन को ले सकें और वहां बस सकें। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मैं बिल्कुल टेल पर हूं। मेरे हल्के के साथ पंजाब का 70 किलोमीटर का एरिया लगता है साथ लगते पंजाब में तो 24 घंटे बिजली आती है लेकिन हमारे यहां कुछ घंटे ही आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक दुकान पर तो फ्री सामान मिले और दूसरे पर पैसे से मिले तो यह कैसे चलेगा। हमारे यहां के किसानों को भी बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए। अगर सरकार जमीदारों की रक्षक है तो वह जमीदारों को बिजली पानी फ्री दे। जैसे उस दिन लाला जी ने बजट में कहा कि पहले सेल्ज टैक्स 4 परसैंट था अब हमने एक परसैंट कर दिया और उससे इंकम बढ़ गई है। जैसे चार से एक परसैंट करने पर इंकम बढ़ जाती है तो चार परसैंट क्यों लगाया जाए। जमीदार की खाल क्यों उतारते हो। इसके अलावा आज बिजली की बहुत जरूरत है और उसका आप निजीकरण करने जा रहे हैं। मैं एक बात यह कहूंगा कि उससे जमीदार को कोई फायदा नहीं है। आप निजीकरण करें या न करें मैं तो यह चाहूंगा कि बिजली आनी चाहिए। मेरा हल्का पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है। रोपड़ से लेकर अम्बाला तक का बाढ़ का पानी मेरे हल्के से गुजरता है। वह तो भला हो घग्घर नदी का जिसकी कपैसिटी 27 फुट पानी लेने की है उसका 27 फुट तक पानी बाहर नहीं निकलता। घग्घर नदी, टांगरी नदी और मारकण्डा नदी, तीनों नदियों का पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो इसकी कपैसिटी 27 फुट की हो जाती है जब 27 फीट से ज्यादा पानी हो जाता है तो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पिछले साल 8-9 गांवों में फलुड आया उस फलुड से जो नुकसान हुआ उसका लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। पटवारी वहां गया था और उसने गिरदावरी भी की थी लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला है आगे मिल जाए तो पता नहीं। इसके बाद मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के के साथ एजूकेशन के मामले में बड़ा भेदभाव हुआ है। हमें नहीं पता कि नए स्कूल खोलने का और स्कूलों को अपग्रेड करने का आपका क्राईटेरिया क्या है ? मुझे नहीं पता कि प्राईमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करने के लिए क्या क्राईटेरिया होना चाहिये। स्पीकर सर, आपके इलाके में ढाणियां बोलते हैं और हमारे यहां उनको डेरे बोलते हैं । 6-7 डेरों के लिए एक स्कूल होता है और ऐसे 200 डेरे हैं। बजट में उन डेरों के स्कूलों के बारे कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन डेरों के कई स्कूल अभी तक ऐसे हैं जहां मास्टर नहीं हैं, विद्यार्थी बेकार बैठे हैं। स्कूल की बिल्डिंग बेकार होती जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम प्लस-टू के स्कूल शिवाल और भागल में जरूर खोले जायें क्योंकि मैट्रिक करने के बाद लड़कियों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। वे कहां पढ़ने जाएं। वहां पर हाई स्कूल भी 3-4 से ज्यादा कर दें तो अच्छा है। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

श्री जगदीश नैयर (हसनगढ़, अनुसूचित जाति) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। (विघ्न)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि 1986 से लेकर 1997 तक का 11 साल का रिकार्ड उठाकर देख कर मैंने आपको बता भी दिया था कि उस दौरान सदस्यों को बोलने के लिए कितना समय दिया जाता था और अब कितना समय दिया गया है। इस सैशन में आपको काफी समय दिया है फिर भी मैं आपको बोलने के लिए टाईम दूंगा। विपक्ष के 22 एम०एल०एज० हैं जिनमें से 21 को समय मिल चुका है। (विघ्न) या तो गवर्नर एड्रैस पर या बजट पर आपको समय मिल चुका है। (विघ्न) भागीराम जी बैठिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि असैम्बली का पिछले 11 साल का रिकार्ड आपके सामने है। आप में से काफी सदस्य पक्ष और विपक्ष में रह चुके हैं। सदस्य चाहे इस पक्ष का हो या विपक्ष का हो आखिर उसमें पेशंस होनी चाहिये। पेशंस के हिसाब से टाईम देंगे। विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होगी। (विघ्न) अगर किसी मैम्बर को गवर्नर एड्रैस या बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला है I assure he will get time to speak.

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मुझे भी टाईम दें।

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी आपको समय मिल चुका है। इनको नहीं मिला है। मैंने बताया है कि विपक्ष के एक सदस्य को समय नहीं मिला है। (विघ्न) अब जगदीश नैयर जी को बोलने दें।

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांडज़ पर बोलना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री महोदय ने सामाजिक विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही अच्छा है। मैं अपने हल्के की तरफ से व अपने जिले की तरफ से इसका स्वागत करता हूं। यह बजट इतना अच्छा है कि पहले कभी ऐसा बजट नहीं देखा गया है। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि पहली बार मैं एम०एल०ए० बनकर यहां पर आया हूं। यह बजट चाहे कोई भी क्लास है या कोई भी जाति है, सभी के कल्याण के लिए है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय, तथा इस समस्त सदन का स्वागत करता हूं। मुख्य मंत्री महोदय ने शपथ लेते ही शराबबंदी का जो वायदा किया था वह पूरा कर दिया है। आप यह बताइए कि जो वायदे पिछली सरकारों ने किए थे, उन्होंने उनको पूरा किया है ? चौधरी भजन लाल जी ने तथा चौटाला साहब ने जितने वायदे मुख्य मंत्री बनने से पहले किए थे वे कभी भी पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ हमारे मुख्य मंत्री ने शराबबंदी का वायदा किया था, उसको उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही एकदम लागू कर दिया। यह विपक्ष के भाई कहते हैं कि शराब बंद नहीं हुई है। यह इनके मुताबिक बंद नहीं होगी, लेकिन हमारे मुताबिक तो बंद है। हरियाणा के सभी एस०पीज० व डी०सीज० की रिपोर्ट है कि शराबबंदी के मामले में हम काफी प्रोग्रैस कर रहे हैं। शराब माफिया को पकड़ रहे हैं। (विघ्न) इसलिए यह जो शराबबंदी का कार्य किया गया है यह बहुत ही अच्छा है। मेरा अहोभाग्य है कि मैं एक ऐसे मुख्य मंत्री के हाथों पड़ा हूं जो कि सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी हैं। मैं इनका कभी भी अहसान नहीं भूलूंगा और न ही किसी के बहकावे में आऊंगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शराब के ठेकेदारों ने आतंक फैला रखा है, और शराब के माफिया जो हैं, उनको विपक्ष के नेताओं ने पैदा किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश हमारा साथ दे रहा है। इसके स्पष्ट उदाहरण भी हैं। चौधरी भजन लाल जी के आदमी की फैक्टरी जो कि अभी भी चल रही थी, शराब का माफिया उस से सहयोग ले रहा था। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सरकार जन कल्याण के लिए होती है, विनाश के लिए नहीं होती है। पिछली सरकार ने मनुष्यों का कल्याण नहीं किया बल्कि उसके उलट कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने 9 महीने हो गए हैं लेकिन आज तक कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है, जोकि इस सरकार की विफलता दर्शाती हो। हमारे मुख्य मंत्री जब भी बोलते हैं तो विपक्ष के सदस्य वाक-आऊट कर जाते हैं। जिस शराब के कारण हमारा प्रदेश

तबाह हो चुका था, माताएं, बहने तबाह हो चुकी थीं शराब बंद होने के बाद आज सुख की सांस ले रही हैं। प्रदेश का हर व्यक्ति यह कह सकता है कि आज बहनों की इज्जत सुरक्षित है। विपक्ष के साथियों ने कानून और व्यवस्था की बात की, प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये सुशीला, रेणुका और द्रौपदी कांडों को भूल गए। आज हरियाणा प्रदेश में शांति है फिर भी ये ऐसी बातें करते हैं। उस वक्त ये कहां थे ? उस समय कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी जब वे काण्ड हुए थे। अध्यक्ष महोदय, कल दलाल साहब ने जो बातें बताईं ऐसी बातों का हमें पता भी नहीं था। जब ये कल जमकर बोले तो इन दोनों भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों में से एक भी यहां पर नहीं था। 15.00 बजे अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरा हसनपुर विधान सभा क्षेत्र है जिसे लोग पारवा क्षेत्र भी कहते हैं और यह भी कहते हैं कि वह तो पार के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, जिन मुख्य मंत्रियों ने पिछले 20 सालों में इस प्रदेश पर राज किया वह मुख्य मंत्री उस क्षेत्र में जाते थे और वहां पर रैलियां करते थे। लोगों को बहकाते थे। लोगों का पैसा खर्च करवाते थे और लोगों से वोट ले कर चुनाव जीत कर यहां चण्डीगढ़ में आ कर बैठ जाते थे। हमारे मुख्य मंत्री जी को मैंने शायद मेरी उम्र में अब देखा है। वे मुख्य मंत्री कहते थे कि हसनपुर क्षेत्र तो पार में लगता है इसलिए वह तो पार का क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसके बारे में आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि उस क्षेत्र का कितना बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, हसनपुर क्षेत्र की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है। वहां पर चलने के लिए सड़कें नहीं हैं। वहां पर लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। उस क्षेत्र के किसानों के सामने बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने मेरे क्षेत्र के किसानों का बहुत विनाश किया और उनके साथ भेदभाव किया। मेरे क्षेत्र के नौजवान साथियों के साथ नौकरियों में भेदभाव किया। मैं आपके माध्यम से इस सदन से जानना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के साथ वह भेदभाव क्यों किया गया ? जो भी सरकार आई मेरे क्षेत्र के लोगों ने उस सरकार के आदमी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे कर यहां विधान सभा में भेजा लेकिन फिर भी वह क्षेत्र नैगलैक्टिड रहा। इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ नौकरियों में बहुत भेदभाव किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री महोदय 7-8 दिन पहले मेरे साथ मेरे क्षेत्र में गये थे और इन्होंने वहां जा कर एक नदी का उद्घाटन किया। उस नदी का काम 300 लाख रूपये में पूरा होगा। उस नदी का काम शुरू हो गया है। पिछली सरकार ने हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई काम कभी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने बिजली के निजीकरण के बारे में बहुत बातें कहीं। जब ये किसी बात का बिरोध करते हैं तो उसका जम कर विरोध करते हैं लेकिन इनको यह पता नहीं है कि उसका क्या परिणाम निकलता है। इन्होंने बिजली के बारे में जम कर विरोध किया। जब पहले चौधरी बंसी लाल जी ने अपने शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम प्रारम्भ किया था उस समय भी ये यही सोचते होंगे कि बिजली की हालत खराब होगी। अब भी इनके दिमाग में यह बात जमी हुई है कि जो बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं इससे बहुत खराबी होगी। अध्यक्ष महोदय, बिजली के निजीकरण से मेरे विरोधी भाईयों को निजी नुक्सान है न कि किसान को। मेरे विरोधी भाईयों ने 24 घंटे बिजली देने के बारे में कहा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारी चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने यह वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आप देखते रहना हमारी सरकार 2-3 साल के अन्दर अन्दर 24 घंटे बिजली देगी। फिर आप इस बारे में तर्क वितर्क करना आपको उसका जबाब मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। शिक्षा के मामले में पिछली सरकार ने मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया

[श्री जगदीश नैयर]

था। जो देखने में बड़ा दर्दनाक है। मेरे क्षेत्र में न कोई डिग्री कालेज है और न कोई आई०टी०आई० है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा संस्थान खोलने का कोई न कोई उपाय अवश्य किया जाए। वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो भी चीफ मिनिस्टर जाता है वह अपनी रैलियां करवाता है वहां के लोग उसको अपना विश्वास दे देते हैं और उसकी पार्टी के आदमी को विधायक बना कर यहां भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कालेज और एक आई०टी०आई० अवश्य खोलें। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से बड़े बड़े गांव हैं जिनमें पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। पीछे सर्दी का मौसम था तो सर्दी के मौसम में उन गांवों के लोगों ने जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर लिया लेकिन अब आगे गर्मी आने वाली है इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के उन बड़े बड़े गांवों में पीने के पानी का प्रबंध अवश्य किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो जैसे मेरे क्षेत्र में होडल शहर 22 हजार की आबादी का है उसमें पीने के पानी की बहुत कमी है। उस शहर के लोग खारा पानी पीते हैं। वहां से जो भी आदमी विधायक बनता है वह लोगों को झूठ बहका देता है कि आपके लिए पीने के पानी का प्रबंध अवश्य किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी वहां के लोगों को कह दिया है और मैं सदन में भी यह वायदा कर रहा हूँ दलाल साहब आप मेरे वायदे की तरफ ध्यान दें। मैं वहां के लोगों से यह वायदा कर चुका हूँ कि अगर हम अपनी सरकार में होते हुए आपको पीने का पानी नहीं दे सके तो मैं विधायक बन कर आपके बीच में नहीं आऊंगा और न ही आपसे वोट मांगने आऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि होडल के अन्दर बेकारी की काफी समस्या है। वर्षों से वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। हमारा जिला वैसे तो अमीर है क्योंकि वहां से रैवेन्यू बहुत अधिक आता है। वहां पर कोई शिक्षा संस्था नहीं है जिससे हमारे बहन-भाईयों को पढ़ने में काफी दिक्कत आ रही है और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रह जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। हमारे जिले के जो छः विधायक हैं, यह उन सभी की मांग है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसे वहां पर अवश्य खोला जाये। मेरे हल्के में पानी की भी काफी समस्या है। वहां पर बड़ौली और दूसरे कई बड़े-बड़े गांव हैं जहां पर पीने के पानी की काफी समस्या है। पानी की कमी के कारण वहां के किसान और लोग परेशान रहते हैं। अतः मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे वहां पर पीने के पानी की समस्या की कोई न कोई व्यवस्था की जाये ताकि पानी की कमी न हो सके। अभी यहां पर हमारे विधायक साथियों ने रजबाहों की सफाई के बारे में कहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वहां पर सफाई का काम अच्छी तरह से हुआ है। पानी की पूरी मात्रा हमें मिल सके इसीलिए हम आगरा कैनाल का कन्ट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आये। इस काम को पिछली सरकार ने नहीं किया। इस प्रस्ताव पर अभी सदन में चर्चा चल रही है, जो अधूरी है। मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा को जल्दी से जल्दी खत्म करके उस प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार को भेजा जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के साथी कह रहे थे कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसान विरोधी सरकार नहीं है। यह किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसीलिए नहरों की सफाई की तरफ सरकार ने ध्यान देकर 40 लाख रुपये खर्च किए हैं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद।

अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प/1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा स्थगित करने के लिए प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have to make an announcement.

Hon'ble Members, I have received a No Confidence Motion/Resolution given notice of by Shri Bhajan Lal, M.L.A. and 28 other members of the Haryana Vidhan Sabha against me.

As a No Confidence Motion/Resolution has been received against me, so I consider it appropriate to refer it to the Hon'ble Deputy Speaker for taking a decision thereon and I shall bow my head before the decision of this august House.

(At this stage Hon'ble Deputy Speaker occupied the Chair)

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, I have received a motion from Shri Karan Singh Dalal that the discussion and voting on demands for grants on Budget Estimates for the year 1997-98 be postponed in favour of discussion on No Confidence Motion against the Speaker.

Now the Parliamentary Affairs Minister may move his motion.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move -

That the discussion and voting on demands for grants on the budget estimates for the year 1997-98 be postponed in favour of discussion on No Confidence Motion against the Speaker.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved -

That the discussion and voting on demands for grants on the budget estimates for the year 1997-98 be postponed in favour of discussion on No Confidence Motion against the Speaker.

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That the discussion and voting on demands for grants on the budget estimates for the year 1997-98 be postponed in favour of discussion on No Confidence Motion against the Speaker.

The motion was carried.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा ही संजीदा मामला सदन के सामने है। कांग्रेस के माननीय साथी चौधरी भजन लाल जी और उनकी पार्टी तथा समता पार्टी के साथियों ने इस महान सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय इस मामले को सदन के विचार के लिए छोड़ कर चेयर से उठ कर चले गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव आया है। हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर महोदय ने डिमाण्डज़ की डिस्कशन को बीच में छोड़ कर इस प्रस्ताव को रखा है जिसे डिस्कशन के लिए स्वीकार करते हुए स्पीकर साहब ने सदन के सामने रखा है। अभी डिमाण्डज़ पर चर्चा चल रही थी और उस पर वोटिंग होनी है लेकिन बीच में अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और आनरेबल स्पीकर साहब इस

[श्री राम बिलास शर्मा]

सदन के समक्ष चेयर उपाध्यक्ष महोदय को सौंप कर चले गये हैं। अब जो बात सदन के सामने है वह यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जानी है अथवा डिमाण्डज़ पहले पास करवानी हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग डिमाण्डज़ पर वोटिंग चाहते हैं तो करवा लें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : जो प्रस्ताव आया है हम उस पर भी वोटिंग चाहते हैं। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Deputy Speaker : As the motion was against the Hon'ble Speaker himself, he considered it appropriate to refer it to me for taking a decision thereon and, as such, I have examined the matter thoroughly keeping in view the constitutional and legal aspects thereof. Before annoucing the final decision I would refer to the following provisions of the Constitution of India :-

> "179 Vacation and Resignation of, removal from the office of the Speaker_____
>
> A Member holding office as Speaker_____ of any Assembly_____
>
> (c) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then Members of the Assembly :
>
> Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless atleast fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution_____"
>
> And rule that the notice is short of the period prescribed under the said provisions of the Constitution, which is mandatory and can not be suspended by the House. If there was any intention to give such a notice, these Hon'ble Members should have thought patiently and given the notice as prescribed under the Constitution. I would like to point out that both Article 179 (c) of the Constitution and Rule 11 of our Assembly Rules envisage for a resolution for the removal of the Speaker and not no-confidence motion against the Speaker. In the instant case, the Hon'ble Members have given a notice of no-confidence motion which is thus not in conformity with Article 179(c) of the Constitution and Rule 11 of our Assembly Rules. Further even such a resolution can not be moved/taken up unless there are specific charges which could be met. In addition, the perusal of the notice shows that they have made very sweeping and general remarks which are baseless and unwarranted against the high office of the Speaker. I must say that the notice does not fulfil the requirements of the Constitutional provisions and the Rules of our Assembly. Thus, prima-facie this notice deserves dismissal but I do not want to go in technicalilties as the motion is against the person occupying the august Office of the Speaker and because such matters ought to be thrashed out on the floor of the House, I, therefore, admit its notice."

Now , I request those members who are in favour of leave being granted to move this motion may please rise in their seats.

(At this stage only 20 members from the opposition rose in their seats.)

Mr. Deputy Speaker : The leave is not granted because there must be 23 members in favour of the leave.

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं खड़ा हुआ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके खड़े होने से क्या होता है। इसके लिए आपके 23 मैम्बर होना जरूरी है लेकिन आपके 20 मैम्बर ही हैं। इसलिए प्रस्ताव रिजैक्ट किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) जब आपको पूछा गया तो आपको बात समझ में आई नहीं अब आप बोल रहे हैं। अब आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Now, discussion on demands for grants will take place.

गृह मंत्री (मनी राम गोदारा) : उपाध्यक्ष महोदय अब ये बोल रहे हैं जब आपने कहा तब तो इनको कुछ पता नहीं चला। असल में इनको यह ही नहीं पता है कि इन्होंने क्या मोशन दी है।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो ये मोशन लेकर आए हैं इससे ज्यादा दुःखद बात कुछ नहीं हो सकती। इससे ज्यादा अन-प्रैसीडैंटिड बात कुछ नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान) जब इनको उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने को कहा तो उस वक्त ये खड़े नहीं हुए। अब ये बोलने के लिए खड़े हो गए हैं जब यह मोशन रिजैक्ट हो गया है। हम अपने स्पीकर साहब, का इस सदन में आने का अभिनन्दन करते हैं। संविधान की धारा 179 यह कहती है कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ नोटिस लाना हो तो कम से कम 14 दिन का नोटिस देना मैनडेटरी है। हम उस धारा को भी एक तरफ रखते हैं लेकिन इनके तो यहां पर 23 मैम्बर भी उपस्थित नहीं है। जैसे ही यह मोशन मिला हमारे अध्यक्ष सदन से चले गए। हम उनका सम्मान करते हैं। और अब स्पीकर साहब का इस सदन में स्वागत करते हैं (इस समय मेज थपथपाए गए।) ये जो अध्यक्ष महोदय, के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं यह कितनी गम्भीरता की बात है और ये सदन की गरिमा को कितनी गंभीरता से लेते हैं यह तो जाहिर हो ही गया है। यह इतना संगीन मसला है लेकिन इसमें इनको मालूम ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इनको यह मालूम ही नहीं कि चेयर के प्रति हम अविश्वास करने जा रहे हैं, इनको यह मालूम ही नहीं कि संविधान इसमें क्या कहता है, इनको मालूम ही नहीं कि इस प्रस्ताव पर इनको कहां खड़े होना चाहिए और इनको यह मालूम ही नहीं कि इसके लिए कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखदायी बात है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सबमिशन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब ने तो बहुत फिराखदिली दिखायी लेकिन इनको ही नोटिस देना नहीं आया। इनको नोटिस तो देना चाहिए था रिमूवल ऑफ दि स्पीकर का क्योंकि स्पीकर के खिलाफ नो कांफिडैन्स मोशन लाने का कोई प्रोविजन नहीं है केवल रिमूवल का ही प्रोविजन है। आपने तो फिराखदिली दिखायी कि नो कांफिडैन्स मोशन को रिमूवल के मोशन में बदल दिया लेकिन इसके बाद भी ये बैठे ही रहे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो इतनी भी फिराखदिली दिखायी कि पहले तो यह खड़े नहीं हुए लेकिन बाद में ये खड़े हुए परन्तु तब भी मैंने काउंटिंग करवायी।

श्री मनी राम गोदारा : इनके तो बहुत से पुराने मैम्बर्ज होंगे। इनके साथ जो रैजोल्यूशन लाने वाला आदमी है, वह यूं कहता है कि देश के अंदर मैं दो नम्बर का आदमी हूं। इस कांस्टीच्यूशनल मैटर

[श्री मनीराम गोदारा]

में बिजनैस ऑफ दि हाउस के मैटर में जिस आदमी को यही नहीं पता कि हाउस का प्रोसिजर क्या होता है तो वह क्या करेगा ? उसने तो इनके दस्तखत करवाकर ऐसे इनको दे दिया जैसे खांड के परमिट देते हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम किसी भी आदमी को अपनी बात कहने का समय तो देना ही चाहिए। राम बिलास जी ने जो बातें कही हैं उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हम सारे सदन की तरफ से स्पीकर साहब का अभिनन्दन करते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रेस दिखाया है। इस महान सदन में उन्होंने अपनी बहुत ही उदारता का परिचय दिया। प्रजातंत्र की परम्पराओं के अनुसार उन्होंने बहुत ही उदारता दिखायी। आप हमारी भावनाएं उन तक पहुंचा दें और इस प्रस्ताव को तुरन्त निरस्त करके हाउस की बाकी कार्यवाही चलाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, सारे कह रहे हैं कि हमें उन पर विश्वास नहीं है। (विघ्न)

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : उपाध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री उपाध्यक्ष : ये अब जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए। अब आप बैठें। यह टौपिक अब समाप्त हो चुका है। यदि अब कोई मैम्बर डिमांड पर बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है। (विघ्न)

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Deputy Speaker : Please sit down. Now the cut motions on the demands will be put to the vote of the House.

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.)

Mr. Speaker : I bow my head before the decision of this august House. Hon'ble Members, now enough discussion on demands has taken place.

Now the demands and cut motions will be put to the vote of the House.

Demand Nos. 1 & 2

Mr. Speaker : Question is -

That a sum not exceeding Rs. 3,37,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 64,90,66,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

Shri Jaswinder Singh Sandhu : Sir, . . .

Mr. Speaker : Please don't make this House a fish market. Please take your seat.

बैठक का समय बढ़ाना

Agriculture Minister : (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, the time of the sitting be extended for 15 minutes.

Mr. Speaker : It is sense of the House that the time of the sitting be extended for 15 minutes."

Voices : Yes ;

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by 15 minutes.

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जसविन्द्र सिंह जी और इनके साथी बार-बार कह रहे हैं जबकि इनके विधायक दल के मुख्य सचेतक ने उनको लिखकर दिया है कि हमने दो माननीय सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद भी उनके लिए व्हिप की बात कर रहे हैं। ऐसी बात थी तो आपको उनको निष्कासित नहीं करना चाहिए था, आपको उनको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए था। अब उनको व्हिप जारी करने के क्या मायने हैं।

Dr. Verender Pal Ahalawat : We want division on these demands.

Mr. Speaker : Alright, now I put the demand Nos. 1 & 2 for division.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker announced that 'Ayes' have it, whereupon division was claimed. Mr. speaker after calling upon those Members who were for 'Ayes' and those who were for 'Noes', respectively, to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was carried.

The motion was carried.

Demand No. 3

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 3 पर बोलते हुए चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बिजली बोर्ड के बारे में जो सुझाव दिए हैं वे बहुत अच्छे हैं। हम बैठकर भी बात कर लेंगे और जो काम की बात होगी उसको करेंगे क्योंकि बिजली के मामले में जो प्रदेश में कमी है उस कमी को दूर करने के लिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं। 400 मैगावाट का गैस बेस्ड प्लांट एन०टी०पी०सी० के थ्रू फरीदाबाद में लगा रहे हैं और 240 मैगावाट का प्लांट आई०ओ०सी० द्वारा पानीपत में लगा रहे हैं और पानीपत में जो छटी यूनिट पैसे की कमी की वजह से न तो चौटाला साहब की सरकार बना पाई और न ही चौधरी भजन लाल जी की सरकार बना सकी, उसको भी अब हम बना रहे हैं।(विघ्न)

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये क्योंकि मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला है (विघ्न) मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण लाल जी बैठिये, (विघ्न) मिस्टर पंवार आई वार्न यू।(विघ्न)

वाक आउट

आवाजें : स्पीकर साहब, अगर आप हमें कलैरिफिकेशन लेने के लिए भी अलाउ नहीं करते तो हम एज़ ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और समता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

वर्ष 1997-98 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक कलैरिफिकेशन है कि चौटाला साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि चालू साल में इस सरकार ने बिजली बोर्ड के लिए ज्यादा पैसा रखा है और अगले साल में कम रखा है और इस तरह किसानों की सबसिडी खत्म की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आता तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। परन्तु हकीकत यह है कि पिछले साल ट्यूबवैल्ज़ की सबसिडी के लिए 125 करोड़ रुपया रखा गया था जबकि अगले साल के बजट में 150 करोड़ रुपये रखा गया है जोकि 25 करोड़ रुपया बढ़ाकर रखा है। बजट के पैरा नं० 25 में साफ लिखा हुआ है कि 423.30 लाख रुपया हमने बुक एडजस्टमैंट किया है और इस साल बिजली बोर्ड से 1100 करोड़ रुपया लेना बाकी है। इस 1100 करोड़ रुपये की हम बुक एडजस्टमैंट कर सकते हैं। ये सदन को वैसे ही गुमराह कर रहे हैं अगर इस पैरे को पढ़ें तो साफ पता लग जायेगा।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 3 पर कैप्टन अजय सिंह जी ने जो कहा, इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इस बारे में मैं कलैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि आमतौर पर किडनैपिंग के केसों, मर्डर के केसों तथा रेप के केसों में बहुत सालों तक मुकद्दमें चलते हैं और उन मुकद्दमों में देर लगती है। इसलिए इस मामले में मुकद्दमें पैंडिंग हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि पुलिस के पास गाड़ियां नहीं हैं। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्री महोदय के हुक्म से 106 गाड़ियां पुलिस को अलॉट हुई हैं जो कि जल्दी ही पुलिस विभाग को मिल जाएंगी।

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 1 on demand No. 3 given by Sarvshri Birender Singh, Ajay Singh and Randeep Singh Surjewala to the vote of the House.

Question is -

That the demand be reduced by Rs. 2/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is -

"That a sum not exceeding Rs. 2,40,80,11,000 for revenue expenditure and Rs. 14,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under demand No. 3-Home

The motion was carried.

Demand No. 4

Mr. Speaker : Question is -

That a sum not exceeding Rs. 53,05,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

The motion was carried.

Demand No. 5

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 2 on demand No. 5 given by Sarvshri Ajay Singh, Randeep Singh Surjewala and Dharambir Gauba to the vote of the House.

Question is -

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is -

That a sum not exceeding Rs. 23,64,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No.-5 Excise and Taxation.

The motion was carried.

Demand Nos. 6 & 7

Mr. Speaker : Question is -

That a sum not exceeding Rs. 2,51,72,83,000 for revenue expenditure be granted to the governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 36,95,28,24,000 for revenue expenditure and Rs. 3,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect for charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

The motion was carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 3 on demand No. 8 given by Shri Dharambir Gauba to the vote of the House.

[Mr. Speaker]

Question is-

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is -

That a sum not exceeding Rs. 1,18,31,02,000 for revenue expenditure and Rs. 1,77,34,80,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 4 on demand No. 9 given by shri Ajay Singh to the vote of the House.

Question is —

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 7,41,06,39,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 5 on demand No. 10 given by sarvshri Ajay Singh, Jai Singh Rana and Randeep Singh Surjewala to the vote of the House.

Question is —

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 3,69,70,17,000 for revenue expenditure and Rs. 1,13,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 10—Medical and Public Health.

The motion was carried.

Demand No. 11

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 6 on Demand No. 11 given by S/Shri Birender Singh, Dharambir Gauba, Ajay Singh and Chander Mohan to vote of the House.

Question is —

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 37,70,68,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Development.

The motion was carried.

Demand No. 12

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 7 demand No. 12 given by Sarvshri Ajay Singh & Randeep Singh Surjewala to the vote of the House.

Question is —

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 35, 34,89 000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 12—Labour and Employment.

The motion was carried.

Demand No. 13

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 8 on demand No. 13 given by Sarvshri Ajay Singh and Randeep Singh Surjewala to the vote of the House.

Question is —

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 2,36,05,96,000 for revenue expenditure and Rs. 2,98,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.

The motion was carried.

Demand No. 14

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 12,64,31,000 for revenue expenditure and Rs. 5,06,13,36,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 9 on demand No. 15 given by Sarvshri Birender Singh, Ajay Singh, Randeep Singh Surjewala, Narender Singh and Jai Singh Rana to the vote of the House.

Question is —

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 5,91,84,00,000 for revenue expenditure and Rs. 2,93,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 10 on demand No. 16 given by Sarvshri Birender Singh, Dharambir Gauba and Ajay Singh to the vote of the House.

Question is —

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 33,53,92,000 for revenue expenditure and Rs. 13,11,35,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 16—Industries.

The motion was carried.

Demand No. 17

Mr. Speaker : Now I put the cut motion No. 11 on demand No. 17 given by Sarvshri Ajay Singh, Jai Singh Rana and Randeep Singh Surjewala to the vote of the House.

Question is —

That demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 1,97,59,12,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 17—Agriculture.

The motion was carried.

Demand No. 18 to 25

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs. 56,96,70,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 6,56,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 57,98,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 20—Forests.

That a sum not exceeding Rs. 80,81,28,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 16, 05,00,000 for revenue expenditure and Rs. 11,72,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 3,59,73,73,000 for revenue expenditure and Rs. 46,32,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor

[Mr. Speaker]

to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 30,27,000 for revenue expenditure and Rs. 4,03,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 3,72,34,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1997-98 in respect of charges under Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

*15.36 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 19th March, 1997.)

28783—H.V.S.—H.G.P., Chd.